शैक्षिक मंथन संस्थान

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः

ISSN 2581- 4133

वर्ष : 16 • अंक : 12 • पृष्ठ : 68 • जयपुर

www.shaikshikmanthan.com

आषाढ़, विक्रम संवत् 2081

1 जुलाई 2024 • ₹ 25/-

शैक्षिक मंथन

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

उन्नत भारत और समरस समाज

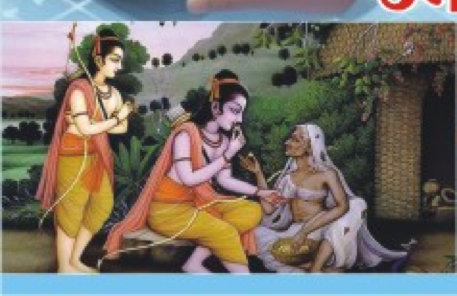

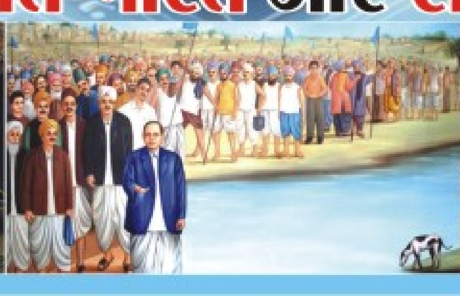

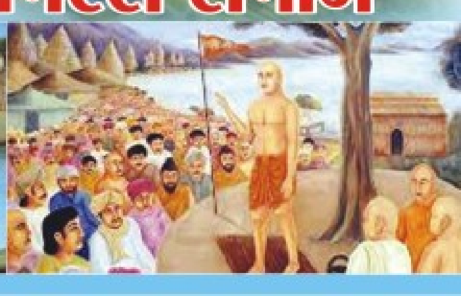

शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 16 अंक : 12 1 जुलाई 2024

आषाढ़, विक्रम संवत् 2081

परामर्श

डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल

जगदीश प्रसाद सिंघल

शिवानन्द सिन्दनकेरा

जी. लक्ष्मण

महेन्द्र कुमार

❖

सम्पादक

प्रो. शिवशरण कौशिक

❖

संपादक मंडल

प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय

प्रो. राजेश कुमार जांगिड़

प्रो. ओमप्रकाश पारीक

डॉ. एस.पी. सिंह

भरत शर्मा

❖

प्रबन्ध सम्पादक

महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक

बसंत जिंदल

❖

प्रेषण प्रभारी : **नौरंग सहाय 'भारतीय'**

प्रकाशकीय कार्यालय
82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर (राजस्थान) 302001
दूरभाष : 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :
शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,
कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली - 110053

E-mail :
shaikshikmanthan@gmail.com
Visit us at :
www.shaikshikmanthan.com

वार्षिक शुल्क ₹ 250/-
दस वर्षीय शुल्क ₹ 2000/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा चित्रों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है।

भारत की उन्नति का वर्तमान परिदृश्य ❑ डॉ. धीरज शर्मा

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की उन्नति के बहुआयामी मानकों पर नजर डालें तो भारत संचार-परिवहन, खेल, ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जैसे अनगिनत क्षेत्रों में प्रगतिशील हैं तथा कुशल मानव संसाधन का बेहतर प्रबंधन किया जाए तो भारत विकसित देशों की श्रेणी में सिरमोर हो सकता है। वर्तमान में भारत वैश्विक नेतृत्व के दौर से गुजर रहा है जो विकसित भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए एक आधार का काम कर सकती हैं।

4

अनुक्रम

3. संपादकीय - प्रो. शिवशरण कौशिक
9. उन्नत भारत एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति : पारस्परिक ... - प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल
15. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समरस समाज - प्रो. प्रवीन कुमार मिश्र
17. उन्नत भारत और महिला शक्ति - डॉ. सुमन बाला
21. उन्नत भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 - श्रद्धा मिश्रा
23. धारणक्षम विकास और समरस भारत - प्रो. शिवशरण कौशिक
26. वर्तमान उन्नत भारत का वैश्विक शांति में योगदान - डॉ. अमित सिंह
31. उन्नत भारत और समरस समाज - प्रो. संतोष कुमार प्रजापति
34. भारतीय वाङ्मय में सामाजिक समरसता - सत्येश भट्ट
36. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियाँ ... - डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता
41. भारतीय ज्ञान परम्परा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति - डॉ. चेतना उपाध्याय
44. परिवर्तन की प्रतीक्षा में पाठ्यक्रम - प्रणय कुमार
47. प्रकृति केन्द्रित विकास की अवधारणा - डॉ. विजय वशिष्ठ
57. National Education Policy 2020 ... - Dr. Anil Kumar Biswas
60. Harmonizing Education and ... - Prof. P.C. Agarwal
64. The New and Emerging Bharat - Prof. TS Girish Kumar
66. तुम फिर से दिल पर राज करो... - विनीत चौहान
67. हमारा विद्यालय - हमारा तीर्थ - देवकृष्ण व्यास

Shoodras, the Ancient Producers under Varna Vyavastha and Caste Equanimity

❑ Prof. Bhagwati Prakash

When the Indian or Hindu Philosophy asserts that the same divine Almighty is pervading across all living beings, how an individual can be untouchable or superior or inferior on the basis of his birth. Why this evil practice should have any place in our social life? All Bhartiya or the Indians the descendents of the ancient Hindu polity Hindus should behave and act as a seamless cohesive caste like true brethren and sistren. Besides, we should also revive the decentralised production of goods and services for inclusive growth, sustainable development and full employment.

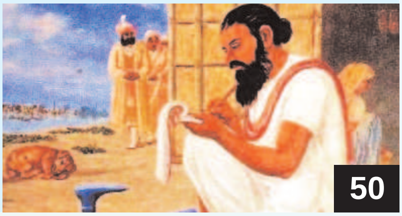

50

संपादकीय

प्रो. शिवशरण कौशिक
संपादक

अन्यान्य प्रसंगों से यह कथा प्रचलित है कि किसी प्रतिष्ठित शासक ने अपने दरबारियों से प्रश्न किया कि 'भारत में किस नदी का जल सर्वश्रेष्ठ है?' समस्त सभासदों की एक ही राय थी कि 'गंगा का जल सर्वश्रेष्ठ है।' जब उसमें उनके महागुणी मन्त्री से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया – 'यमुना का जल'। यह उत्तर सुनकर सभा में उपस्थित सभी विस्मित भी थे और प्रश्नाकुल भी। राजा ने जब उनसे आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा कि 'गंगा का जल क्यों नहीं?' तो उनका उत्तर था कि 'राजन्, गंगा का जल जल नहीं, वह तो अमृत है'। गंगा के प्रति हिन्दू समाज में ही अतिरिक्त श्रद्धा का भाव हो, ऐसा नहीं है। एक उर्दू के शायर ने गंगा के प्रति अपना सम्मान भाव प्रकट करते हुए लिखा है –

''दुनिया का कोई दरिया
सानी नहीं है तेरा,
आबे हयात है यह
पानी नहीं है तेरा।''

आबे हयात का भी मूल अभिप्राय अमृत या अमृत-जल ही होता है जिसका आशय उस जल से है जिसे पीने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। भारत का हिन्दू समाज गंगाजल से पवित्र और गंगा से पावन संभवतया और किसी जल या नदी को नहीं मानता। हिन्दुओं के लिए गंगा केवल नदी नहीं, माता है, जीवन दायिनी माता, नित्य पूजनीय माता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पुरस्कर्त्री माता। गंगा का जल हाथ में लेकर ली गई शपथ को भारत में अपरिहार्य व्रत माना गया है। जीवनान्त में हुई मुक्ति को गंगागति ही कहा गया है।

भारत में जब भी गंगा की पवित्रता की बात होती है तो सभी नदियों की पवित्रता और शुद्धि की बात की जाती है, मानव जाति को बचाने की बात होती है। गंगा जहाँ एक ओर गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा में अनेक नगरों-कस्बों-गाँवों की जीवनधारा है, वहीं कहीं-न-कहीं नगरीकरण, उद्योगीकरण, आधुनिकीकरण या मशीनीकरण के कारण उत्पन्न अनेक कारणों से उत्पन्न प्रदूषण-संकट से भी जूझ रही है। यह स्थिति सभी नदियों के साथ समान है। भारतीय दृष्टिकोण के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि असीमित आधुनिक विकास की अवधारणा तथा प्रकृतिपूजक भारतीय विचार में बहुधा परस्पर विरोध ही दिखाई देता है। इसीलिए आज गंगा का दूषित जल हाथ में लेकर गंगा की स्वच्छता की शपथ लेने जैसी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई है। मनुष्य के समस्त पापों को धोने वाली गंगा अपने उजले आँचल के लिए अपनी सन्तानों की ओर मुँह बाये खड़ी है। और गंगा ही क्यों, भारत की अधिकांश नदियाँ उनके किनारे बसे छोटे-बड़े नगरों-कारखानों, उद्योगों से निकलकर उनमें मिलने वाले उपशिष्टों से त्रस्त हैं। इनमें बसने वाले नागरिकों-मालिकों को इनके प्रति संवेदनशील होना होगा, सजग होना होगा। अन्यथा ये नदियाँ खतरे में नहीं, बल्कि जीवन खतरे में है।

सरकारी स्तर पर विगत 3-4 दशकों में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, समाज चिन्तकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा नदियों के प्रदूषण को लेकर गहरी चिन्ता प्रकट की है और स्वच्छता अभियान की कुछ बृहत् परियोजनाएँ भी सामने आई हैं। इसका यह परिणाम हुआ कि अब सामान्यतया 'गंगा बचाओ' या 'नदी बचाओ' अभियानों की बात होती है तो उनके प्रवाह की बात भले ही न हो, परन्तु उनकी निर्मलता पर अवश्य चर्चा होती है।

भारत सरकार का 'नमामि गंगे' अभियान भी इसी क्रम में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है। जिसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिन्धु, कावेरी आदि नदियों की आराधना के श्लोक – ''गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती

नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम् कुरु।'' को 'भारत के नदी उत्सव' अभियान का आह्वान गीत बनाया है। जिससे विद्यार्थियों, सामान्य नागरिकों में नदियों के प्रति आस्था भाव जाग्रत हो, उनकी निर्मलता तथा उनके जल के सम्यक उपयोग का बोध हो, यही इसका अभिप्राय है।

गंगा नदी के पुनर्जीवन के लिए केवल उसकी निर्मलता पर ध्यान करना पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए एक व्यापक दृष्टि तथा उचित नीतियों की आवश्यकता है। सबसे पहले उसका जल स्तर बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। इसलिए इसमें से नहरों इत्यादि में निकाले जाने वाले पानी में कमी की जानी चाहिए। गंगा से जल निकाला जाता है उसमें 75-80 प्रतिशत तो सिंचाई के लिए उपयोग में आता है। अगर उस मात्रा को कम करना है तो धान और गेहूँ के स्थान पर किसानों को मोटे अनाज (श्री अन्न) पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। श्री अन्न वैसे भी चावल और गेहूँ से अधिक पौष्टिक होते हैं। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व मोटा अनाज ही खाने के अधिक उपयोग में आता था। मोटे अनाजों की फसलें सूखे की मार भी तुलनात्मक रूप से अधिक सह लेती हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि देशभर की नदियों को स्वच्छ तथा निरन्तर प्रवहमान बनाने के लिए सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं की भूमिका तो प्रमुख है ही, किन्तु सर्वाधिक महत्त्व जनसाधारण का है जो उनके जल का भोक्ता भी है और संरक्षक भी। ❑

सम्माननीय सदस्यगण !

शैक्षिक मंथन के जिन सदस्यों की दस वर्षीय सदस्यता पूर्ण हो चुकी है, वे नियमित अंक प्राप्ति हेतु कृपया शीघ्र ही नवीनीकरण करवाने का अनुग्रह करें।

भारत की उन्नति का वर्तमान परिदृश्य

डॉ. धीरज शर्मा
इतिहास विभागाध्यक्ष,
राजकीय महाविद्यालय,
सुमेरपुर (राज.)

भारत की उन्नति के विभिन्न आयामों में वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो यह परंपरा ऋषि मुनियों की समृद्ध संस्कृति में मानव-कल्याण से प्रेरित है और इसका संबंध वर्तमान जनतांत्रिक व्यवस्था में जनकल्याणकारी कार्यों से कर सकते हैं जहाँ धर्म और कर्म दोनों सनातन संस्कृति को पोषित करते हुए उन्नत, विकसित और समृद्ध भारत के स्वप्न को साकार कर रहे हैं। पुरातनकाल में भारतीय उन्नति के प्रतीक के रूप में देखा जाए तो दर्शन में कपिल मुनि, कणाद और चार्वाक ने पाश्चात्य दार्शनिकों से अपना लोहा मनवाया है, तथा साहित्य में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, दंडी, भवभूति और भारवि ने अपनी काव्य विद्वत्ता से यूरोपीय कवियों को भी अनुवाद के लिए सहसा ही अपनी ओर खींच लिया गया। परिणामस्वरूप अनेक ग्रंथों के अनुवाद लेटिन और आंग्ल भाषा में किए गए। यद्यपि भारत कला, साहित्य और दर्शन में ही अग्रणी नहीं था बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में ग्रहों की गति के नियम, सूर्य व चंद्र ग्रहण की परिकल्पना, रसायन के क्षेत्र में धात्विक परिष्करण (मैहरोली का लौह स्तम्भ रसायन विज्ञान की उन्नति का उत्कृष्ट उदाहरण है) और उनसे संबंधित औषधि निर्माण तथा आयुर्वेद में चरक, वाग्भट्ट व पतंजलि का योगदान तथा शल्यक्रिया में सुश्रुत, खगोलशास्त्र में वराहमिहिर, भास्कराचार्य, गणित में आर्यभट्ट की शून्य की खोज, पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि आज का बौद्धिक भारत प्राचीनकाल से ही अनवरत प्रगतिशील रहा है। वर्तमान विश्व व्यवस्था में उन्नति का द्योतक तकनीकी विकास और वैज्ञानिक अनुसंधानों को माना जाता है। साथ ही भारत की एक अनूठी संस्कृति है और यह दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक है। इसके साथ ही यह अपने-आप को बदलते समय के साथ ढ़ालती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारतीय संस्कृति समस्त मानव जाति का कल्याण चाहती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन गौरवशाली मान्यताओं एवं परंपराओं के साथ ही नवीनता का समावेश भी दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं का महासंगम है, जिसमें सनातन संस्कृति से लेकर आदिवासी, तिब्बत, मंगोल, द्रविड़, हड़प्पाई और यूरोपीय धाराएँ समाहित हैं। ये धाराएँ भारतीय संस्कृति को इंद्रधनुषीय संस्कृति या समरस संस्कृति में परिवर्तित करती है।

भारत की सांस्कृतिक उन्नति

भारत का इतिहास और संस्कृति गतिशील है और यह मानव सभ्यता की शुरूआत तक जाती है। यह सिंधु घाटी की रहस्यमयी संस्कृति से शुरू होती है

और भारत के दक्षिणी इलाकों में किसान समुदाय तक जाती है। भारत के इतिहास में भारत के आस-पास स्थित अनेक संस्कृतियों से लोगों का निरंतर समेकन होता रहा है।

विश्व की अनेक सभ्यताओं एवं संस्कृति ने अपना मूल रूप खो दिया है लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति अनेक झंझावतों को झेलते हुए अनवरत प्रगतिशील है।

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर और चीन की संस्कृतियों के समान ही प्राचीन है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने-आप को बदलते समय के अनुसार ढालती भी आई है।

भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को छूने वाले प्रत्येक पक्ष का समन्वय देखने को मिलता है इसी एकता में अनेकता और विविधता के कारण आज भारतीय संस्कृति अपनी उन्नति के पथ पर अग्रसर है। भारतीय संस्कृति में 'अध्यात्म एवं भौतिकता' में समन्वय नजर आता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीनकाल में मनुष्य के चार पुरूषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं चार आश्रमों- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख है, जो आध्यात्मिकता एवं भौतिक पक्ष में समन्वय लाने का प्रयास है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संस्कृति ने अनेक जाति - समुदाय और धर्म के श्रेष्ठ विचारों/आदर्शों को अपने में समेट लिया है। भारतीय संस्कृति में यहाँ के मूल निवासियों के समन्वय की प्रक्रिया के साथ ही बाहर से आने वाले शक, हूण, यूनानी एवं कुषाण भी यहाँ की संस्कृति में घुल-मिल गए हैं। अरबों, तुर्कों और मुगलों के माध्यम से यहाँ इस्लामी संस्कृति का आगमन हुआ। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति ने अपना पृथक् अस्तित्व बनाए रखा और नवागत संस्कृतियों की अच्छी बातों को उदारतापूर्वक ग्रहण किया।

वसुधैव कुटुंबकम् बनाम भारतीय सांस्कृतिक उन्नति

भारत की सनातन संस्कृति परम्परा का दायरा केवल राष्ट्र की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि सनातन संस्कृति में मानव-कल्याण और 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना निहित है जो विश्व समुदाय को एक कुटुम्ब के रूप में देखती है इन विचारधारा को पुष्ट करने में गीता का निष्काम कर्म भाव, जैन समुदाय के 'अहिंसा परमो धर्म', बौद्ध दर्शन के अहिंसा और लोकसंग्रह की अवधारणा का योगदान शामिल हैं।

'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत बखूबी निभा रहा है जैसे- एक तरफ मानव प्रायोजित कोरोना महामारी ने मानव जीवन को संकट की स्थिति में ला खड़ा कर दिया वहीं दूसरी तरफ भारत ने वसुधैव कुटुंबकम् परंपरा को कायम रखते हुए वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए विश्व समुदाय को अपनी वेक्सीन उपलब्ध करवाई और भारतीय संस्कृति को मानव-कल्याण के लिए उपयोगी साबित किया।

> **वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की उन्नति के बहुआयामी मानकों पर नजर डालें तो भारत संचार-परिवहन, खेल, ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जैसे अनगिनत क्षेत्रों में प्रगतिशील हैं तथा कुशल मानव संसाधन का बेहतर प्रबंधन किया जाए तो भारत विकसित देशों की श्रेणी में सिरमोर हो सकता है। वर्तमान में भारत वैश्विक नेतृत्व के दौर से गुजर रहा है जो विकसित भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए एक आधार का काम कर सकती हैं।**

भारतीय संस्कृति के बारे में पं. मदनमोहन मालवीय का कहना है कि ''भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशालता और उसकी महत्ता तो संपूर्ण मानव के साथ तादात्म्य स्थापित करने अर्थात् 'वसुधैव कुटुंबकम्' की पवित्र भावना में निहित है।''

भारत में सामाजिक उत्थान बनाम परंपराओं का संरक्षण

सामाजिक उत्थान से पहले हम समाज की उत्पत्ति पर नजर डालें तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है समाज रीति-रिवाजों, प्रक्रियाओं, अधिकारों और पारस्परिक सहायता, कई समूहों के नियंत्रण और स्वतंत्रता और उनके मानव व्यवहार के उप-विभाजनों की एक प्रणाली है। प्राणियों में मानव समाज विवेकशील हैं फिर भी मानव समाज ने भिन्न-भिन्न समयांतरालों में अनेक सामाजिक द्वंद्वों का सामना किया है जैसे - जातीय वैमनस्य, धार्मिक उन्माद, लिंग-भेद, वर्णभेद तथा वर्गभेद। समाज में फैली इन मानवजनित विकृतियों से उभरकर भारत ने मधुर सामाजिक संबंधों को कायम रखा है।

कालातीत सामाजिक विकृतियों को जन्म देने में विदेशी आक्रांताओं का हाथ रहा है इससे पहले भारत के वैभव की छाप वैश्विक पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित थी।

आक्रांताओं के परिणामस्वरूप भारत का सामाजिक ताना-बाना कलुषित हुआ यथा - सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा। इन कुप्रथाओं ने एक सभ्य समाज पर दाग का काम किया था लेकिन कुछ

हद तक समाज सुधारकों और सरकारी प्रयासों (संवैधानिक प्रावधानों, अधिनियमों, कल्याणकारी योजनाओं) ने समाज के इस दुष्चक्र के पहियों पर विराम लगा दिया।

सामाजिक उत्थान रूपी इमारत शिक्षा रूपी ईंट पर टिकी हुई है। भारतीय संस्कृति का हस्तांतरण शिक्षा के आधार पर ही होता आया है लेकिन भारतीय इतिहास में कुछ ऐसा कालक्रम रहा जहाँ स्त्री शिक्षा पर विराम लगा फिर भी स्त्रियों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक) में अपना लोहा मनवाया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है तो वहीं अनुच्छेद 15 लिंग और नस्ल के भेदभाव को नकारता है तथा अनुच्छेद 16 सभी को रोजगार पाने के समान अवसर प्रदान करता है। इन सामाजिक उत्थानों में सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण कदम अस्पृश्यता निवारण है जिसका आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद-17 है। वर्गभेद ने जातीय भेदभाव का रूप ले लिया था जो सामाजिक समानता के आधारभूत सिद्धांतों का खंडन करता है। इसके निराकरण के लिए सरकार ने अनेक नियामकीय प्रयास किए हैं तथा शैक्षिक उन्नयन से सामाजिक सामंजस्य की नींव सुदृढ़ हो रही है। विश्व पटल पर भारत की उन्नति में मध्यमवर्ग का अहम् रोल रहा है। इन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में - खेल जगत में, संस्कृति उत्थान में, परम्पराओं के हस्तांतरण में, शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास में, वैज्ञानिक व तकनीकी नवाचारों में, तथा सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दिया है। इस प्रकार सामाजिक उन्नति के बहुआयामी प्रयासों में भारत काफी हद तक सफल भी हुआ है लेकिन यह उन्नति केवल सामाजिक ढाँचे पर ही निर्भर नहीं करती है बल्कि यह सार्वभौमिक रूप से विविधता में निहित है।

विकसित भारत की संकल्पना बनाम वैश्विक चुनौतियाँ

21वीं सदी भारत की सदी होगी यह उद्घोष मात्र नहीं है इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार अनवरत प्रयासरत है। साथ ही जनसांख्यिकी लाभांश भी भारत की उन्नति के अनुकूल है और सदी के इस अवसर का फायदा उठाने के लिए भारत की कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या का है जो कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता को दर्शाता है। इन सभी अनुकूल परिस्थितियों के कारण भारत स्वतंत्रता के 100वें वर्ष, यानी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए प्रयासरत है। देश की तीव्र प्रगति को देखते हुए इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार कर सकना संभव नजर आता है। यह क्षण इच्छित विकास की अवधारणा का मूल्यांकन करने का भी अवसर प्रदान करता है। विकास प्राथमिकताओं और फोकस क्षेत्र का चयन जटिल और महत्त्वपूर्ण दोनों है।

'विकसित भारत' के तहत आर्थिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। आर्थिक विकास के आधार पर ही विकास के अन्य सभी क्षेत्र टिके हुए हैं।

विजन इंडिया 2047 के तहत् आगामी 25 वर्षों में भारत के विकास का खाका तैयार करने के लिये भारत के शीर्ष नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। परियोजना का लक्ष्य भारत को नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी देश, मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण का मॉडल और पर्यावरणीय संवहनीयता का चैंपियन या उत्साही पक्ष-समर्थक बनाना है।

विकसित भारत के विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी देशों में शुमार होंगे - संरचनात्मक रूपांतरण, श्रम बाजारों का निर्माण, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना जिससे उत्पादकता में गुणवत्ता, नवाचार और टिकाऊपन होगा, वित्तीय और सामाजिक समावेशन में सुधार करना, प्रशासनिक उत्कृष्टता को प्राप्त करना (जवाबदेही, भागीदारी, पारदर्शिता और विधिसम्मत शासन), नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और जलवायु प्रत्यास्थता जैसी हरित प्रौद्योगिकियों और अभ्यासों को अपनाना, रोजगार सृजन करना, जीवन प्रत्याशा को बेहतर बनाना, बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, गुणवत्तापूर्ण और कौशलपरक शिक्षा पद्धति को अपनाना, मानवश्रम संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, सतत् एवं धारणीय विकास को प्राथमिकता देना। केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित वर्तमान मॉडल हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यधिक विघटनकारी हो सकता है। इसके लिए हमें विश्व समुदाय के बहुआयामी मानकों पर खरा उतरना होगा जहाँ - मानव कल्याण और खुशहाली को प्राथमिकता देना होगा तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी सूचकांकों में सुधार करते हुए शीर्षस्थ राष्ट्रों में अपने आपको खड़ा करना (वैश्विक नवाचार सूचकांक, विधि का शासन सूचकांक, निर्धनता सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, लैंगिक समानता सूचकांक और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, मानव अधिकार सूचकांक)।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था

विश्व जीडीपी रैंकिंग 2024 के अनुसार, की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वर्तमान भारत सरकार और इकोनॉमी के मजबूत आधारस्तम्भ कर्मयोगी प्रयासरत हैं।

वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2023 में बढ़कर 7.59 प्रतिशत हो गई और 2029 तक बढ़कर 9.23

प्रतिशत होने का अनुमान है। वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की विकास दर 2 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी पाँच वर्षों में 16 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी लगातार सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल रही है जो अप्रैल 2024 तक, 648.562 बिलियन है, जो विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। वर्तमान में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का योगदान क्रमश: इस प्रकार है – 53 प्रतिशत, 31 प्रतिशत और 16 प्रतिशत। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक भागीदार देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे विकसित देश शामिल हैं। सर्वाधिक भुगतान संतुलन की स्थिति अमेरिका के साथ है तो प्रतिकूल स्थिति चीन के साथ हैं। भारत के एफडीआई में वर्तमान में सर्वाधिक निवेशकर्ता देशों में सिंगापुर और मॉरिशस का योगदान हैं। इस तरह विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भारत रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है।

वर्तमान परिदृश्य में भारत की उन्नत प्रौद्योगिकी और संचार प्रणाली

वर्तमान के भारत ने संचार नेटवर्किंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और एआई टेक्नोलॉजी में अपनी पहचान बनाई है। आजादी के बाद भारत तकनीकी रूप से इतना विकसित नहीं था लेकिन प्रबुद्ध वैज्ञानिकों तथा सरकारी प्रयासों ने 1958 में डीआरडीओ तथा 1969 में इसरो की स्थापना से इस क्षेत्र में जो कदम रखा वो आज उन्नत रक्षा प्रोद्योगिकी प्रणाली तक पहुँच पाया है। वर्तमान परिदृश्य में भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग को अगले 5 वर्षों में 300–USD 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के राजस्व स्तर को छूने की उम्मीद है। भारत आईटी उत्पादों का शीर्ष निर्यातक है, इसका फार्मा क्षेत्र तीसरा सबसे बड़ा है तथा अनुबंध अनुसंधान क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में प्रौद्योगिकी लेनदेन के लिए सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में भारत तीसरे स्थान पर है। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने के साथ, इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में निवेश में वृद्धि देखी गई है।

भारत वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर शीर्ष देशों में से एक है, तथा अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में शीर्ष पाँच देशों में से एक है। देश ने नियमित रूप से अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें चंद्रमा पर जाने वाले मिशन (चंद्रयान-3), सूर्य मिशन-आदित्य एल-1 और प्रसिद्ध ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) शामिल हैं। भारत सार्क देशों के लिए उपग्रहों को लॉन्च करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, तथा अन्य देशों को उपयोग के लिए अपनी अंतरिक्ष सुविधाओं की पेशकश करके राजस्व अर्जित कर सकता है। वर्तमान में भारत 170 परमाणु बम के साथ आणविक क्षेत्र में शीर्षस्थ देशों में शामिल हैं। मेक इन इंडिया को मूर्त रूप देते हुए भारत रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है जो एक बड़ी उपलब्धि है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी भारत ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है हाल ही में न्यूज चैनल आजतक में एआई एंकर एमा, डीडी कृषि चैनल में एआई एंकर कृष और भूमि का लांच किया गया है।।

वर्तमान में भारत की जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्थिति को देखा जाए तो कोरोना काल में भारत ने को – वैक्सीन, कोविशील्ड को विश्व समुदाय को उपलब्ध करवाकर बायोटेक्नोलॉजी में

अपनी पहचान रख दी। बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान, संकर नस्ल और संकर फसल किस्म, में नये-नये आविष्कार किए हैं तथा जैव पेटेंट तक हासिल किए हैं।

नेनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो वर्तमान भारत की स्थिति सुदृढ़ है जो कार्बन नेनो ट्यूब, नेनो बायोसेंसर, आप्टिकल फाइबर, नेनो मोटरकार के रूप में देखने को मिलती है। भारत की उन्नति के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के रूप में अच्छी स्थिति है।

वर्तमान भारत में प्रगतिशील खेल जगत

खेल का मानव जीवन में इसलिए महत्त्व है कि यह शारीरिक विकास के साथ-साथ सर्वांगीण विकास के अन्य पहलुओं को भी छूता है जो बौद्धिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य के रूप में देखने को मिलता है। भारत में पुरातन काल से ही खेल की समृद्ध परंपरा रही है और खेल ग्राम्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है लेकिन कालचक्र के परिवर्तन ने खेलजगत में भी आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है और नये-नये खेलों का आविर्भाव हुआ है जो खेल जगत में हमें देखने को मिलते हैं। वर्तमान खेल परिदृश्य में भारत की उन्नति का परिचय कराएँ तो विभिन्न आयु वर्गों में महिला-पुरुष, ट्रांसजेंडर्स, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ने खेल जगत में भारत का गौरव बढ़ाया है। वैश्विक पटल पर खेलजगत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता ओलंपिक खेलों में भी भारत का ग्राफ बढ़ रहा है जो रियो ओलंपिक 2016 में भारत को इन खेलों में कुल दो पदक मिले। साक्षी मलिक ने महिलाओं की 58 किलोग्राम फ्रीस्टाईल कुश्ती में कांस्य पदक जीता और पी.वी. सिंधु ने बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया लेकिन टोकियो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में 48 वां स्थान प्राप्त किया था जो सुखद अहसास दिलाता है। वहीं एशियन गेम्स में 107 पदकों (28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य) की अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ भारत ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझू में 2023 के एशियाई खेलों में एक नया मानदंड स्थापित किया है परिणामस्वरूप पदक तालिका में चौथे स्थान पर जगह बनाई है। वर्तमान में खेल क्षेत्र में बढ़ती उन्नति के लिए सरकार प्रतिबद्ध हैं तथा खेलों के विकास के लिए 3397.32 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया जो खेलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ और उन्नति की ओर अग्रसर भारत

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो अपने देश के नागरिकों के अधिकारों व हितों को संरक्षण दें तथा लोक कल्याणकारी कार्य करें। वर्तमान परिदृश्य में भारतीय लोकतंत्र जन भावनाओं पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंशतः कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है जिसमें आतंकवाद, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टचार, लालफीताशाही, भाई-भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी आदि मुख्य हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समय-समय पर सरकारी प्रयास किए गए हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की उन्नति के बहुआयामी मानकों पर नजर डालें तो भारत वैश्विक नेतृत्व के दौर से गुजर रहा है जो विकसित भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए एक आधार का काम कर सकती है। प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति के लिए समय की एक पराकाष्ठा होती है जिसे कुशल नेतृत्व वाली सरकार भुना सकती है और यह समय जनसांख्यिकी लाभांश, कुशल प्रशासक, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भारत के अनुकूल है साथ ही हम राष्ट्र के कुशल नेतृत्व से उम्मीद करते हैं कि विकसित भारत के मनोरथ को साकार रूप देंगे। ❑

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य अधिक शिक्षित, कुशल और नवोन्वेषी आबादी का निर्माण करना है, जिससे भारत के विकास को गति मिले और इसे ज्ञान अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया जा सके। इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उन्नत भारत के लिए अपना योगदान दे रहा है। चूकि उन्नत भारत की अवधारणा में प्रगति और कल्याण के कई आयाम शामिल हैं जो सामूहिक रूप से देश के समग्र विकास में योगदान करते हैं।

उन्नत भारत एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति : पारस्परिक सम्बन्ध की समझ

प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल

कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बिलासपुर (छ.ग.)

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा तथा विकास में एक अत्यंत घनिष्ठ अन्तर्निहित सम्बन्ध होता है या दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों वस्तुत: एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम यह भी जानते हैं कि शिक्षा और विकास के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के सिद्धांत बहुत प्रभावित करते हैं। शिक्षा को प्रभावित करने में विभिन्न दर्शन, सामाजिक पहलुओं, इतिहास के कालक्रम, मनोवैज्ञानिक आयामों, आर्थिक आधारों, राजनैतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ, भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक परम्पराएँ, भाषाई विविधताएँ, धार्मिक एवं राष्ट्र की भावनाएँ आदि के समावेशित कारक कार्य करते हैं और दूसरी तरफ विकास के लिए भी मूलत: यही कारक कार्य करते हैं इसीलिए विकास भी इन कारकों को अपने से अलग नहीं कर पाती है। यहाँ पर हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विकास और उन्नत शब्दों के क्या पर्याय हैं? और शिक्षा के सम्बन्ध में उन्नत शब्द का प्रयोग अधिक उचित है या विकास शब्द का प्रयोग। विकास और उन्नत शब्द में अंतर बहुत बारीक है किन्तु उनके अर्थ बहुत ही स्पष्ट हैं, अपने आप में हम समझ सकते हैं कि उन्नत वृद्धि का पर्यायवाची है और इन दोनों का प्रयोग समय और परिस्थिति दोनों के अनुकूल उपयोग होता है। उन्नत और वृद्धि किसी एक पक्ष या पहलू के सन्दर्भ के लिए होता है दूसरी तरफ विकास में सभी पक्ष या पहलू समाहित रहते हैं इसीलिए कभी कभी सर्वांगीण शब्द को भी विकास के साथ जोड़ दिया जाता है। कह सकते हैं कि विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, तकनीकी, कौशल, व्यापार, वाणिज्य, नीतियाँ आदि समावेशित रूप से जुड़े रहते हैं और इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर हम जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राष्ट्र के सन्दर्भ में देखते हैं तब शिक्षा विकास के एक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आती है इसलिए उन्नत शब्द यहाँ अधिक समीचीन लगता है यद्यपि शिक्षा के अंदर भी कई पक्ष हैं और उस दृष्टि से यहाँ भी विकास शब्द का उपयोग किया जाता है। निष्कर्षत: यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राष्ट्र के संदर्भ में देखने के कारण उन्नत शब्द का ही उपयोग सही होगा।

उन्नत भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पृष्ठभौमिक संरचना

भारत को उन्नत करने में शिक्षा की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत में शिक्षा हमेशा समय के साथ, समय की माँग के अनुसार परिवर्तित होती रहती है जिसके लिए समय-समय पर आयोग, समितियाँ और नीतियाँ बनायी जाती रही किन्तु अब तक जितने भी आयोग एवं समितियाँ बनी थी वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकीं जिसके कारण शिक्षा भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकी। 2020 में प्रस्तुत की गई भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) शिक्षा की एक व्यापक रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना है। इस शिक्षा नीति में सभी के लिए, सभी स्तर पर समावेशी, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करके, साथ ही आजीवन सीखने

के अवसरों को बढ़ावा देकर भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने की कल्पना की गयी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूरे शिक्षा की संरचना को बदल दिया गया है और इसे समग्रता के साथ देखा जा रहा है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पहले शिक्षा की संरचना कुछ इस प्रकार की थी –

शिक्षा स्तर	कक्षा	व्यावसायिक कोर्स एवं प्रशिक्षण	शिक्षा संरचना
शोध	शोध	शोध	
परा स्नातक	एमए./एम.एस सी./एम.कॉम	एम.ई/एम.टेक/मेडिकल पी. जी.	2
स्नातक	बीए/बी.एससी./बी.कॉम	बी.ई./बी.टेक/ एम.बी.बी.एस.	+3
उच माध्यमिक	11 से 12	पालीटेकनिक	+2
माध्यमिक	9 से 10	आई. टी. आई./नर्सिंग	10
उच्च प्राथमिक	6 से 8		
प्राथमिक	1 से 5		
नर्सरी	किंडरगार्टन/मोंटेसरी/आगनबाडी		

किन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उपरोक्त शिक्षा संरचना में परिवर्तन कर दिया गया है जो अब इस प्रकार से है –

शिक्षा स्तर	कक्षा	व्यावसायिक कोर्स एवं प्रशिक्षण	शिक्षा संरचना
शोध	शोध	शोध	
परा स्नातक	एमए./एम.एस सी./एम.कॉम	एम.ई/एम.टेक/मेडिकल पी. जी.	1
स्नातक	बीए/बी.एससी./बी.कॉम	बी.ई./बी.टेक/ एम.बी.बी.एस.	+4
माध्यमिक	9 से 12	पालीटेकनिक/आई.टी.आई./नर्सिंग	
		स्किल प्रशिक्षण/	+4
मिडिल	6 से 8		+3
प्राथमिक	3 से 5		+3
तैयारी स्तर	किंडरगार्टन/मोंटेसरी/आगनबाडी से कक्षा 2 तक		5

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उपरोक्त शिक्षा की संरचना में न केवल बाह्य संरचना में परिवर्तन आया है बल्कि आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा को उसकी संरचना और प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है तब उस सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सही मायने में शिक्षा के द्वारा परिवर्तित संरचना और प्रक्रिया के माध्यम से भारत के उन्नत और विकास के साथ संरक्षित करता है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उन्नत भारत के लक्ष्य के साथ कैसे संरेखित है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने आप में सम्पूर्णता लिए हुए है, जिसमें तैयारी स्तर की शिक्षा से लेकर शोध तक का व्यापक स्तर समाहित है और यह न केवल सामान्य या सैद्धांतिक शिक्षा तक सीमित है बल्कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से भारत की मूलभूत ज्ञान की शिक्षा के साथ ही साथ आधुनिक वैश्विक ज्ञान, तकनीकी और कौशल की शिक्षा को भी समन्वय करता है, जिससे एक कौशल युक्त, तकनीकी फ्रेंडली और भारतीय ज्ञान से युक्त विद्यार्थी भारतीय होने के गर्व के साथ अपने ज्ञान की शिक्षा के माध्यम से समाज एवं देश की सेवा के साथ ही साथ वसुधैव कुटुम्बकम् का उद्देश्य भी पूरा करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रत्येक स्तर की शिक्षा की कुछ विशेषताएँ सामने आती हैं जिसे समझने की आवश्यकता है और ये समझ हमें उन्नत भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के कारकों के योगदान की भी समझ उत्पन्न करेगा।

1. प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार इस स्तर पर 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई तक सार्वभौमिक पहुँच हो और बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक शिक्षा के साथ ईसीसीई का एकीकरण हो जिससे बच्चों की शिक्षा आगे बढ़ती जाएगी और किसी भी प्रकार का व्यवधान नही आएगा। यहाँ पर तैयारी स्तर (प्रिपरेटरी स्टेज) में नर्सरी के साथ बालवाटिका आँगनवाडी को भी सम्मलित किया गया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह पर देखने को मिलता है कि आँगनवाडी की कार्यकर्ताओं को भी अब तैयारी स्तर (प्रिपरेटरी स्टेज) की शिक्षक शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित होने का अवसर मिलेगा।

2. प्राथमिक स्तर एवं बहुभाषिकता – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ग्रेड

5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा पर जोर देते हुए स्कूलों में बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाये और इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एन.सी.इ.आर.टी. के भारत के स्थानीय भाषा के साथ-साथ मातृभाषा में विषयवस्तु तैयार करे और प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा इसको स्थानीय स्तर पर लागू किया जाये जिससे बच्चों में अपने मातृभाषा/स्थानीय भाषा के माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त होंगे।

3. मिडिल स्तर – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ग्रेड 6 से 8 तक की शिक्षा में भाषा, गणित, विज्ञान स्थानीय इतिहास, खेलकूद, संस्कृति आदि से परिचित कराने की शुरुआत होगी जिससे अगले स्तर पर विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक स्तर पर, भावात्मक स्तर पर एवं मनोगत्यात्मक स्तर पर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी।

4. माध्यमिक स्तर – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्तर में कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा होगी लेकिन इस स्तर की शिक्षा में व्यापक आमूल चूल परिवर्तन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय भारत में कुल 57 माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड हैं जिसमें केंद्र सरकार के सी.बी.एस.ई. एवं एन.आई ओ.एस. हैं। एक आई.सी.एस.ई. बोर्ड है जो ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित है इसके आलावा वनस्थली बोर्ड जो एक निजी संस्था का बोर्ड है तथा शेष सभी राज्य सरकारों की है। अभी तक इन सभी बोर्डों द्वारा कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित की जा रही हैं जिसके कारण हमारी शिक्षा परीक्षा उन्मुख रही है। इस व्यवस्था में विद्यार्थी बहुत ही तनाव की स्थिति से गुजरते हैं क्योंकि उनके परीक्षा परिणामों को व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामजिक और आर्थिक स्तरों से जोड़ कर देखा जा रहा है। इन स्थितियों से बचने के लिए कई बार भारत के प्रधानमंत्री को भी विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करनी पड़ रही है। इधर दूसरी तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए विद्यार्थियों को बहुत सहूलियत प्रदान करते हुए कक्षा 9 से12 के बीच केवल एक बार बोर्ड परीक्षा देने की वकालत की है अर्थात् विद्यार्थी जब अपने को बोर्ड के लिए तैयार पाए तब बोर्ड की परीक्षा दे इसके साथ ही साथ माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को किसी एक समूह से ही सब्जेक्ट की चुनने की बाध्यता नहीं है वह अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय को चुन सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। हम कह सकते हैं कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा अब परीक्षा उन्मुखी न होकर विद्यार्थी केन्द्रित हो रही है।

5. कौशल विकास शिक्षा – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आई.टी.आई., पालीटेकनिक, नर्सिंग एवं एनी व्यावसायिक विषयों या ब्रांचों में विद्यार्थियों को कौशल युक्त करने के लिए नये-नये प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने और पुराने प्रशिक्षण केन्द्रों को अपग्रेड करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और इनसे विद्यार्थियों को स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलती है।

6. उच्च शिक्षा – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्तर में अब स्नातक 4 वर्ष का हो गया है परा स्नातक एक वर्ष का एवं शोध के लिए दो मार्ग खुल गये हैं जिसमें एक 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम पूरा करने के पश्चात सीधे शोध में प्रवेश हो सकेगा और दूसरी तरफ परा स्नातक के बाद भी शोध में प्रवेश ले सकेगा।

इस स्तर पर विद्यार्थियों को उनके समय को बचाने के लिए उन्हें एक साथ दो डिग्री लेने की छूट प्रदान की गयी है कि वे एक संस्था के अलावा किसी अन्य संस्था से भी डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इस स्तर पर भी विषयों के समूहों को ओपन कर दिया गया है विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन कर सकता है।

7. शिक्षक शिक्षा – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा पर बहुत बल दिया जा रहा है इसका कारण यह है कि अभी तक शिक्षक शिक्षा केवल शिक्षक बनने के लिए एक अनिवार्य डिग्री रही है इसके अलावा विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों से इसका सम्बन्ध न के बराबर रहा है। लेकिन अब शिक्षक शिक्षा में बहुत व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। शिक्षक शिक्षा को अब 4 वर्षीय होने के साथ-साथ 4 अलग-अलग स्तरों के लिए विशिष्ट बनाया जा रहा है। इसको आई.टी.इ.पी. का नाम दिया गया है इसके

4 स्तरों के नाम इस प्रकार है – प्रथम आई.टी.इ.पी. (प्रिपरेटरी), द्वितीय – आई.टी.इ.पी. (प्राइमरी), तृतीय – आई.टी.इ.पी. (मिडिल) और चतुर्थ – आई.टी.इ.पी. (सेकेंडरी)। इसमें विद्यार्थी कक्षा 12 के पश्चात सीधे प्रवेश ले सकता है। यद्यपि 4 वर्षीय शिक्षक शिक्षा के साथ 2 वर्षीय एवं 1 वर्षीय शिक्षक शिक्षा भी 4 अलग–अलग स्तरों के साथ चलती रहेगी। 2 वर्षीय शिक्षक शिक्षा में विद्यार्थी 3 वर्ष के स्नातक के पश्चात् जबकि 1 वर्षीय शिक्षक शिक्षा में 1 वर्ष के परा स्नातक के बाद प्रवेश ले सकेगा।

8. मेडिकल एव इंजीनिरिंग शिक्षा – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल एव इंजीनिरिंग शिक्षा में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब मेडिकल एवं इंजीनिरिंग शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में देने की वकालत हो रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय परम्परागत चिकित्सा एव इंजीनिरिंग की शिक्षा देने के लिए कई प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। उपर्युक्त वर्णन में हमने देखा कि किस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा संरचनागत परिवर्तन किये गये हैं अब हम उसके कुछ मूलभूत प्रक्रियात्मक परिवर्तनों को देखने का प्रयास करेंगे –

1. पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक, समग्र एकीकृत और मनोरंजक बनाने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र को नया स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, वैज्ञानिक स्वभाव और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया गया है इस हेतु पाठ्यक्रमों में व्यापक बदलाव लाया जा रहा है। उच्च शिक्षा में कला, विज्ञान और व्यावसायिक धाराओं के बीच कठोर अलगाव को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) का निर्माण। बहु–विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना।

2. मूल्यांकन सुधार – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के अधिक व्यापक मूल्यांकन को बढ़ावा देते हुए योगात्मक से रचनात्मक मूल्यांकन को अनिवार्य बनाये जाने की कदम उठाये गये हैं और यह बदलाव नियमित और योग्यता–आधारित मूल्यांकन की शुरूआत कर रही है। प्रत्येक स्तर के शिक्षा के लिए मानदंडो में व्यापक बदलाव लाना और उसे क्रियान्वयन करना शुरू हो चुका है। शिक्षकों के कौशल और दक्षता में सुधार के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

3. प्रौद्योगिकी का उपयोग – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का एकीकरण एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग पर निर्णय लेने की सुविधा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (एनईटीएफ) की स्थापना की गयी है। यह प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों दोनों के लिए मदद करने वाला है।

4. इक्विटी और समावेशन – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है इसके साथ ही महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए लिंग समावेशन निधि। कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियाँ और प्रोत्साहन दी जा रही है अर्थात् इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा समाज के सभी वर्गों के शिक्षा और उनकी उन्नति के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों को निम्न सारिणी द्वारा आसानी से समझ सकते हैं –

संरचनागत परिवर्तन		प्रक्रियागत परिवर्तन
मेडिकल एव इंजीनिरिंग शिक्षा		उच्च शिक्षा में भारतीय भाषा
शिक्षक शिक्षा		अलग अलग स्तरों के लिए शिक्षक शिक्षा
उच्च शिक्षा	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020**	विषय की समूह वर्ग की समाप्ति
कौशल विकास शिक्षा		इक्विटी और समावेशन
माध्यमिक स्तर		प्रौद्योगिकी का उपयोग
मिडिल स्तर		मूल्यांकन सुधार
प्राथमिक स्तर एव बहुभाषिकता		शिक्षणशास्त्र
प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई)		पाठ्यचर्या

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा – उपर्युक्त वर्णन से हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास है। यह नीति तीन दशकों के बाद आई है और इसे आधुनिक शिक्षा विचारधारा के साथ संगत बनाने का प्रयास किया गया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रणाली को व्यापक रूप में सुधारा गया है और जिसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएँ और प्रक्रियाएँ शामिल की

गयी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है भारत में एक एकीकृत शिक्षा प्रणाली को बनाए रखना, जिसमें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा एक साथ शामिल होंगी। यह समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसमें नवाचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और अन्य नवाचारिक क्षेत्रों में रुचि और कौशल विकसित करने का मौका मिले। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, भारत में भाषा शिक्षा को महत्त्व दिया जाएगा, ताकि छात्र अपनी मातृभाषा में भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता के मानकों को बढ़ावा देने के लिए, इस नीति में गुणवत्ता को नामांकन के लिए विभिन्न प्रमाणपत्रों का प्रयोग करने का प्रावधान है। यह नीति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक विकास करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान और कौशल प्राप्त हों। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है समृद्ध गुरुकुल प्रणाली को प्रोत्साहित करना, जो वैदिक और अद्वितीय शिक्षा प्रणाली को पुनर्पहचान दिलाये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उन्नत भारत में योगदान

जैसा कि हम जानते हैं कि उन्नत भारत अभियान भारत सरकार का एक अमूल्य संकल्प है जो देश को विभिन्न क्षेत्रों में विकास की ऊँचाइयों तक पहुँचाने का उद्देश्य रखता है। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था और यह एक व्यापक राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम है जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्नत भारत की अवधारणा सितंबर, 2014 में आईआईटी दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान ग्रामीण विकास कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल कई तकनीकी संस्थानों, ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्रवाई समूह (आरयूटीएजी) समन्वयकों, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से विकसित किया गया था। इस कार्यशाला में ग्रामीण प्रोन्नत भारत अभियान और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों ही जो कि भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं, को देश के विकास और उन्नति के लिए एक दूसरे को सहयोग करने के साथ कार्य प्रणाली तैयार करने की बात की गयी थी। हम यह भी जानते हैं कि भारत एक विशाल और विविधता वाला देश है जिसमें अनेक सांस्कृतिक, भाषाई, और सामाजिक परंपराएँ आपस में मिलती हैं। उन्नत भारत अभियान और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन पहलुओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन पहलुओं का मुख्य उद्देश्य देश की ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, आदि के क्षेत्रों में सुधार करना है, ताकि भारत एक उन्नत और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े।

उन्नत भारत अभियान के मुख्य उद्देश्य

1. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी मुद्दों की पहचान करने तथा उनके लिए स्थायी समाधान खोजने में उच्च शिक्षा संस्थानों के संकाय और छात्रों को शामिल करना।

2. लोगों की आवश्यकता के अनुसार, विद्यमान नवीन प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उनका चयन करना, प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को सक्षम बनाना, या नवीन समाधानों के लिए कार्यान्वयन विधियों को विकसित करना।

3. उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रणालियाँ तैयार करने में योगदान देने की अनुमति देना।

उन्नत भारत अभियान के कुछ मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं –

1. **स्वच्छ भारत अभियान** – इसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाना है, जिसमें सार्वजनिक स्वच्छता, शौचालय सुधार, जल संरक्षण और वातावरण संरक्षण शामिल हैं।

2. **स्वस्थ भारत अभियान** – यह अभियान भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण, बीमारियों के प्रतिनियंत्रण और जनसंख्या के नियंत्रण शामिल हैं।

3. **ऊर्जा संरक्षण और विकास** – इसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करना और उन्नत ऊर्जा प्रणालियों को प्रोत्साहित करना है।

4. **ऊर्जा स्वायत्तता** – यह लक्ष्य उच्च स्तरीय ऊर्जा स्वायत्तता की स्थापना करना है, जिससे भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वतंत्रता से पूरा कर सके।

5. **डिजिटल भारत अभियान** – इसका लक्ष्य भारत को डिजिटल बनाना है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट सुविधाएँ, ई-गवर्नेंस, और डिजिटल प्रवासी सेवाएँ शामिल हैं।

6. **संवैधानिक व्यवस्था और न्यायपूर्ण भारत** – इसका उद्देश्य भारत को एक संवैधानिक और न्यायपूर्ण समाज के रूप में स्थापित करना है, जिसमें न्यायिक सुधार, पुलिस सुधार, और संवैधानिक सुधार शामिल हैं।

7. **गाँव विकास योजना** – इसका उद्देश्य भारत के गाँवों को विकसित करना है, जिसमें ग्रामीण आर्थिक विकास, कृषि विकास और ग्रामीण अधिकारों की सुरक्षा शामिल हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उन्नत भारत पर प्रभाव – हमारा मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उन्नत भारत के अभियान के विभिन्न कारकों पर अपना प्रभाव डालेगा।

1. मानव पूंजी विकास – उन्नत भारत के अभियान के एक कारक के रूप में मानव पूँजी का विकास आता है और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक मजबूत फोकस एक अधिक कुशल और सक्षम कार्यबल तैयार करेगा। इस नीति में आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल पर जोर देने से रोजगार क्षमता और नवाचार में वृद्धि होगी।

2. आर्थिक विकास – उन्नत भारत के अभियान के दूसरे कारक के रूप में आर्थिक विकास आता है और यहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़कर, एनईपी का लक्ष्य कौशल अंतर को कम करना और आर्थिक उत्पादकता में सुधार करना है जिससे व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता को प्रोत्साहन से रोजगार सृजन और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

3. सामाजिक विकास – उन्नत भारत अभियान के तीसरे कारक के रूप में सामजिक विकास आता है और यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने से सामाजिक-आर्थिक विभाजन दूर होगा और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं में शिक्षा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेगी और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देगी।

4. तकनीकी उन्नति – उन्नत भारत के अभियान के चौथे कारक के रूप में तकनीकी उन्नति आती है और यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र डिजिटल साक्षरता में अच्छी तरह से पारंगत हों, जो उन्हें प्रौद्योगिकी-संचालित भविष्य के लिए तैयार करेगा। एनईपी द्वारा प्रोत्साहित अनुसंधान और नवाचार वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में योगदान देंगे।

5. वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता – उन्नत भारत के अभियान के पाँचवे कारक के रूप में तकनीकी उन्नति आता है और यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके, एनईपी का लक्ष्य भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाना, अंतरराष्ट्रीय छात्रों और सहयोग को आकर्षित करना है। एक मजबूत उच्च शिक्षा प्रणाली अकादमिक और अनुसंधान क्षेत्रों में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाएगी।

इस उपर्युक्त वर्णन में हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य अधिक शिक्षित, कुशल और नवोन्वेषी आबादी का निर्माण करना है, जिससे भारत के विकास को गति मिले और इसे ज्ञान अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया जा सके। इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उन्नत भारत के लिए अपना योगदान दे रहा है। चूंकि उन्नत भारत की अवधारणा में प्रगति और कल्याण के कई आयाम शामिल हैं जो सामूहिक रूप से देश के समग्र विकास में योगदान करते हैं। इन आयामों में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता, तकनीकी उन्नति, टिकाऊ पर्यावरणीय प्रथाएँ, मजबूत बुनियादी ढाँचा और सभी नागरिकों के लिए उच्च जीवन स्तर शामिल हैं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा मदद मिलेगी। ❑

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करनी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरुरत है। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में सामनता, समावेशन और सामाजिक-आर्थिक रूप से गतिशीलता हाशिल की जा सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समरस समाज

प्रो. प्रवीन कुमार मिश्र
प्राध्यापक, इतिहास विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि असली भारत ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है और उनका विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कई वर्षों के परिश्रम के बाद आखरिकार शिक्षा क्षेत्र में बदलाव और सामाजिक न्याय एवं समरस समाज निर्माण का दस्तावेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हमारे सामने है। इस नीति के निर्माण की समिति में ही समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी और उनकी अपेक्षा एवं भावों को इसमें सम्मिलित किया गया है। वैसे तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(A), में सभी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन अब भी इस मूलाधिकर से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वंचित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी कई समस्याओं को दूर करने और भारत के करोड़ों बच्चों के सपने को पूरा करने और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने का एक सराहनीय प्रयास का नाम है। इतना ही नहीं, शिक्षा के साथ बच्चों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे. इसके लिए मध्यावधि भोजन में फल, दूध एवं अन्य भोज्य पदार्थों का सम्मिलन वो भी प्रांत एवं मौसम अनुसार हो, इसे भी सुनिश्चित किया गया है। शरीर-बुद्धि के मध्य संयोग बना सशक्त भारत निर्माण करना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभीष्ट है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुछ शिक्षाविदों की एक समिति ने ही नहीं बनाया है, बल्कि इसे बनाने में सम्पूर्ण राष्ट्र ने अपनी सहभागिता को दर्ज किया है। एक पंचायत से लेकर बड़े शिक्षा संस्थान एवं तमाम सामाजिक संगठनों आदि ने भी इसमें अपने सुझाव दिए थे। ये शिक्षा नीति उन्हीं सबको आधार मानकर बनी है, इसीलिए इसका विरोध भी हमें ज़्यादा नहीं दिखता है। इस शिक्षा नीति ने देश के शिक्षाविदों की वर्षों की उस मांग को भी पूर्ण किया है जिसमें वे सकल घरेलू आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो, की बात कर रहे थे। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा। ये नामांतरण केवल नाम में बदलाव मात्र नहीं, बल्कि पूरी दृष्टि का बदलाव है, जिसमें हम मानव को शिक्षा देने का उदेश्य केवल और केवल रोजगार देना नहीं, अपितु शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के स्वत्व, चित्त का जागरण करना और उसे सभ्य समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना भी है। यही तो भारत की पुरातन शिक्षा पद्धति का भी ध्येय था, इसलिए नामांतरण करना भी एक सकारात्मक प्रयास है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब छठी क्लास के बाद ही व्यावसायिक एजुकेशन की भी शुरुआत होगी और 12वीं क्लास तक हर बच्चा व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकेगा। ये व्यावसायिक शिक्षा जहाँ भारत में रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा, वहीं शिक्षा में अन्वेक्षण को भी बढ़ावा देगा। अगर हम स्कूली शिक्षा के बारे में बात करें तो फिर अब पुराने ढाँचा 12+2 को हटाकर एक नया स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। इसमें 5+3+3+4 का रहेगा। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 12वीं कक्षा के बाद से 'मल्टीपल एंट्री एग्जिट' की व्यवस्था की है। इसका अर्थ है कि 12वीं के बाद कोई 1 साल तक पढ़ता है तो उसे 'सर्टिफिकेट' दिया जाएगा। इसी तरह 2 साल तक 'डिप्लोमा'

व तीसरे वर्ष 'डिग्री' और चार साल में उसे 'ऑनर्स' माना जाएगा। विद्यार्थियों के लिए परास्नातक (एम. ए.) केवल 1 वर्ष की ही होगी। इसका उद्देश्य किसी भी छात्र का वर्ष खराब ना हो जितना उसने छोड़ दिया है। किसी कारण से उसे वहीं से फिर शुरू कर सके ऐसी व्यवस्था सरकार ने बनाई है जिसका लाभ ज़्यादातर दलित, पिछड़े समाज, गरीब एवं महिलाओं को ही होगा। इसके अलावा स्नातक में कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है उदाहरण के तौर पर राजनीति विज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति भी संगीत सीख सकता है।

इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी (हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया) बनाने की बात की गई है। साथ ही उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 प्रतिशत एनरोलमेंट अनुपात बढ़ाना है, जो अभी 26.3 प्रतिशत है। वहीं 3.30 करोड़ सीट बढ़ाने का लक्ष्य भी लिया गया है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने और सामाजिक न्याय को पाने का अच्छा कार्य है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान छात्रवृति हेतु 'राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल' को अधिक सक्रिय करने की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, दिव्यांग, महिलाओं आदि को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कुछ अच्छे बिंदु हैं जो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस वर्ग को एसईडीजी यानि की 'सामाजिक आर्थिक उपेक्षित वर्ग' के रूप में चिन्हित किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, ट्रान्सजेंडर एवं सभी छात्राएँ इन सभी के बीच किस प्रकार से शिक्षा पहुँचे, इस पर बारीकी से अध्ययन किया गया है। शिक्षा नीति का दस्तावेज मानता है कि सामाजिक जड़ता, प्रथाएँ एवं गरीबी, इस वर्ग के छात्रों को शिक्षा से दूर ले जाता है। विद्यालयों का दूर होना भी छात्राओं के लिए अपनी आगे की शिक्षा को जारी रखने में बड़ी बाधा बनती है, इसलिए इस शिक्षा नीति में 'लैंगिक समावेशन फंड' बनाने की बात की गई है। इस पैसे को खासकर छात्राओं, जिसमें ट्रान्सजेंडर को भी सम्मिलित किया गया है। इन सभी को अपने विद्यालय तक पहुँचने के लिए साइकिल देना, इनके लिए अलग से साफ, स्वच्छ शौचालय निर्माण एवं पढ़ाई हेतु अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने पर खर्च किया जाएगा। वहीं ग्रामीण भारत में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का ज़्यादा निर्माण करना साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालयों की लंबी चेन देशभर में खड़ी करना, जिससे अच्छी शिक्षा के साथ छात्रों के समग्र विकास हेतु अच्छा भोजन और परिस्थिति दी जा सके, वहीं सामाजिक समरसता के भारत भाव को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हर जिले में एक उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण करना जो भारत में सामाजिक न्याय एवं सभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचे इस ध्येय को पूर्ण करेगा।

उन्नत भारत अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और समावेशी भारत की वास्तुकला के निर्माण में मदद करने के लिए ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी बदलाव के दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस मिशन की अवधारणा एक आंदोलन के रूप में की गई है, जो गोद लिए गए गाँवों में उपलब्ध मानव और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सतत विकास में तेजी लाने के लिए भागीदारी प्रक्रियाओं और उपयुक्त प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्रामीण भारत की विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ने वाली प्रक्रियाओं को सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य उभरते व्यवसायों के लिए ज्ञान और अभ्यास प्रदान करके समाज और समावेशी विश्वविद्यालय प्रणाली के बीच एक अच्छा चक्र बनाना और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की क्षमताओं को उन्नत करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत की परंपरागत शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन भारत की भाषाओं के विकास और संवर्धन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें अब पाली, पर्शियन और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान खोले जाएँगे और भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक, साहित्यिक विकास के लिए भी संस्थान खोले जाएंगे और परंपरागत साहित्य विज्ञान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में करिकुलम सिलेबस तैयार किया जाएगा, इससे प्राचीन भारत की गौरवशाली परम्परा और ज्ञान को संवारने का कार्य होगा। दलित समाज के छात्र उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होने के चलते बीच में ही पढ़ाई छोड़ (ड्रॉपआऊट) देते थे ये उनके लिए भी सहायक सिद्ध होगा, साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शिता की बात की गई। ये भी समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों आदि की शिक्षा संस्थानों में स्थान को सुनिश्चित करेगी, इसलिए आज जो भी कुछ विरोध सामाजिक न्याय के नाम पर हो रहा है, वो मात्र दिखावा है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी का विकास, समग्र विकास से सामाजिक समता निर्माण ऐसी दिशा देने का कार्य किया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करनी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरुरत है। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में सामनता, समावेशन और सामाजिक-आर्थिक रूप से गतिशीलता हाशिल की जा सकती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानि चाहिए जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सके। ❑

उन्नत भारत और महिला शक्ति

डॉ. सुमन बाला

सह आचार्य
हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षक महाविद्यालय, हटूँडी, अजमेर (राज.)

भारत प्राचीन काल से एक विकसित संस्कृति, संपन्न परंपराओं और उच्च मानवीय मूल्यों का देश रहा है। राष्ट्र की इस समृद्धि में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक कालखंड में भारतीय महिलाओं ने अपने ज्ञान, विवेक, समर्पण और परिश्रम से अपनी छाप छोड़ी है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिला शक्ति के योगदान को अनदेखा किया जा सके। राष्ट्र के समग्र विकास और उसके निर्माण में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान का दायरा असीमित है। महिलाओं ने देश के चहुमुखी विकास और समाज की उन्नति में अपनी भागीदारी को सशक्त ढंग से पूर्ण किया और पुरुषों से आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। संकीर्णता, भेदभाव और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भी देश को नई ऊंचाइयों पर पहुँचने में अपनी भूमिका बखूबी निभाई है जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बढ़-चढ़कर भाग लेना।

किसी भी राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुँचने के लिए उसकी सामाजिक व्यवस्था का संतुलित होना प्राथमिक आवश्यकता है। सामाजिक व्यवस्था के संतुलन के लिए उस समाज में पारिवारिक खुशहाली जरूरी है। परिवार और घर की धुरी महिला ही होती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ''नारी ही परिवार और समाज की केंद्र बिंदु है।'' महिला का सबसे बड़ा और अहम योगदान घर और परिवार को संभालने में हमेशा रहा है। अधिकांश महिलाएँ घर एवं परिवार के इस दायित्व का निर्वाह कुशलतापूर्वक करती रही हैं। घर एवं परिवार को संभालने के लिए जिस कुशलता और क्षमता की आवश्यकता होती है उसका पुरुषों में सामान्यत: अभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कहा जाता है कि एक लखपति पिता बालक को नहीं पाल सकता परंतु एक भिखारिन माँ भी बालक को अच्छी तरह पाल सकती है। इसलिए राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान घर और बच्चों को संभालने एवं उनको संस्कारित करने का दायित्व है जिसे वे सदियों से बड़ी कुशलता से करती आ रही हैं। महिलाओं के परिवार, समाज को राष्ट्र के निर्माण में इस योगदान को नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान में भी महिलाएँ घर-परिवार के दायित्वों के साथ-साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की अग्रदूत बनकर राष्ट्र उन्नति में अपना योगदान प्रत्येक क्षेत्र में दे रही हैं।

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसकी आधी आबादी की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यदि कोई भी राष्ट्र अपनी इस आधी शक्ति की भूमिका को किसी भी रूप में नजरअंदाज करता है अथवा इस शक्ति का सम्मान नहीं करता है तो उस राष्ट्र के समुचित विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो यह सच्चाई हमारे सामने आती है कि जिस समय महिला शक्ति का सम्मान हुआ उस कालखंड में राष्ट्र ने उन्नति की ऊंचाइयों को छुआ है और जिस कालखंड में महिलाओं के योगदान को सम्मान न देकर नकार दिया गया उस कालखंड में राष्ट्र की अवनति को कोई नहीं रोक पाया है। प्राचीन काल में भारत विश्व

गुरु के पद पर आसीन था और बाकी विश्व इससे काफी पीछे था। उस काल में भारतीय समाज में नारी का सम्मान था और उसका स्तर काफी ऊंचा था। उस काल में महिलाएँ स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करती थी, उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी और वह आध्यात्मिक रूप से धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने के साथ-साथ राजनीतिक क्रियाएँ संपन्न करवाने की भी अधिकारिणी थी। महिलाएँ उस काल में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों के साथ-साथ युद्ध लड़ने जैसे कठिन कार्यों को भी करती थी। इतिहास में हमें कुछ उदाहरण ऐसे भी दिखाते हैं जो महिलाओं की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को इंगित करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में विदेह के राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने अन्य ऋषिगण शास्त्रार्थ में जब परास्त हो जाते हैं तो गार्गी उनसे शास्त्रार्थ कर उन्हें परास्त करती है।

किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को समझने का सबसे आसान तरीका है उसमें महिलाओं की स्थिति को समझ लिया जाए। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, ''मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से आँकता हूँ।'' महिलाओं की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध एवं मजबूत समाज की द्योतक है। आज भी किसी देश के विकास संबंधी सूचकांक को निर्धारित करने हेतु उद्योग, व्यापार, खाद्यान्न उपलब्धता, शिक्षा स्तर के साथ महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। महिला शक्ति राष्ट्र शक्ति का अभिन्न अंग होती है जिसको सशक्त और शामिल किए बिना राष्ट्र उन्नति संभव नहीं हो सकती। इतिहास के विभिन्न कालखंड को देखते हैं तो पाते हैं कि जिस काल में भारत अपनी सुदृढ़ सांस्कृतिक विरासत और मानवीय मूल्यों में अग्रणी रहा उस काल में महिलाओं का भी समाज में उच्च स्थान रहा। आदिकाल में समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी जिसने परिवार को सुदृढ़ स्थिति प्रदान की। वैदिक काल में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान था। ऋग्वेद की ऋचाओं में महिलाएँ वेद शिक्षित, युद्ध कला में निपुण और ऋचाओं की रचनाओं में लगभग 30 महिला ऋषियों के नाम का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में वर्णन मिलता है कि ''नववधू तू जिस घर में जा रही है वहाँ की साम्राज्ञी है'' (अथर्ववेद 14/14)। वेदों के बाद सर्वाधिक मान्यता स्मृतियों की है और स्मृतियों में भी मनुस्मृति ग्रंथ की है। मनुस्मृति को उस काल की सामाजिक आचार व्यवहार संबंधी नियमावली अथवा नैतिक मूल्य संहिता माना जाता था। मनुस्मृति में महिलाओं के सम्मान में कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है और जहाँ उनका आदर नहीं होता है वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। बौद्ध काल में भी महिलाओं के सम्मान और किसी प्रकार के लिंग भेद न होने का वर्णन मिलता है। इस काल में महिलाओं का संघ में प्रवेश था और वह ऊंचे आध्यात्मिक पहुँच से शिक्षिका के पद पर भी आसीन होती थी। धर्मशास्त्र काल में लगभग 788 ईस्वी में शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के ज्ञानी माने गए हैं और उन दिनों शास्त्रार्थ परंपरा थी। ऐतिहासिक विवरण में शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र के पराजित होने पर उनकी पत्नी भारती द्वारा शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित करने का वर्णन मिलता है। मौर्य काल और गुप्त काल में भी उच्च वर्ग की महिलाओं के शिक्षित होने, समारोह में हिस्सा लेने और अंगरक्षकों के रूप में कार्य करने का वर्णन मिलता है। इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने में आती है जो मध्यकाल में अपने चरम पर पहुँच जाती है। लगभग सातवीं शताब्दी के अंत में मुसलमान शासकों के प्रभुत्व में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने समाज में जगह बना ली और महिलाओं की स्थिति में अत्यंत गिरावट आई। यह काल राष्ट्र की अवनति और गुलामी का काल रहा।

आधुनिक काल में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करना (अनुच्छेद 15), अवसरों की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39घ) आदि जैसे अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं। विभिन्न कालखंड में हम देखते हैं कि जिस काल में महिलाओं का स्थान जिस प्रकार का रहा उस कालखंड में भारत अपने सांस्कृतिक विरासत और मानवीय मूल्यों में भी उसी के अनुरूप रहा है। भारतीय समाज में नारी की विभिन्न कालों की स्थिति को देखकर हम आत्म निरीक्षण कर सकते हैं कि जिस काल में देश की महिलाओं का समाज में उच्च और सम्मानित स्थान रहा उस कालखंड में भारत सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र रहा है। वैदिक काल के

दौरान महिलाओं की स्थिति राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों में अच्छी थी, महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान था तब भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत और मानवीय मूल्यों में अग्रणी रहा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ''हम प्राचीन भारत की नारियों को आदर्श मानकर ही नारी का उत्थान और सशक्तीकरण कर सकते हैं।''

मध्यकाल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में आई गिरावट के सुधार हेतु आजादी के बाद अनेक प्रयास हुए जिसके फलस्वरूप फिर से महिलाओं की स्थिति में सुधार और समाज में उनका सम्मान बढ़ना प्रारंभ हुआ है। महिलाओं की स्थिति में आई इस गिरावट के कारण समाज में महिलाओं को पुरुषों से कमजोर मानकर उनसे भिन्न तरह का व्यवहार किया जाने लगा। महिलाओं पर अनेक बंधन आरोपित कर दिए गए जिससे उनकी शक्ति का समुचित उपयोग समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए नहीं हो पा रहा था। भारत ही नहीं अपितु विश्व में भी महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखकर उनसे अमानवीय व्यवहार तक किया जाने लगा था। महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक और जेंडर रूप में दूसरों के पालन करने के लिए हैं और उन्हें माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में पुरुषों की सुरक्षा में रहना चाहिए, ऐसी मानसिकता ने भारतीय समाज को जकड़ लिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि राष्ट्र उन्नति में महिला शक्ति का उपयोग पूर्णतया नहीं हो पाया और हम विश्व में प्रथम स्थान से फिसलते चले गए। राष्ट्र निर्माण के लिए किसी को हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जहाँ एक तरफ यह संविधान का उल्लंघन होगा वहीं राष्ट्र उन्नति में उसकी आधी आबादी के योगदान से वंचित करना है। आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति सुधार के इन प्रयासों और उनके सशक्तीकरण की गति धीमी रही है। आजादी के 75 वर्ष के पश्चात भी सभी महिलाओं को वह अधिकार नहीं मिल पाए हैं जिनकी वह अधिकारणी है और जिससे उनकी शक्ति का समुचित उपयोग राष्ट्रीय उन्नति में किया जा सके। शिक्षा का अभाव इसका एक बड़ा कारण है। महात्मा गांधी के शब्दों में ''महिलाओं को कमजोर मानना अपराध है, यह पुरुषों का महिलाओं के प्रति अन्याय है। शक्ति का अर्थ यदि नैतिक/आत्मिक शक्ति से है तो महिलाएँ पुरुषों से असीमित रूप से श्रेष्ठ हैं।''

यदि हम राष्ट्र और समाज की उन्नति में महिलाओं की भूमिका पर नजर डालें तो प्रत्येक क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय है। परिवार में महिलाएँ माँ, पत्नी, प्रशासक और प्रबंधन की भूमिका में सतत विकास और जीवन की गुणवत्ता की कुंजी के रूप में पूर्ण समर्पण से कार्य करती हैं। माँ के रूप में महिला की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है जिसमें बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उसे शिक्षित एवं संस्कारित कर समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का कार्य भी महिला करती है। इस प्रकार माँ के रूप में उसमें मानव कल्याण की भावना, कर्तव्यनिष्ठा, सृजनशीलता एवं ममता को सर्वोपरि मानने का भाव विद्यमान रहता है। पत्नी के रूप में भारत की नारी सती सावित्री बन अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से भी भिड़ जाने की हिम्मत रखती है वहीं वह सतीत्व और आत्म सम्मान के लिए आत्मदाह तक कर लेने से भी नहीं झिझकती। गृहणी के रूप में वह परिवार की धुरी होती है। वह संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं की वास्तविक संरक्षिका और वाहिका की भूमिका में उनका संरक्षण, हस्तांतरण और संवर्धन करने का दायित्व बखूबी निभाती है। भावी पीढ़ी को शिक्षित करने और उनके विकास में महिलाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक पुरुष को ही शिक्षित करते हैं परंतु जब एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (असर) के अनुसार माँ के शिक्षा स्तर का बच्चों के समग्र विकास के साथ गहरा संबंध होता है।

लोकतंत्र का सही अर्थ वह है जिसमें निर्णय करने के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की वास्तविक, सक्रिय और पर्याप्त भागीदारी हो। वर्तमान में सरकार विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, नेतृत्व और निर्णय लेना, रोजगार और वित्तीय समावेशन आदि में जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वन स्टॉप सेंटर, स्वाधार गृह योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन शक्ति आदि अनेक योजनाएँ महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य कर रही है।

महिलाओं की भूमिका को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बखूबी देखा जा सकता है। सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं में 70 से 80 प्रतिशत महिला स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हमारे देश में है। परिवार के स्वास्थ्य एवं पोषण का ध्यान एक गृहणी बहुत अच्छी तरह करती है। यदि महिला शिक्षित है तो वह स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरत को पहचानने का कार्य अधिक कुशलता से कर सकती है। सभी स्तरों पर स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को सुधारने में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रही है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महिलाएँ उत्पादक और उद्यमी दोनों तरह का कार्य करते हुए इसकी उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता चारों पहलुओं को सुनिश्चित करने में अपना योगदान दे रही है। यदि राष्ट्र के आर्थिक विकास के क्षेत्र को देखा जाए तो 65 प्रतिशत महिलाएँ कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते हुए देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में महिलाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं के पास केवल 13 प्रतिशत भूमि है और कृषि कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी लगभग 48 प्रतिशत है। विनिर्माण कार्य बल में लगभग 20 प्रतिशत

सहभागिता महिलाओं की है। भारत स्टार्टअप के मामले में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें 10 प्रतिशत का नेतृत्व महिला संस्थापक कर रही हैं। शोध बताते हैं कि महिलाओं द्वारा शुरू किए गए उद्यम प्रकृति में अधिक टिकाऊ हैं। 2022 में 250 भारतीय कंपनियों के सर्वेक्षण से पता चला है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक की भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत बढ़ गई है जो राष्ट्र की उन्नति में उनकी भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि को इंगित करता है।

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय रहा है। बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, अपपिको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण आंदोलन हैं जो महिलाओं में नेतृत्व की नैसर्गिक क्षमता को दर्शाते हैं। पारंपरिक रूप से पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भागीदारी रहती है। किसानों, पशुपालकों तथा जल एवं ईंधन संग्राहकों के रूप में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रहती है। ग्रामीण समुदाय की महिलाएँ आजीविका और कल्याण के लिए मुख्यत: प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं जिसमें वे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की टिकाऊ प्रक्रियाओं को अपनाकर न केवल राष्ट्र प्रगति अपितु विश्व कल्याण में अपना योगदान देती रही हैं। पर्यावरण प्रबंधन व संरक्षण, समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करके हम प्रगति की दर को और बढ़ा सकते हैं।

वर्तमान में महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। महिलाओं के लिए कठिन माने जाने वाले क्षेत्रों में भी महिलाएँ अपनी क्षमता का प्रदर्शन अच्छे से कर रही हैं। पुलिस, अर्धसैनिक बलों सहित सभी सुरक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी है। भारतीय सशस्त्र बलों (सेना, वायु सेवा और नौसेना) में भी महिलाओं की भूमिका पायलट और फाइटर प्लेन उड़ाने में भी दिखाई देने लगी है जो कि पहले केवल पुरुषों का क्षेत्र ही माना जाता रहा है। इसी प्रकार डेयरी फार्मिंग जिसमें पहले पुरुषों का वर्चस्व रहा है उसमें वर्ष 2018 में भारतीय सहकारी संघ की रिपोर्ट में 4.98 मिलियन महिलाओं ने भागीदारी की है जो सहकारी समितियों में कुल सदस्यता का 30 प्रतिशत है। चंद्रयान- 3 की अवधारणा, डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और क्रियान्वयन में 100 से अधिक महिला कर्मचारियों ने प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की कई महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की चंद्र मिशन में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। कोविड-19 के दौरान कोरोना योद्धाओं के रूप में महिला डॉक्टरों, नर्सों, आशा वर्करों और आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका काबिले तारीफ रही है। स्वदेशी वैक्सीन को तैयार करने में महिला वैज्ञानिकों का योगदान रहा है जिसमें उन्हें पुरस्कार भी मिले हैं। किसी भी परीक्षा में बालिकाओं का प्रदर्शन हमेशा बालकों की तुलना में श्रेष्ठ ही रहता है। इस प्रकार महिलाएँ स्वयं को सशक्त और सक्षम बनाने के साथ-साथ राष्ट्र की मजबूती में भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है।

लोकतंत्र का सही अर्थ वह है जिसमें निर्णय करने के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की वास्तविक, सक्रिय और पर्याप्त भागीदारी हो। वर्तमान में सरकार विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, नेतृत्व और निर्णय लेना, रोजगार और वित्तीय समावेशन आदि में जेंडर समानता और महिला सशक्तीकरण पर ध्यान दे रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वन स्टॉप सेंटर, स्वाधार गृह योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन शक्ति आदि अनेक योजनाएँ महिला सशक्तीकरण हेतु कार्य कर रही है। वर्तमान में महिलाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दे रही है। आज महिलाएँ राजनीतिक, व्यापार, कला, खेल सहित रक्षा क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रही हैं। सेना, मिसाइल, परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति का लोहा बनवा रही हैं। वह दिन दूर नहीं जब प्राचीन भारतीय नारी के सम्मानित स्थान को महिलाएँ प्राप्त कर लेंगी। महिलाओं में नेतृत्व का नैसर्गिक गुण होता है और यह किसी भी राष्ट्र की एक अमूल्य निधि है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच में सुधार, उन्हें सहायक सेवा प्रदान करना (देखभाल, स्वास्थ्य एवं परिवहन), नेतृत्वकारी भूमिकाओं में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सामुदायिक भागीदारी में प्रोत्साहित आदि किया जाए ताकि वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव की अग्रदूत बन सके।

अर्थशास्त्र में ऐसा कोई पैमाना नहीं है जो महिलाओं के कार्यों का सही आकलन कर उनका मूल्यांकन कर सके। भारतीय महिलाओं की बचत की प्रवृत्ति ने भारत को 1930,1998, 2008 और 2014 में आई वैश्विक मंदी से बचाया जबकि लगभग विश्व के सभी देश इससे ग्रसित हुए। 2016 की नोटबंदी अभी हाल ही का उदाहरण है जिसमें भारतीय महिलाओं की बचत अच्छी तरह से दृष्टिगोचर होती है। भारतीय महिलाओं की बचत की प्रवृति ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया बल्कि महिलाएँ इस प्रवृत्ति को आने वाली पीढ़ी में भी विकसित करती रही हैं। परिवार को बांधने और जोड़ने के उनके दायित्व का मूल्य क्या कोई अर्थशास्त्री आँक सकता है? परिवार एवं समाज के लिए उसके कर्तव्य, सहयोग, समर्पण, संवेदनशीलता, संघर्ष और स्नेह भावना की कीमत कौन से पैमाने से मापी जा सकती है ? नेपोलियन बोनापार्ट ने सही ही कहा है, ''मुझे एक योग्य माता दो मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूँगा।'' ❑

उन्नत भारत अभियान और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों ही महत्त्वपूर्ण पहलू हैं जो भारतीय समाज को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये पहलू देश को स्वच्छ, स्वस्थ और शिक्षित बनाने की दिशा में गति प्रदान कर रहे हैं, जिससे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो सके। इन पहलुओं को लागू करने के लिए सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर समर्थन और सहयोग आवश्यक है ताकि भारत वास्तव में उन्नत और सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर सके।

उन्नत भारत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020

श्रद्धा मिश्रा
शोध छात्रा,
गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

उन्नत भारत अभियान की संकल्पना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के समर्पित संकाय सदस्यों के एक समूह की पहल से शुरू हुई, जो ग्रामीण विकास और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। सितंबर, 2014 में आईआईटी दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान ग्रामीण विकास कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल कई तकनीकी संस्थानों, ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्रवाई समूह (आरयूटीएजी) समन्वयकों, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से इस अवधारणा को विकसित किया गया था। कार्यशाला को जन कार्रवाई और ग्रामीण प्रोन्नत भारत अभियान और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दोनों ही भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं जो देश के विकास और उन्नति को समर्थन देने के लिए शुरू की गई हैं। भारत, एक विशाल और विविधता-सम्पन्न देश, जिसमें अनेक सांस्कृतिक, भाषाई, और सामाजिक परंपराएँ आपस में मिलती हैं, वहाँ भी आज भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्नत भारत अभियान और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इनमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन पहलुओं का मुख्य उद्देश्य देश की ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, आदि के क्षेत्रों में सुधार करना है, ताकि भारत एक उन्नत और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े।

उन्नत भारत अभियान: देश का विकास के लिए एक अमूल्य संकल्प

उन्नत भारत अभियान भारत सरकार का एक अमूल्य संकल्प है जो देश को विभिन्न क्षेत्रों में विकास की ऊँचाइयों तक पहुँचाने का उद्देश्य रखता है। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था और यह एक व्यापक राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम है जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

- बैठक की मुख्य बातें : केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निम्नलिखित पर जोर दिया –
- सभी गाँवों में समान तीन से पाँच मुख्य मुद्दों तथा स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित कुछ मुद्दों की पहचान करें और उन पर काम करें।
- अधिक गाँवों को लाभ पहुँचाने के लिए इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या को अधिकतम करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के संबंध में स्कूल शिक्षकों को संवेदनशील बनाने में यूबीए का उपयोग किया जाना चाहिए।
- एक ऐसे पोर्टल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया जो विभिन्न संस्थानों के लिए एक इंटरैक्टिव मंच के रूप में काम करेगा जहाँ वे सफलता की कहानियाँ साझा कर सकेंगे और एक-दूसरे को प्रेरित कर सकेंगे।
- यूबीए के अंतर्गत साक्षरता, स्वास्थ्य सेवा आदि में सुधार जैसे मापदंडों के संबंध में राज्यवार अध्ययन करना तथा लक्ष्य निर्धारित करना।

मुख्य उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी मुद्दों की पहचान करने तथा उनके लिए स्थायी

समाधान खोजने में उच्च शिक्षा संस्थानों के संकाय और छात्रों को शामिल करना।

- लोगों की आवश्यकता के अनुसार, विद्यमान नवीन प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उनका चयन करना, प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को सक्षम बनाना, या नवीन समाधानों के लिए कार्यान्वयन विधियों को विकसित करना।
- उच्च शिक्षा संस्थानों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रणालियां तैयार करने में योगदान देने की अनुमति देना।

उन्नत भारत अभियान 2.0

- यह UBA 1.0 का उन्नत संस्करण है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था।
- यूबीए 1.0 या यूबीए चरण–1 आमंत्रण मोड था जिसमें भाग लेने वाले संस्थानों को यूबीए का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- जबकि यूबीए 2.0 उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का चैलेंज मोड है , जिसके तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को कम से कम 5 गांवों को स्वेच्छा से गोद लेना होगा। वर्तमान में, यूबीए 2.0 मोड चल रहा है।

उन्नत भारत अभियान के कुछ मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं –

1. **स्वच्छ भारत अभियान :** इसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाना है, जिसमें सार्वजनिक स्वच्छता, शौचालय सुधार, जल संरक्षण और वातावरण संरक्षण शामिल हैं।
2. **स्वस्थ भारत अभियान :** यह अभियान भारत के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण, बीमारियों के प्रतिनियंत्रण, और जनसंख्या के नियंत्रण शामिल हैं।
3. **ऊर्जा संरक्षण और विकास :** इसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करना और उन्नत ऊर्जा प्रणालियों को प्रोत्साहित करना है।
4. **ऊर्जा स्वायत्तता :** यह लक्ष्य उच्च स्तरीय ऊर्जा स्वायत्तता की स्थापना करना है, जिससे भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वतंत्रता से पूरा कर सके।
5. **डिजिटल भारत अभियान :** इसका लक्ष्य भारत को डिजिटल बनाना है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट सुविधाएँ, ई–गवर्नेंस, और डिजिटल प्रवासी सेवाएँ शामिल हैं।
6. **संवैधानिक व्यवस्था और न्यायपूर्ण भारत :** इसका उद्देश्य भारत को एक संविदानिक और न्यायपूर्ण समाज के रूप में स्थापित करना है, जिसमें न्यायिक सुधार, पुलिस सुधार और संवैधानिक सुधार शामिल हैं।
7. **गाँव विकास योजना :** इसका उद्देश्य भारत के गाँवों को विकसित करना है, जिसमें ग्रामीण आर्थिक विकास, कृषि विकास, और ग्रामीण अधिकारों की सुरक्षा शामिल हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास है। यह नीति एक दशकों के बाद आई है और उसे आधुनिक शिक्षा विचारधारा के साथ संगत बनाने का प्रयास किया गया है। इस नीति के अनुसार, शिक्षा प्रणाली को व्यापक रूप में सुधारा जाएगा, जिसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएँ और प्रक्रियाएँ शामिल होंगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ मुख्य प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं –

1. **अधिक एकीकृत शिक्षा प्रणाली :** नई नीति का लक्ष्य है भारत में एक एकीकृत शिक्षा प्रणाली को बनाए रखना, जिसमें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा एक साथ शामिल होंगी। यह समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
2. **नवाचारिक शिक्षा :** नई नीति के अनुसार, नवाचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और अन्य नवाचारिक क्षेत्रों में रुचि और कौशल विकसित करने का मौका मिले।
3. **भाषा शिक्षा :** नई नीति के अनुसार, भारत में भाषा शिक्षा को महत्व दिया जाएगा, ताकि छात्र अपनी मातृभाषा में भी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
4. **गुणवत्ता के मानक :** शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता के मानकों को बढ़ावा देने के लिए, नई नीति में गुणवत्ता को मानकांकन के लिए विभिन्न प्रमाणपत्रों का प्रयोग करने का प्रावधान है।
5. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी :** नई नीति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक विकास करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान और कौशल प्राप्त हों।
6. **समृद्ध गुरुकुल :** नई नीति का उद्देश्य है समृद्ध गुरुकुल प्रणाली को प्रोत्साहित करना, जो वैदिक और अद्वितीय शिक्षा प्रणाली है।
7. **पेड़ागोजी शिक्षा :** नई नीति में पेड़ागोजी शिक्षा को महत्त्व दिया गया है, जिसमें छात्रों को अधिक सक्रिय रूप से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा।

निष्कर्ष

उन्नत भारत अभियान और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों ही महत्त्वपूर्ण पहलू हैं जो भारतीय समाज को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये पहलू देश को स्वच्छ, स्वस्थ और शिक्षित बनाने की दिशा में गति प्रदान कर रहे हैं, जिससे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो सके। इन पहलुओं को लागू करने के लिए सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर समर्थन और सहयोग आवश्यक है ताकि भारत वास्तव में उन्नत और सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर सके। ❑

धारणक्षम विकास और समरस भारत

प्रो. शिवशरण कौशिक
प्रोफेसर,
राजकीय महाविद्यालय
साँगानेर, जयपुर (राज.)

किसी भी राष्ट्र की उन्नति और उसकी सामाजिक समरसता के बीच परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध होता है। प्राय: वही समाज या देश तेजी से उन्नति करता है जिसके निवासियों के बीच राष्ट्र की केंद्रीयता में एक दूसरे के मध्य सौहार्द तथा सद्भाव होता है। सामाजिक विखंडन तथा अलगाव उसकी प्रगति में सदैव बाधक ही होते हैं। कहा गया है कि ''जहाँ सुमति तहँ संपति नाना, जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना। निस्संदेह आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वह अत्याधुनिकता के विकास से संपन्न होता विज्ञान युग है जिसमें मशीनों तथा यंत्रों ने समग्र जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। कुछ क्षेत्रों में निश्चित रूप से विकास की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। काल क्रमानुसार शिक्षा की प्रगति के मानदंड और प्रारूप भी बदले हैं।

यह युग इतिहास के अन्यान्य युगों से बहुत भिन्न है। वैज्ञानिक साधनों ने इसे ऐसी अनेक विशेषताओं से संचालित किया है जो पुराने युगों से अपरिचित थी। इस कालखंड में किसी भी स्थान विशेष पर जब कोई घटना घटती है तो उसे विश्व पटल पर प्रचारित होने में क्षण भर नहीं लगता। सभी क्षेत्रों में तात्कालिकता तथा क्षिप्रकारिता का जोर बढ़ गया है। तब यह आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक घटक में परस्पर समन्वय तथा समावेशी भाव प्रबल हो! आज राजनीति के कारण अथवा अनेक दूसरे आर्थिक या अस्मितामूलक कारणों से समाज में एक दूसरे को सशंक दृष्टि से देखा जाने लगा है। चेहरे भयग्रस्त दिखाई देने लगे हैं या भय का वातावरण बनाया जाने लगा है।

इन सब बातों के चलते यह अत्यंत ही आशान्वित करने वाली बात है कि हमारा आज का शक्तिशाली और ऊर्जावान नेतृत्व देश के नवनिर्माण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील ही नहीं है, अपितु सकारात्मक परिणामों के लिए सतत् चिन्तित है। ऊपरी सतह पर जो कोलाहल सुनाई दे रहा है उससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश की अंतरात्मा जाग्रत है और हलचल जीवन का लक्षण है जो निश्चित ही आगे की ओर ले जाती है।

भारत की आर्थिक प्रगति और सामाजिक समरसता में मूलत: विभिन्न

> **भारत का इतिहास अति प्राचीन है, संस्कृति बहुत समृद्ध है, हमारा अनुभव अपार है। भारत के लोग वर्षों से शांतिप्रिय, उद्यमशील और सहिष्णुता रहे हैं। यह भारतवासियों की सकारात्मक ऊर्जा ही है जो देश की प्रगति और समरसता दोनों के स्थापत्य में उल्लेखनीय योगदान देती रही है। युवाओं का विश्वसनीय सामर्थ्य और उनका प्रबल जीवन कौशल हर कालखंड में भारत के सतत् निर्माण में सहयोगी रहा है। सौभाग्य से हम भारत के ऐसे पूर्वजों की संतान हैं जो धीर-भाव से सोचने में और शांत-भाव से देखने में विश्वास करते रहे हैं।**

समुदायों, विभिन्न प्रांतों, विभिन्न भाषाओं तथा विभिन्न ज्ञान-परंपराओं और मान्यताओं के मध्य एक समान आशा, उमंग, उत्साह हो तथा भारत की समूची ज्ञान-संपदा का आपस में सम्यक विनिमय हो, यह परम आवश्यक है। हमारे देश की स्वतंत्रता का यह अमृतकाल इसी सर्वतोपयोगी ज्ञान-विज्ञान के सुनियोजित तथा योजनाबद्ध रूप से किए जाने वाले सदुपयोग का नाम है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विगत कुछ वर्षों में भारतीय पृष्ठभूमि की सुविचारित योजनाएँ आरंभ हुई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसे अनेक उपबंध किए गए हैं जो भारतीय समाज में एक ऐसा परिवर्तन लाने के कारक बन सकेंगे जिनसे सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय का सुफल प्राप्त हो सकेगा। भारत की उन्नति तथा सामाजिक समरसता की स्थापना का यह सुचिन्तित कालखंड है।

वस्तुतः शिक्षा पद्धति और देश की शिक्षा व्यवस्था में समूचे भारतीय समाज की गतिशीलता का प्रकटीकरण अवश्य ही होना चाहिए। यह सर्वविदित है कि प्रवाह सदैव शोधक शक्ति का काम करता है। नदी में भी, जीवन में भी, समाज में भी और राष्ट्र में भी। प्रवाह के अवरुद्ध होने से जिस प्रकार से नदी का पानी सड़ने लगता है, उसी प्रकार से समाज में भी सदाशयता और समरसता का स्रोत सूखने लगता है, और ऐसी स्थिति में समाज में भी कई प्रकार की विषमताएँ आने लगती हैं। यद्यपि इनमें बहुत सी विषमताएँ प्रकृति-प्रदत्त हैं, और वे तो रहेंगी, किंतु बहुत सी विषमताएँ 'व्यक्तियों' तथा 'शक्तियों' द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। प्रत्येक युग में राष्ट्र-विरोधी शक्तियाँ भारतीय समाज को विभाजित कर देश को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास करती रही हैं। वे अकादमिक क्षेत्र के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में निरन्तर अपने अभियान चलाती रहती हैं।

यह सचाई है कि अनेक सामाजिक सांस्कृतिक श्रेष्ठताओं के बाद भी आज भारतीय समाज अनेक जातियों में बँटा हुआ है और जातियों के बीच विभेदकारी षडयंत्रों के प्रयास तीव्रगामी होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा, समाज और राजनीति के सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले महनीय व्यक्तियों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि वे भारत की सामाजिक समरसता तथा सुरक्षा की दिशा में अधिक सजग होकर कार्य करें। शिक्षक का समाज में जब-जब आचरण और व्यवहार उच्चतम जीवन मूल्यों से परिचालित रहा है, वह उतना ही स्वीकार्य और मान्य रहा है। समाज की शाश्वत गतिशीलता का प्रथम मार्गदर्शक शिक्षक ही होता है। वही समाज की संपूर्णता व सरसता का प्रवर्तक भी होता है। साथ ही समरसता से ही समाज में सौहार्द, एकता और शक्ति का निर्माण होता है। भारत के समग्र विकास और धारणक्षम विकास की भी यही अवधारणा है। एक संपन्न राष्ट्र उसमें निवास करने वाले सभी जाति, मत और संप्रदाय के लोगों के समान रूप से होने वाले विकास के आधार पर ही स्थाई रूप से समृद्धिशाली हो सकता है। भिन्न-भिन्न खान-पान, वेशभूषा, आचार-व्यवहार, मान्यता और विश्वासों को स्वीकारते हुए एक दूसरे को सम्मान प्राप्त हो। यदि प्रत्येक नागरिक अपनी जाति और संप्रदाय के प्रति पहले से उपस्थित अतिरिक्त भावात्मक एकता के साथ राष्ट्रीय एकता के लिए अन्य समाजों के साथ भी एक्य स्थापित करता है, तभी सार्थक समरसता स्थापित हो सकती है। इसी को हम वर्षों से भारत की अनेकता में एकता कहते आए हैं।

राज्य और राष्ट्र की दृष्टि से यदि किसी समाज या देश के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होते तो वह देश या समाज, ना ही उन्नति कर सकेगा, और ना ही समरस रह सकेगा। दूसरी ओर सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त शिक्षित नागरिक देश के निर्माण में अपनी माहती भूमिका निभाएंगे, यही परस्पर सामाजिक समरसता है। इसीलिए आज विश्व के बहुत से देश शांति और सुरक्षा के नाम पर अत्यधिक धन व्यय कर रहे हैं।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में भारत की सभी जातियों, मत-पंथों के लोग एक साथ मिलकर, सारे सामाजिक विभेद मिटाकर राष्ट्रीय एकता व समरसता का अनूठा प्रमाण दे चुके हैं। भारत का स्वाधीनता आंदोलन विदेशी राज्य से मुक्ति तक ही सीमित नहीं था, अपितु भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वत्व की प्राप्ति का संघर्ष था। क्योंकि ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों द्वारा किए गए आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक दमन ने भारत को अनेक वर्ष पीछे धकेल दिया

था। उस समय की भारत की निर्धनता और आर्थिक विपन्नता का विषय दादाभाई नौरोजी ने सन् 1876 में अपने निबंध 'पॉवर्टी इन इंडिया' में पुरजोर रूप से उठाया था जिसे बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन् 1886 से अपने कार्यक्रमों का प्रमुख हिस्सा बना लिया। सन् 1891 में अपने सातवें अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया – ''पूरी 5 करोड़ जनता जिनकी संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, एक शोचनीय स्थिति में धँसी हुई भुखमरी के कगार पर खड़ी है और प्रति दशाब्द लाखों व्यक्ति सचमुच ही भुखमरी के कारण मृत्यु का ग्रास बनते हैं'' बाद के वार्षिक अधिवेशनों में भी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की अंग्रेजों ने जो दशा की, उस समय की भारत की गरीबी और भुखमरी का उल्लेख बराबर किया जाता रहा।

सन् 1896 में लोकमान्य तिलक द्वारा संपादित मराठी साप्ताहिक 'केसरी' में कुछ पद्य प्रकाशित हुए थे जिनमें शिवाजी महाराज को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत देश की दुर्दशा पर इस प्रकार से शिकायत करते हुए दिखाया गया है – ''हाय! हाय! यह मैं अपनी आँखों से देश की विनाश लीला को देख रहा हूँ ... हाय! यह कैसा विनाश का तांडव नृत्य है... समृद्धि समाप्त हो चुकी है और उसके बाद स्वास्थ्य भी। देश में दुर्भाग्य का दानव सारे देश को अकाल के शिकंजे में जकड़े हुए हैं।'' यहाँ यह कह देना उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय का यह दारिद्र–चिंतन किसी वर्ग–विशेष के लिए न होकर भारत के समूचे सर्वसाधारण के लिए था। सन् 1875 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपनी प्रसिद्ध कृति 'भारत दुर्दशा' में ऐसा ही उल्लेख किया है, वह लिखते हैं –

रोवहु सब मिलि कै आवहु भारत भाई
हा! हा! भारत दुर्दशा न देखी न जाई।

इस कविता में भारतेंदु भारत के समृद्ध और गौरवशाली अतीत का स्मरण तो करते ही हैं साथ में अंग्रेज राज्य की दुर्नीतियों का भी खुलासा करते हैं। साथ ही वे भारत को पुन: समर्थ बनाने का आह्वान भी करते हैं।

भारत का इतिहास अति प्राचीन है, संस्कृति बहुत समृद्ध है, हमारा अनुभव अपार है। भारत के लोग वर्षों से शांतिप्रिय, उद्यमशील और सहिष्णु रहे हैं। यह भारतवासियों की सकारात्मक ऊर्जा ही है जो देश की प्रगति और समरसता दोनों के स्थापत्य में उल्लेखनीय योगदान देती रही है। युवाओं का विश्वसनीय सामर्थ्य और उनका प्रबल जीवन कौशल हर कालखंड में भारत के सतत् निर्माण में सहयोगी रहा है। सौभाग्य से हम भारत के ऐसे पूर्वजों की संतान हैं जो धीर–भाव से सोचने में और शांत–भाव से देखने में विश्वास करते रहे हैं।

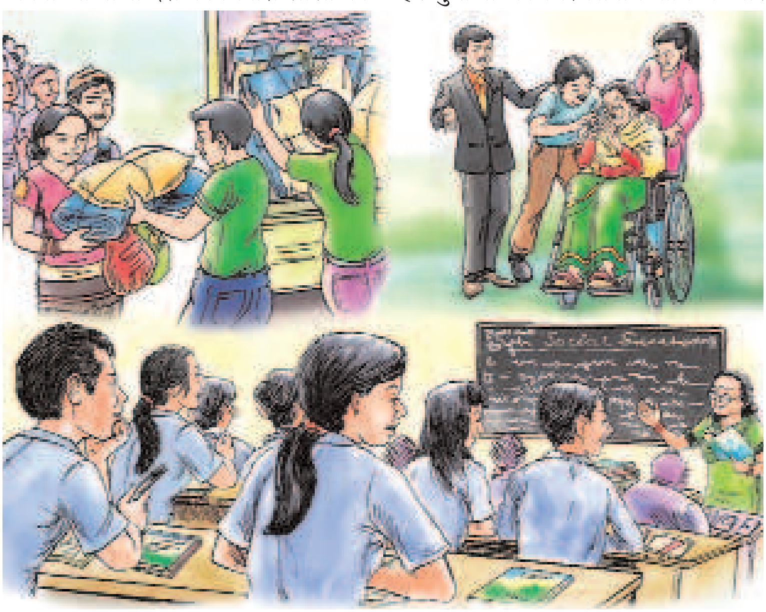

यह एक ऐतिहासिक सचाई है कि भारत की सामाजिक समरसता और आर्थिक उन्नति के निर्माण में विभिन्न पक्षों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भारत कृषि प्रधान तथा श्रम प्रधान देश रहा है, इसलिए सदियों से फसलों, खाद्यान्नों के परस्पर विनिमय के कारण समाज में परस्पर मैत्रीपूर्ण वातावरण रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि से नदियों, पर्वतों, वनों तथा सरोवरों के परिक्षेत्रों में आयोजित होने वाले मेलों, समागमों, उत्सवों, त्योहारों ने भी समाज को सर्वांग दृष्टि से मंगलकारी परिस्थितियां प्रदान की हैं। आज भी इन आयोजनों की नये रूप में भारत की सामाजिक समरसता और धारणक्षम विकास की दृष्टि से महत्ता कम नहीं हुई है। हाँ, यह अवश्य है कि ये सभी आयोजन प्रकृति संरक्षण की बुनियाद पर ही संपन्न होने चाहिए।

किंतु फिर भी हमने परतंत्रता का सामाजिक और आर्थिक शोषण देखा है। भारत के विकास के बढ़ते कदम अब विश्व का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। आज हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। विज्ञान, उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में विगत दशक में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शौचालय, सड़क, रेल, पानी, बिजली आदि के क्षेत्र में भी भारत ने समूचे देश में विकास की बृहत् आधारशिला निर्मित की है।

आज जब विश्व के कई बड़े भूभाग युद्ध की विभीषिका में झुलस रहे हैं तब वसुधैव कुटुंबकम् के भारतीय विचार की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। हम सब प्रकार से मानवता, समता और स्वाधीनता के आधार पर संसार को नया प्रकाश देने के अधिकारी हैं और मनुष्य को नई संस्कृति देने के संकल्प के उचित पुरस्कर्ता हैं। ❑

वर्तमान उन्नत भारत का वैश्विक शांति में योगदान

डॉ. अमित सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर,
राष्ट्रीय सुरक्षा विशिष्ट अध्ययन केंद्र, जे.एन.यू, नई दिल्ली

पिछले 10 सालों में भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की है जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत विश्व की पाँचवी अर्थव्यवस्था है एवं इसकी अंतरराष्ट्रीय साख भी बढ़ी है। यह विकास एवं उन्नति ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की चहुँमुखी उन्नति में भारत की विदेश एवं सुरक्षा निति का विशेष योगदान रहा है। भारत की विदेश नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में भारत सरकार में काफी बदलाव हुआ है। पिछले 10 सालों में भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है एवं इसमें मजबूती आई है। हालाँकि अभी तक भारत की लिखित 'राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति' नहीं है, शायद इसलिए मोदी सरकार ने इसे भी अमलीजामा पहनाने की कवायद भी चल रही है। यह रणनीति सेना और रक्षा संबंधित निकायों को विभिन्न प्रकार के खतरों से निपटने के लिए दिशानिर्देशों की तरह काम करेगी। हालाँकि अभी हाल ही में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति' लिखित हो या न हो जरूरत इस बात की है कि भारत को चहुँ ओर से कैसे सुरक्षित रखा जाए और पिछले कई सालों से भारत इसमें लगा हुआ है और सफलता पाई है। जनरल अनिल चौहान ने यह भी कहा कि ''पाकिस्तान भले ही एक तरह की आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है, लेकिन सैन्य रूप से उसकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं आई है और उसकी सेनाएँ हमारे लिए खतरा बनी हुई हैं।'' सीडीएस ने कहा, ''हमारी तात्कालिक चुनौती चीन का उदय और अनसुलझी सीमा समस्या है। हमारे दो पड़ोसी हैं, और दोनों हमारे विरोधी हैं। दोनों का दावा है कि उनकी दोस्ती हिमालय से भी ऊँची और महासागर से भी गहरी है और वे दोनों परमाणु हथियार सक्षम हैं।'' उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हमें अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकना चाहिए।

यहाँ गौरतलब यह है कि जबसे नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है तब से विदेश नीति काफी रोबस्ट यानी मजबूत हो चली है। एक जमाना था जब भारत की विदेश नीति को या भारत को अंतरराष्ट्रीय पटल पर पश्चिमी देशों का पिछलग्गू देश माना जाता था पिछले कुछ समय से देखा गया है कि अब भारत और भारत की विदेश नीति एवं सुरक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। यह नया भारत है जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बिल्कुल मुखर होकर अपनी बात रखता है, यहाँ तक कि कई सारे अंतरराष्ट्रीय विषयों या संदर्भों पर हवा का रुख बदलने का दम रखता है।

अभी हाल ही में जो कुछ चर्चाएँ चलीं हैं कि भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच चलने वाले युद्ध में हस्तक्षेप करते हुए युद्ध को रुकवाया एवं रूस ही नहीं यूक्रेन को भी मनाते हुए पूरी कोशिश की, ताकि भारतीय

छात्रों को एवं नागरिकों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, हमास और इजरायल के बीच में भी जो जंग चल रही है उसमें भी भारत ने दोनों पक्षों को समझाते हुए, शांति की बात की और वहाँ से भी अपने नागरिक भी निकाले है। पिछले कुछ सालों से जहाँ पर भी किसी भी तरह का विवाद, गृह युद्ध या किसी तरह की युद्ध की स्थिति या फिर महामारी की स्थिति में भी भारत ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बल्कि पाकिस्तान, नेपाल एवं पश्चिमी देशों के नागरिकों को भी भारत ने सुरक्षित उनके मुल्क पहुँचाया है। भारत की राजनीति अब बदल चुकी है और अब हर जगह भारत की धाक है।

यह बात किसी से छुपी नहीं है कि रूस के साथ भारत के बहुत पुराने और घनिष्ठ संबंध हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए, अमेरिका, नाटो एवं अन्य मुल्क भी भारत की तरफ, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध को कैसे रोका जाए एवं भारत से दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की गुहार कर रहे हैं। यह बात सही है कि जब खरसान में 2022 में रूस को कुछ समय के लिए थोड़ा सा मुँह की खानी पड़ी थी, ऐसे में पुतिन को लग रहा था की इसमें तकनीकी या सामरिक तौर पर परमाणु हमला कर के वह यूक्रेन की पीठ तोड़ सकते हैं। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने भी रूस में परमाणु मूवमेंट को चिन्हित किया था। उन्होंने बताया कि रूस परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है और यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएगा, ऐसे में नाटो और अमेरिका की नींद उड़ गई थी और वो पूरी तैयारी में लग गए कि किसी भी तरह से रूस को ऐसा करने से रोकना है। उन्होंने कई देशों को गुहार लगाई और उसमें भारत भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले को हाथों हाथ लिया और पुतिन से बात की और खतरे को टाला। इतना ही नहीं जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन की मीटिंग हुई थी तब भी भारत में साफ तौर पर बोला कि ये युग युद्ध

भारत के पास विशेषज्ञता है और वो इस मामले में एक लंबा एवं विश्वसनीय रोल प्ले कर सकता है। अब भारत ने डिफेंस स्वावलंबन में अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है और आने वाले समय में भारत की धमक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और भी बढ़ने वाली है। अगर भारत लगातार अपनी रक्षा निर्यात की नीति पर ऐसे ही तवज्जो देता रहा तो जल्द ही भारत विश्व की नंबर एक अर्थव्यवस्था बन जाएगा क्योंकि रक्षा निर्यात के छेत्र में ही यह पोटेंशियल है कि वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जमीन से आसमान तक कुछ ही क्षणों में ले जा सकता है।

का युग नहीं है। आपसी सहयोग के माध्यम से विवादों का निपटारा किया जा सकता है। जब जी-20 की अध्यक्षता भारत ने की तब भी इस बात को दोहराया गया कि ये युद्ध का समय नहीं है, हमें मिल-बैठकर आपसी विवादों का निपटारा करना चाहिए। शायद यही भारत की लीडरशिप का नतीजा है कि इतने सालों से जिस जी-20 का एक साझा वक्तव्य जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आता था, लेकिन भारत की अध्यक्षता में वह भी संभव हुआ। भारत ने अपनी लीडरशिप साबित की। इसलिए अमेरिका, रूस और यहाँ तक कि चीन भी एक जॉइंट स्टेटमेंट के लिए तैयार हुआ एवं इतिहास में पहली बार एक साझा वक्तव्य भारत की अध्यक्षता वाले जी-20 में आया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की धाक साफ तौर पर देखी जा सकती है, एक पुख्ता विदेश नीति देखी जा सकती है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कई नेता कायल हैं, कई एजेंसियाँ लीडरशिप की एक अप्रूवल रेटिंग भी निकालती हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी सर्वोच्च स्तर पर हैं। जिस धमक के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बात अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखते हैं या फिर पश्चिमी देशों को जवाब देते हैं। उससे साफ पता चलता है कि ये एक नया भारत है। अभी कुछ दिन पहले भारत के संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि, कांबोज ने भी बिल्कुल खुलकर ये वकालत की कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं करेगा, कुछ नए सदस्यों को नहीं लाएगा तो उसकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी।

पिछले 10 सालों की विदेश एवं सुरक्षा नीति का लेखा जोखा यही है कि भारत के नेतृत्व में कई अंतरराष्ट्रीय पहलें (इनीशिएटिव) हुई हैं। उसको भारत के

साथ-साथ विश्व के कई संगठन हाथों हाथ ले रहे हैं, चाहे वो सोलर अलायन्स की बात हो या फिर जी-20 सबमिट की बात हो या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन की बात। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया गया है, जो भारत की शर्तों पर हुआ। आई-टू-यु-टू (भारत, इजरायल, अमेरिका और यूएई) नामक एक नया संगठन भारत के माध्यम से बना। यहाँ तक कि चीन को काउंटर करने के लिए, चीन के बेल्ट एडं रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए जी-20 में नया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पश्चिमी एशिया के देशों और अमेरिका के माध्यम से उसको अमली जामा पहनाया है, इससे भारत की मजबूत वैश्विक लीडरशिप का पता चलता है। पश्चिमी एशिया के मुल्कों में हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, काफी मुस्लिम राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं। इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं लेकिन फिर भी भारत इजराइल को भी समझा रहा है। भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है लेकिन भारत सिर्फ इतना चाहता है कि विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से हो और फिलिस्तीन भी रहना चाहिए और इजरायल भी रहना चाहिए। इससे पहले ये सभी चीजें नजर नहीं आती थी और कहीं न कहीं भारत पिछलग्गू राष्ट्र नजर आता था। यदि ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो 2047 तक भारत का विकसित भारत बनने का सपना जल्द ही पूरा होगा, जिस बात पर (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने भी बल दिया है।

यहाँ गौरतलब यह है कि पिछले कई सालों से चीन की अनैतिक गतिविधियां हिंद महासागर में बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से चीन दक्षिण सागर से अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है और अवैध कब्जा करते जा रहा है उसी का विस्तार वो हिंद महासागर में भी चाहता है। इसी वजह से कई बार देखा गया है कि चीन अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी पर लगातार काम कर रहा है। देखने वाली बात ये है कि हिंद महासागर में जो छोटे-छोटे मुल्क हैं उनके साथ भारत अपने रिश्ते कैसे बना रहा है या फिर चीन उनको कैसे अपने जाल में फंसा रहा है, इस पर भी पिछले कई सालों से भारत की पैनी नजर है। भारत नहीं चाहता कि चीन हिंद महासागर में अपने पैर फैलाए। कई बार चीन ने हिंद महासागर के अंतरराष्ट्रीय वाटर में भी अपने 'शोध' के लिए जहाज उतारे, उस पर भी भारत ने चिंता एवं प्रतिक्रिया लगातार जताई है। भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी चीन के इस रवैये के बारे में पुख्ता जानकारी दी है। भारत की नजर लगातार चीन पर बनी हुई है क्योंकि हिंद महासागर में चीन क्या करना चाहता है, उसके मंसूबे क्या हैं, उससे भारत भली-भांति परिचित है।

जिस प्रकार से चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपना रुतबा बढ़ाया है, वहाँ पर अन्य देशों का समुद्र पर दावा होने के बावजूद, उनको भी वहाँ से खदेड़ने का काम किया है। भारत को और मुखर होने की आवश्यकता है। यह सिर्फ कागजी कार्रवाई या चिंता जताने से समाधान नहीं होगा, चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत समय पहले आईएनएस ऐरावत एक भारत का जहाज दक्षिण चीन की यात्रा पर था, चीन के जहाजों ने उसे चेज किया और वहाँ से बाहर जाने के लिए दबाव डाला। ऐतिहासिक काल से ही हिंद महासागर में भारत का रुतबा रहा है। अब जरूरी है उस रुतबे को दिखाने की, क्योंकि चीन जैसे विस्तारवादी देशों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। श्रीलंका यह बात समझ चुका है कि चीन एक विस्तारवादी देश है। मालदीव को भी यह समझने की जरूरत है कि मालदीव का आकार-प्रकार बहुत छोटा है, ऐसे में चीन जैसे देश उनको कब खत्म कर देंगे। चीन ने श्रीलंका की आर्थिक मदद की और बाद में श्रीलंका जब दिवालियेपन के कगार पर खड़ा था, तो भारत ने ही श्रीलंका को बचाया है, कई देश अब चीन की विस्तारवादी नीतियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं।

अमेरिका के नौसेना के भी अड्डे हिंद महासागर में हैं। अमेरिका आज से नहीं कई सालों से नजर रखे हुए है, क्योंकि हिंद महासागर से आज भी 90 प्रतिशत विश्व व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। एक महत्त्वपूर्ण शिपिंग लेन हिंद महासागर से होकर जाता है। अमेरिका लगातार पिछले कई सालों से भारत को आगाह कर रहा है, भारत के साथ उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की

है, कहीं न कहीं अमेरिका यह चाहता है कि भारत की क्षमता में वृद्धि की जाए। अमेरिका का भी मानना है कि यदि चीन पर लगाम लगानी है तो इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। आने वाले समय में भारत के नेतृत्व में हिंद महासागर में चीन पर लगाम लगाई जा सकेगी। जिसमें अमेरिका के साथ-साथ फ्रांस का और अन्य देशों का समर्थन भारत को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा।

पिछले कई सालों से चीन अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण पर लगा हुआ है और इसी वजह से रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहा है। इस बार उन्होंने अप्रत्याशित बढ़ोतरी करते हुए 7-8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसमें चीन ने मुख्य ध्यान मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और हिंद महासागर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया है। लेकिन भारत के लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि इस तरह का अंदेशा भारत को पिछले कई सालों से था। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपने डिफेंस आधुनिकीकरण पर बल दिया है। भारत ने अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी अच्छा कर लिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए पहले बोला करते थे कि भारत की सीमा से जो गाँव लगते थे उनका आखिरी गाँव बोला जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने वह नॅरेटिव बदल दिया है और बोला है कि वह भारत का पहला गाँव है। इससे गाँव का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है साथ ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा किया ताकि डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत हो।

इसी के मद्देनजर बहुत सालों तक भारत के दो ही नौसेना के प्रमुख अड्डे हुआ करते थे, इस्टर्न कमांड एवं वेस्टर्न नेबल कमांड। उसी को ध्यान में रखते हुए अंडमान और निकोबार को अपना तीसरा मुख्य सैनिक अड्डा बनाया। अभी हाल ही में हम लोगों ने लक्षद्वीप को चौथा नौसेना का सैनिक अड्डा बनाने की पूरी तैयारी की है। उसी के मद्देनजर भारत में पूरी तरह से लक्षद्वीप का कायाकल्प किया है और आने वाले समय में भारत कई और अत्याधुनिक, खुद से बने हुए एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या भी बढ़ने वाली हैं जिसे अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप पर स्थापित किया जाएगा।

अभी हाल ही में भारत में आईएनएस जटायु को लक्षद्वीप में स्थापित किया है उससे पहले उन्होंने भारत आईएनएस द्वीप रक्षक को भी स्थापित किया था। यह आईलैंड मालदीव से सिर्फ 564 किलोमीटर की दूरी पर है और यह दूरी समुद्र में लगभग ना के बराबर है। जिस प्रकार से चीन समर्थित मोइज्जू की सरकार मालदीव में आई है और आते ही उन्होंने जो प्रो चीन स्टैंड लिया है, एंटी इंडिया स्टैंड लिया है, इसी वजह से लक्षद्वीप को प्रमोट किया जा रहा है और यह एक नए सैनिक अड्डे के रूप में उभर रहा है। भारत के नौसेना के प्रमुख आर. हरि ने 6 मार्च, 2024 को कहा कि आईएनएस जटायु सागर में भारतीय आंख और कान बनकर उभरेगा और हमें अब यह पता रहेगा कि इस एरिया में क्या-क्या गतिविधियाँ चल रही है। वैसी गतिविधियां जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हैं, एक अच्छा रोल प्ले करेगा। अब भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वो अब अरब सागर में आंख, नाक और कान बढ़ा दे। ताकि भारत चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी लगाम लगा पाए और अभी वर्तमान लाल सागर को लेकर विवाद चल रहा है हूती विद्रोही अटैक कर रहे हैं जिससे भारत भी प्रभावित हो रहा है तो ऐसे में एक अच्छा नेबल बेस और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो यानि मुंबई एवं लक्ष्यद्वीप का नेबल कमांड भारत के प्रजेंस को अरब सागर में और पुख्ता करेगा। भारत सजग है और चीन या पाकिस्तान से आने वाली सभी चुनौतियों के लिए भारत तैयार हो चुका है।

भारतीय नौसेना कई सालों से अपने आधुनिकीकरण के लिए रूस पर निर्भर था। रशिया भारत का एक पुराना और टाइम-टेस्टेड मित्र है। इसके बावजूद भी भारत ने डिफेंस को लेकर विविधीकरण किया है। सिर्फ एक राष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत को कई और राष्ट्रों से भी अपने डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने की तरफ़ रुख किया है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी की बात भी की है, यानी की कुछ साल पहले भारत सिर्फ हथियार खरीदता था लेकिन भारत अब खुद भी हथियारों का निर्माण कर रहा है और उसे बेच भी रहा है। आने वाले समय में या वर्तमान में भी भारत ने रशिया के साथ-साथ

अमेरिका या कई और बड़े देशों को चैलेंज प्रस्तुत किया है कि अब आप डिफेंस के इस बाजार में अकेले नहीं है, भारत भी है जिसके पास कई अत्याधुनिक हथियार हैं जो वह बेच सकता है। अब भारत दो से तीन एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जो कि पूरी तरह से स्वदेशी हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन एवं एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारत बना रहा है, जल्द ही नौसेना में वो कमीशन होते जाएंगे।

भारत के रक्षा निर्यात में बेतहाशा वृद्धि हुई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारत का रक्षा निर्यात बीते वित्त वर्ष (2023-24) में 21,083 करोड़ का हुआ है। जिसमें सिर्फ एक ही वित्त वर्ष में 32.5 प्रतिशत का उछाल आया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि भारत ने 84 देशों, जिसमें रूस, यूएई, सऊदी-अरब, इजरायल, इटली, आदि शामिल हैं को अपने रक्षा उत्पाद बेचकर यह चमत्कारिक लक्ष्य प्राप्त किया है। भारत की रक्षा नीति में नरेंद्र मोदी की सरकार में काफी बदलाव हुआ है।

भारत 2014 से पहले भी रक्षा निर्यात किया करता था लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की कई सकारात्मक नीतियों की वज़ह भारत की डिफेन्स इंडस्ट्री को मजबूती मिली है एवं उसी के माध्यम से ही भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है, भारत की आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आई है एवं देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। पिछली सरकारों की तुलना में मोदी सरकार ने रक्षा निर्यात बढ़ाने के लिए न सिर्फ रक्षा निर्माण क्षेत्र को प्रेरित किया बल्कि तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने की सुविधाएँ भी बढ़ाई गई हैं। साथ ही साथ सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए उत्साहजनक वातावरण बनाया गया है। इसी पॉजिटिव वातावरण की वजह से इन कंपनियों ने अन्वेषण को अधिक प्रभावशाली बनाया एवं गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखते हुए भारत के रक्षा उपकरणों को तकनीकी विश्वसनीयता प्रदान की। जिसके माध्यम से आज भारत एक सक्षम रक्षा निर्यातक एवं आपूर्तिकर्ता देश के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो गया है।

भारत का रक्षा निर्यात अब धीरे-धीरे विश्व के कोने-कोने तक अपनी पहुँच बना रहे हैं। देश के निर्यात किए उत्पाद इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, यूएई, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी-अरब, मिस्र, इजरायल, स्पेन, चिली समेत कई अन्य देशों तक पहुँच रहे हैं। भारतीय रक्षा उत्पादों की माँग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। यहाँ जानने वाली बात यह भी है कि जबसे मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया एवं स्वदेशी को प्रोमोट करने की वकालत की तब से ही रक्षा निर्यात में अब बेतहाशा मुनाफा कमा रहा है। साथ ही साथ भारत के पूर्ण रूप से स्वदेश में ही विकसित हथियारों की विश्वसनीयता एवं साख भी बढ़ी है।

भारत ने ब्रह्मोस के साथ कई अत्याधुनिक मिसाइलें भी बनाई हैं जिसका नौसेना वर्जन भी है और उनको कमीशंड भी किया जा रहा है और अब भारत उनको वियतनाम, फिलीपींस एवं अन्य देशों को भी बेचा जा रहा है। क्योंकि वियतनाम, थाइलैंड फिलीपींस चीन के चैलेंज को महसूस कर रहे हैं। अभी हाल ही में पूर्णतया स्वदेशी अग्नि-5 का भी सफल परीक्षण भारत ने कर लिया है जिसने चीन की नींदें उड़ा दी हैं। भारत को चाहिए कि अपने मित्र देशों को भी इस तरह की तकनीक से वाकिफ करवाये। भारत के पास विशेषज्ञता है और वो इस मामले में एक लंबी एवं विश्वसनीय भूमिका निभा सकता है। अब भारत ने रक्षा स्वावलंबन में अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है और आने वाले समय में भारत की धमक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और भी बढ़ने वाली है। अगर भारत लगातार अपनी रक्षा निर्यात की नीति पर ऐसे ही ध्यान देता रहा तो जल्द ही भारत विश्व की नंबर एक अर्थव्यवस्था बन जाएगा क्योंकि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में ही यह पोटेंशियल है कि वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जमीन से आसमान तक कुछ ही क्षणों में ले जा सकता है। ❑

उन्नत भारत और समरस समाज

प्रो. संतोष कुमार प्रजापति
आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय),
बिलासपुर (छ.ग.)

उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की यात्रा में इस देश की जो सबसे बड़ी विशेषता दिखाई देती है वह है 'वैविध्य'। इसी का अवलोकन कर किसी विद्वान ने कहा है- 'यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह दिखाई देता है।' अपने ऊपरी कलेवर में निश्चित रूप से यह बात सही भी दिखाई देती है, लेकिन जैसे शरीर के प्रत्येक अंग ऊपर से भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं पर उनके रक्त संचार को बनाये रखने वाला रक्त परिवहन तंत्र आंतरिक रूप से एक होता है, जैसे नदियों का अपवाह तंत्र मिट्टी का भेद नहीं मानता वैसे ही इस देश की मूल आत्मा एक है। हम आरंभ से ही विराट दर्शन के पक्षपाती रहे हैं। 'माता भूमि : पुत्रोऽहम् पृथिव्या:', 'वसुधैव कुटुंबकम्', 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' आदि चिंतन मणियाँ इसी दृष्टि एवं गहन पारंपरिक अनुभवों का परिणाम हैं। भारतीय मनीषा के चिंतन स्रोत उपनिषद् इसके प्रमाण हैं। ईशावास्योपनिषद का षष्ठ मंत्र द्रष्टव्य है -

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो मा विजुगुप्सते॥

(जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इस ('सार्वात्म्यदर्शन') के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता।)

वस्तुत: ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र ही 'ईशावास्यामिदं सर्वम्' (सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है।) की उद्घोषणा करता है। जिस अनुभूति को पुरुषार्थ से प्राप्त करने की बात छठे मंत्र में ही की गयी है। जाहिर है कि दृष्टि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ तो आवश्यक होगा ही।

हमारे यहाँ एक उक्ति प्रचलित है 'जन्मना जायते शूद्रो, संस्कारा- द्द्विजुच्यते'। यदि इसकी विवेचना में जायें तो, हमारी परंपराओं में जन्मना कुछ भी निर्धारित नहीं होना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है। बल्कि संस्कार अर्थात् पुरुषार्थ से जो अर्जन किया जाए उससे व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होना चाहिए। इसका स्पष्ट निर्देश श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण करते हैं -

चातुर्वर्ण्यम् मया स्त्रष्टम्
गुणकर्म विभागश:।

(अर्थात् मेरे द्वारा चारों वर्णों की रचना गुण और कर्म के अनुसार की गयी है।)

प्रसिद्ध निर्गुण संत कबीर ने भी देसभाषा में अत्यंत सरल शब्दों में इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया है-

जहवाँ से आयो अमर वह देसवा
बाह्मन छत्री न सूदबइसवा।

ये तो हुई आदर्श स्थिति, जहाँ हमारी सभ्यता को पहुँचना है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि हमारा समाज अनेक

विसंगतियों का शिकार रहा है। मध्यकाल की साम्राज्यवादी परिस्थितियों एवं आधुनिक काल की उपनिवेशवादी नीतियों के कारण सामाजिक विभेद की रूढ़िवादी समस्याओं का सामना हमारे देश को लंबे समय तक करना पड़ा है। मध्यकालीन सत्तावादी लोलुपता एवं उससे उपजे विषमतावादी सोच की पड़ताल करते हुए लोकदर्शन के अद्भुत चितेरे–तुलसीदास ने उत्तरकांड में लिखा है –

मोह सकलव्याधिह्न कर मूला।
तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला।
काम, वात, कफ लोभ अपारा।
क्रोध पित्तनित छाती जारा।।
अहंकार अति दुखद डमरूआ।
दंभ कपट मदमान नेहरूआ।।
तृषना उदरवृद्धि अति भारी।
त्रिविध ईषना तरून तिजारी।।

(सब रोगों की जड़ मोह है। उन व्याधियों से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गाँठ का रोग है। दंभ कपट, मद और यान नसों के रोग हैं। तृष्णा जलोदर रोग है। तीन प्रकार (पुत्र, धन और मान) की बल इच्छाएँ प्रबल तिजारी हैं।)

हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद कामायनी में लिखते हैं–

तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में,
कुछ सत्ता है नारी की।
समरसता है संबंध बनी
अधिकार और अधिकारी की।।

उपर्युक्त दोनों कवियों की इतनी पंक्तियाँ यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि समरसता के अभाव एवं व्यक्तिगत, स्वार्थी महत्त्वाकांक्षाओं के प्रभाव में हमारे समाज की स्थिति क्या है? किसी समय के प्रगतिशील मूल्य किसी दूसरे काल–खण्ड में बहुधा रुढ़ि बन जाते हैं। कुछ सामाजिक न्याय के मामले में भारतीय समाज के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। वंशानुगत मोह के कारण कहीं न कहीं कालांतर में हमारे समाज में जाति, संप्रदाय, पंथ, क्षेत्र, भाषा आदि तमाम कुंठित श्रेष्ठताबोध की ग्रंथि बनी; जिसे उपनिवेशवाद के कुचक्रों ने खाद – पानी देकर अपने हित साधने के लिए और बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने भी इसकी तरफ ध्यान दिलाया था कि ''एक तरफ तो हम इतने महान धर्म के अनुयायी हैं कि पेड़–पौधों एवं समस्त जंतुओं में ईश्वर के दर्शन करते हैं और दूसरी ओर हम इतने निम्न धर्म के अनुयायी हैं कि अपने ही बंधु–बांधव, मनुष्य जाति को कीड़ों–मकोड़ों से भी बदतर समझते हैं''। स्त्रियों की दशा पर भी ध्यान दिलाते हुए उन्होने कहा कि 'जिस समय अमेरिका में महिलाएँ आत्मनिर्भर होकर लक्ष्मी स्वरुपा हैं उस समय हमारे देश की महिलाएँ अल्पायु में ही बच्चे पैदा करने की साधन बना दी गयी हैं' आजादी के सतहत्तर साल बाद भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के पश्चात जो सामाजिक परिवर्तन हो जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या' नामक निबंध में इस ओर ध्यान दिलाया है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपने से नीचे की एक जाति ढूँढ़ ही लेता है। इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक के मध्य में इस महान देश के भीतर विभिन्न जातीय संगठनों के बड़े–बड़े होर्डिंग्स आज भी इसके साक्षी हैं। हालाँकि यह अनायास नहीं है। हम आज भी उस औपनिवेशिक सोच से बाहर नहीं निकल पाये हैं जिसका बीजारोपण अंग्रेजों ने पूरे षड्यंत्र के तहत अपने शासन काल में किया था। 'भारत विखंडन' नामक पुस्तक में राजीव मल्होत्रा ने इसकी पड़ताल भी की है– ''एक ओर काल्डवेल ने द्रविड़

समरस समाज की संकल्पना मानवता के चरम उत्कर्ष की संकल्पना है। यह जड़ से चेतन की यात्रा है जहाँ मनुष्य का मनुष्यता पर दृढ़ विश्वास होता है। चूँकि भारत विश्व का सबसे प्राचीन देश है इसलिए मानवता को मजबूत करने वाले मूल्यों की ओर अग्रसर होना इसका दायित्व भी है। हम भारत के निवासी हैं इसलिए इसे पूरा करना प्रत्येक भारतवासी का भी दायित्व बनता है। इसी से भारत अपने परम वैभव को प्राप्त कर सकेगा एवं विश्व गुरु की राह में आगे बढ़ेगा।

पहचान पर इस उद्देश्य से बल दिया कि उन्हें भारतव्यापी हिंदू समुदाय से अलग किया जा सके और दूसरी ओर उन्होंने द्रविड़ों को आर्यों से नीचे माना, क्योंकि आर्यों को नस्ली तौर पर यूरोपीय समुदाय से निकला हुआ माना गया था। उनके अनुसार, द्रविड़ों ने अपनी 'मानसिक संस्कृति' और 'उच्च सभ्यता' श्रेष्ठतर आर्यों से प्राप्त की थी। लेकिन उन्होंने आर्यों की बराबरी प्राप्त नहीं की।'' ध्यातव्य है कि यह आर्य-द्रविड़ सिद्धांत औपनिवेशिक अध्ययन पद्धति द्वारा जानबूझकर गढ़ा गया सिद्धांत है जिससे भारत को विखंडित बनाये रखने में पर्याप्त सहायता मिली है।

यह तो हुई अतीत की बात। अब बात करते हैं भविष्य के भारत की। वस्तुत: उन्नत भारत, की उर्ध्वमुखी भारत की संकल्पना क्या होगी? यहाँ पर भी हमें अतीत से ही सबक लेना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का जीवंत देश है। जैसा कि इकबाल ने कहा है-

यूनान मिश्र रोमां सब मिट गये जहाँ से आखिर कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी।।

तो निश्चित रूप से हमें विचार करना पड़ेगा कि आखिर वह हमारी हस्ती में वह कौन-सा तत्त्व है जो हमें अभी तक जिंदा रखे हुए है? तो हम पायेंगे कि 'समन्वय की विराट चेतना' ही इसका आधार है। समरसता जिसका प्राण है। भारत के जितने भी महान शासक यहाँ हुए हैं सबने इसे अंगीकार किया है। यह समन्वयन की भावना जिस काल में जितनी विस्तृत हुई है वह राजा उतना ही स्थायी और वह राज्य उतना ही विकसित हुआ है। उदाहरणस्वरूप हम चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यनीति लें, अशोक महान की धम्मनीति लें या भारतीय जनमानस के लोकनायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को लें। एक अत्यंत सामंती समय में लोकनायक राम का चरित्र गढ़ते समय तुलसीदास ने इसी समरस समाज की परिकल्पना की है। वनवास के समय चित्रकूट सभा में इसकी बानगी भी देखने को मिलती है। जहाँ तत्कालीन राज-दरबारों के अहंकार के बरक्स वन में राम-दरबार स्थापित होता है। राजदरबार में एक ही पंक्ति में राजा जनक, गुरु वशिष्ठ, निषादराज गुह अयोध्या से आगत समस्त प्रजा एवं सहचर वनेचर सभी एक पंक्ति में भोजन करते हैं। इससे भी आगे बढ़कर श्रीराम द्वारा भीलनी शबरी के प्रेमभरे जूठे

बेर खाना समरसता का अनुपम उदाहरण है। वानर जाति के समस्त समुदाय एवं राक्षस जाति के भी श्रेष्ठ लोगों (विभीषण) का विश्वास जीतना भी हम इसी कड़ी में देख सकते हैं। द्वापर में जननायक श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन के अहंकार युक्त भोज्य पदार्थों को छोड़? कर दासी पुत्र विदुर के यहाँ भोजन करना भी इसी समरसता का अनुपम उदाहरण है। केवल जाति या वर्ण के स्तर पर नहीं बल्कि स्त्री-पुरुष संबंधों में भी इस समरसता की दरकार हमेशा रहेगी। स्त्री शक्ति मातृ शक्ति है। बिना मातृ शक्ति के उत्थान के एक समरस समाज की संकल्पना बेईमानी है। इतिहास गवाह है कि हमारे यहाँ सीता और शकुंतला जैसी स्वाभिमानी माताएँ रहीं हैं। जिन्होंने अपने दम पर चक्रवर्ती सम्राटों को तैयार किया है। आधुनिक युग में भी स्त्री शक्ति के इस पौरुष को हम नकार नहीं सकते हैं।

वस्तुत: समरस समाज की संकल्पना मानवता के चरम उत्कर्ष की संकल्पना है। यह जड़ से चेतन की यात्रा है जहाँ मनुष्य का मनुष्यता पर दृढ़ विश्वास होता है। चूँकि भारत विश्व का सबसे प्राचीन देश है इसलिए मानवता को मजबूत करने वाले मूल्यों की ओर अग्रसर होना इसका दायित्व भी है। हम भारत के निवासी हैं इसलिए इसे पूरा करना प्रत्येक भारतवासी का भी दायित्व बनता है। इसी से भारत अपने परम वैभव को प्राप्त कर सकेगा एवं विश्व ज्ञान महाशक्ति की राह में आगे बढ़ेगा। समरसता की मूल चेतना को भाँपते हुए एवं राष्ट्र के विकास में इसकी आवश्यकता को चिन्हित करते हुए प्रसिद्ध हिन्दी कवि जयशंकर प्रसाद ने इसीलिए लिखा है –

समरस थे जड़ या चेतन,
सुंदर साकार बना था।
चेतनता एक विलसती थी,
आनंद अखंड घना था।।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह समरसता आनंदवाद का मार्ग है जो कि भारतीय दर्शन, चिंतन एवं जीवन पद्धति का लक्ष्य है। ❑

भारतीय वाङ्मय में सामाजिक समरसता

सत्येश भट्ट
जनसंपर्क अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिलासपुर (छ.ग.)

भारत की इस गौरवशाली एवं वैभवशाली ज्ञान परंपरा की तपोभूमि को ऋषि, मुनियों, संतों, आध्यामिक गुरुओं और राष्ट्रभक्तों ने अपने ओजस्वी विचारों से सींचा है। भारत भूमि ने समूचे विश्व को एक परिवार के रूप में स्वीकार करते हुए वसुधैव कुटुंबकम् के समरसता के संदेश को प्रसारित किया है। पुरातन भारतीय संस्कृति में कभी भी किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया गया है। सनातन संस्कृति में जाति, वर्ण, वर्ग, समुदाय, कुल, वंश, रंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव जैसी किसी व्यवस्था के प्रचलन का प्रमाण नहीं मिलता। गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, "मैंने गुण व कर्म के आधार पर इस सृष्टि में चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) की रचना की है– चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।" समतापरक सुसंस्कृत समाज का निर्माण, संचालन एवं अस्तित्व किसी व्यक्ति, जाति, वर्ण, वर्ग या समुदाय विशेष के योगदान से नहीं होता है। समाज की संपूर्णता एवं सजीवता के निमित्त प्रत्येक व्यक्ति की खुशहाली, सहभागिता एवं समर्पण बेहद जरूरी है। हमारी ज्ञानात्मक चेतना के अक्षय स्रोत वेदों में भी संपूर्ण सृष्टि को एक परिवार माना गया है। इनमें मेरे–तुम्हारे जैसे संकुचित भावों के लिए कोई स्थान नहीं है–

अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।

भारतीय सामाजिक समरसता यहाँ की संस्कृति का मूल आधार है इसलिए विश्व की सभी संस्कृतियों ने भारत से मानवीय मूल्य एवं राष्ट्रवाद को सीखा है। उत्तर से दक्षिण तक पूरब से पश्चिम तक भाषा अलग, पंथ अलग, परम्पराओं, विभिन्नता, रहन–सहन, खान–पान, त्योहारों में विभिन्नता के बावजूद विचारों मे एकता भारत की सामाजिक समरसता का प्रतीक है। भारतीय समाज में विभिन्न संस्कृतियों के मिलने के बाद भी अपनी मूल पहचान विश्व कल्याण एवं विश्व बंधुत्व की भावना को बरकरार रखा है जिसके कारण आज भी भारतीय संस्कृति जीवंत बनी हुई है। "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु॥" अर्थ है यह भूमि (पृथ्वी) हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं अर्थात् पूरे विश्व के लोग हमारे भाई बंधु हैं। 'पर्जन्य' अर्थात् मेघ हमारे पिता हैं। और ये दोनों मिल कर हमारा 'पिपर्तु' अर्थात् पालन करते हैं। प्राचीन समय मे सनातन समुदाय के जीवन की आचार संहिता वेद, पुराण, उपनिषद, संहिता, रामायण, और गीता थे जिनमे मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भी तरह का भेद भाव नहीं था। प्राचीन काल का समाज अत्यंत वैज्ञानिक एवं समता मूलक मूल्यों पर आधारित था। कर्मों के आधार पर वर्ण विभाजित किए गये थे। मनुष्य, वन, पृथ्वी एवं अन्य जीवों को समान महत्त्व देना और इनकी उपयोगिता का वर्णन वेद एवं उपनिषद मे किया गया है।

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।

वनस्पतय: शान्तिर्विश्वेदेवा:
शान्तिर्ब्रह्म शान्ति:
सर्वं शान्ति:, शान्तिरेव शान्ति:
सा मा शान्तिरेधि॥
ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥

यजुर्वेद के इस शांति पाठ मंत्र में सृष्टि के समस्त तत्त्वों व कारकों से शांति बनाये रखने की प्रार्थना करता है। इसमें यह कहा गया है कि लोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हों, जल में शांति हो, औषध में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी देवतागणों में शांति हो, ब्रह्म में शांति हो, सब में शांति हो, चारों और शांति हो, शांति हो, शांति हो, शांति हो। यह उदाहरण सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति में देखने को मिलेगा जिसमें सभी से शांति धारण करने की स्तुति की गयी है। धीरे-धीरे समय में बदलाव होता गया नए विचारक और चिंतकों में बुद्ध और जैन विचार मतावलंबी हुए जिन्होंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि विषयों पर जोर दिया और समतामूलक समाज का निर्माण होने में अपना योगदान दिया। मध्यकाल तक आते आते भारत में बाह्य आक्रमण शुरू हुए कुछ आक्रांता थे जिनका मकसद धन-दौलत लूटना और अपने देश वापस चले जाना था। लेकिन कुछ आक्रमणकारियों ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इन शासकों ने भारतीय संस्कृति को अविच्छिन करने का प्रयास किया परंतु भारतीय समाज की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि दो संस्कृतियों के आपसी टकराव के बावजूद भी भारतीय संस्कृति ने अपने मूल स्वरूप मे कोई बदलाव नहीं होने दिया तो इसका सबसे बड़ा कारण था मध्यकालीन संत, ऋषि, मंदिर, मठ पुजारी जिन्होंने अपनी संस्कृति को मजबूती के साथ लोक कल्याण मे लगाए रखा जिसके कारण लोगों का विश्वाश उठा नहीं। कबीरदास, मीरा, रैदास, तुलसीदास, जायसी, सूरदास, जैसे महान संतों की बाड़ी ने मनुष्यता के बीच फैल रहे भेद-भाव को दूर किया। कबीर ने कहा कि -

कबीरा कुवाँ एक है, पानी भरै अनेक।
बर्तन में ही भेद है, पानी सबमें एक।।

मध्यकालीन संत तुलसीदास का रामचरितमानस समन्वयशीलता का अद्‌भुत ग्रंथ है। तुलसीदास ने कहा है कि 'राम कथा जग मंगल करनी' यह कथा संसार के कल्याण के लिए लिखी गयी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि 'जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहँ विपत्ति निदाना' वहीं सूरदास जीवों की एकता पर बल देते हुए कहते हैं कि -

बैठक सभा सबै हरिजु की
कौन बड़ों को छोट।
सूरदास पारस के परसे
मिटत लोह के खोट।।

आधुनिक काल तक आते-आते सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक दृष्टिकोणों में बदलाव हुआ समाज में नए विचार, तकनीकी, विज्ञान का उदय हुआ जिसके कारण सामाजिक स्वरूप में बदलाव होना आवश्यक था। आधुनिक काल में स्वामी विवेकनाद, राजाराम मोहन राय, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मलवीय जैसे प्रगतिशील चिंतकों ने समाज को एक नयी दिशा एवं रास्ता प्रदान किया।

समाज एक गतिशील संस्था है जो शाश्वत प्रगति एवं भाई चारे के पथ पर अग्रसर होकर अपने समस्त घटकों की खुशहाली सुनिश्चित करती है। भारतीय संस्कृति विश्वकल्याण, समन्वयशीलता, सहिष्णुता, प्रेम, सत्य, अहिंसा के लिए विश्वविख्यात रही है इसमें सभी के कल्याण की भारतीय सस्कृति की विश्व में पहचान जिन बातों से है, वे हैं - हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों जैसे 'सत्यमेव जयते', 'अहिंसा परमो धर्म:', 'परहितसरिस धर्म नहिं भाई', 'वसुधैव कुटुंबकम्', 'अतिथि देवो भव:', 'जननी जन्मभूमिश्च', 'स्वर्गादपि गरीयसी' जैसे उद्‌घोष के साथ आगे बढ़ी जिस कारण विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति होने का गौरव प्राप्त है और सामाजिक समरसता का बेजोड़ उदाहरण है।

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिन:
सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद्दु:खभाग्भवेत्।

भारतीय समाज में सभी के सुखी होने, सभी के निरोगी होने, सभी के कल्याण की कामना की गयी है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय समाज, अपने आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, वैचारिक एवं मानवीय मूल्यों के लिए विश्व के समक्ष सर्वश्रेष्ठ है तो इसके पीछे का कारण यहाँ के लोगों की समरसता पूर्ण जीवन शैली है जिसमें सभी को समान अवसर प्राप्त है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि भले ही मैं ईसाई हूँ लेकिन मैंने हिंदू धर्मग्रंथों का अध्ययन किया है और इसमें संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। यह सदा सहिष्णुता, विविधता व समावेशी मूल्यों का पक्षधर रहा है। जिसने भारत को दुनिया में विशिष्ट पहचान दी है। ❑

भारतीय समाज में सभी के सुखी होने, सभी के निरोगी होने, सभी का के कल्याण की कामना की गयी है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय समाज, अपने आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, वैचारिक एवं मानवीय मूल्यों के लिए विश्व के समक्ष सर्वश्रेष्ठ है तो इसके पीछे का कारण यह के लोगों की समरसता पूर्ण जीवन शैली है जिसमें सभी को समान अवसर प्राप्त है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि भले ही मैं ईसाई हूँ लेकिन मैंने हिंदू धर्मग्रंथों का अध्ययन किया है और इसमें संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। यह सदा सहिष्णुता, विविधता व समावेशी मूल्यों का पक्षधर रहा है। जिसने भारत को दुनिया में विशिष्ट पहचान दी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियाँ एवं समाधान

डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता

प्रवक्ता, अग्रवाल महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगापुर सिटी

जिला- सवाई माधोपुर (राज.)

इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारत की वर्तमान चुनौतियों, समस्याओं और भविष्य की जरूरतों की पूर्ति में सहायक होगा। शिक्षा की प्रक्रिया में कई कारक शामिल होते हैं, जिनमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। इक्कीसवीं सदी के भारत की शिक्षा नीति के स्वरूप को दर्शाने वाली इस शिक्षा नीति में कुल 27 प्रमुख बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की गई है। इन 27 बिंदुओं में से बिंदु संख्या 15 में शिक्षक शिक्षा से संबंधित महत्त्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं। वर्तमान शिक्षा नीति का शुभ परिणाम, इसे अमल में लाने के लिए तैयार की जाने वाली कार्य-योजना की उत्कृष्टता, संबंधित कार्य योजना पर अमल करने की दृढ़ इच्छाशक्ति और शिक्षा प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की प्रतिबद्धता पर निर्भर होगा।

शिक्षा प्रत्येक राष्ट्र की एक अनिवार्य आवश्यकता है। मानव की उपलब्धियों में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसलिए प्रत्येक देश अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में समयानुसार सुधारात्मक परिवर्तन करता है। यह बात भारत पर भी लागू होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, लक्ष्मी शंकर मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) और सन् 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना, इस संबंध में शिक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है। सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राममूर्ति की अध्यक्षता में समीक्षा समिति (1992) की सिफारिशों ने भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा को सुधारने और आधुनिक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई यह शिक्षा नीति एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारत की वर्तमान चुनौतियों, समस्याओं और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगा। शिक्षा की प्रक्रिया में कई कारक शामिल होते हैं, जिनमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। इक्कीसवीं सदी के भारत की शिक्षा नीति के स्वरूप को दर्शाने वाली, इस शिक्षा नीति में कुल 27 प्रमुख बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की गई है जिसमें बिंदु क्रमांक 15 में शिक्षक शिक्षा से संबंधित महत्त्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं।

शिक्षक शिक्षा – शिक्षक शिक्षा, दो शब्दों, शिक्षक एवं शिक्षा का समेकित रूप है, जिसमें शिक्षक शब्द का अर्थ सीखने एवं सिखाने वाले के रूप में तथा शिक्षा शब्द

का अर्थ अध्यापन एवं ज्ञानाभिग्रहण के रूप में किया गया है। यहाँ दोनों ही शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत के 'शिक्ष' धातु से हुई है, जिसका शब्दकोशीय अर्थ है, सीखना, अध्ययन करना तथा ज्ञानार्जन करना। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा का सामान्य अर्थ उस व्यक्ति की शिक्षा से है, जो सीखने एवं सिखाने का कार्य करता है। शिक्षक का समानार्थी शब्द गुरु है, जो प्राचीन और वर्तमान भारत में अध्यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षकों का प्रशिक्षण गुरुकुलों में स्वाभाविक रूप से अध्ययन-अध्यापन के दीर्घकालिक अनुभव के आधार पर होता था, जिसमें प्रज्ञा के साथ ही साथ उत्तम चरित्र का होना अनिवार्य शर्त थी। समयांतर में समाज में औपचारिक शिक्षा की बढ़ती माँग ने पेशेवर शिक्षकों के विकास की अवधारणा को बल दिया और शिक्षक शिक्षा की औपचारिक शुरुआत के लिए शिक्षक संस्थानों की स्थापना हुई। शिक्षक शिक्षा, शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रम में उन युवाओं हेतु एक व्यावसायिक तैयारी है जो शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं। यह व्यावसायिक तैयारी अनेक प्रकार की हो सकती है, परंपरागत अथवा वस्तुनिष्ठता से युक्त एवं आबद्ध, जिसका लक्ष्य है- विद्वता एवं खुलेपन के लिए समर्पित प्रगतिशील शिक्षक वर्ग की उपलब्धि, जो विद्यार्थियों की व्यक्तिपरकता अथवा आत्मनिष्ठा के प्रति अभिमुख हो।

शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता - प्राचीन काल से ही शिक्षक का समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान है, जो उसके समाज के प्रति निर्वहन किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण कर्तव्यों के संदर्भ में देखा जाता है। प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक के कर्तव्य को इंगित करते हुए अलतेकर लिखते हैं कि, ''अध्यापन के अतिरिक्त आचार्य के और भी कर्तव्य होते हैं। उसे शिष्य का मानस पिता माना गया था। अतः नैतिक दृष्टि से शिष्य के समस्त दोषों का उत्तरदायित्व उस पर था। शिष्य के चरित्र का सर्वदा ध्यान रखना उसका कर्तव्य था।'' राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक को समाज की स्थिति का मानदंड मानते हुए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि समाज में शिक्षक की स्थिति समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों की परिचायक है, क्योंकि कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षक से अधिक विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षक शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाए तथा ज्ञानी, कुशल, दक्ष, संवेदनशील एवं चरित्रवान शिक्षकों का विकास किया जाए।

सीखना एवं सिखाना यद्यपि एक-दूसरे के निकट है, किंतु दोनों में प्रक्रियागत एक महत्त्वपूर्ण भेद है, जहाँ सीखने की प्रक्रिया भूल-सुधार एवं सतत अभ्यास के सिद्धांत का अनुगमन करती है, वहीं सिखाने की प्रक्रिया में भूल एवं सुधार के सिद्धांत को लागू करना एक गंभीर परिणाम को जन्म दे सकता है। इसलिए इसमें गहन शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की आवश्यकता है। शिक्षार्थी की शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर शिक्षक की दक्षता, संवेदनशीलता और प्रेरणा से निर्धारित होता है। साथ ही यह सर्वमान्य धारणा है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक के पढ़ाए जाने वाले विषय की समझ एवं व्यावसायिक क्षमता, सीखने के आवश्यक वातावरण का निर्माण करती है। इसलिए शिक्षक शिक्षा को आवश्यक माना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वीकार करते हुए कहा गया है कि, 'शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं इसलिए वे हमारे राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं इस महान योगदान के कारण शिक्षक भारतीय समाज के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक थे और केवल सर्वश्रेष्ठ विद्वान ही शिक्षक बनते थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक की परिकल्पना - राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक की एक आदर्श अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जो प्राचीन भारतीय शिक्षकों की तरह विद्वता, नैतिक आचरण, कर्तव्यपरायणता और विश्व के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील शिक्षक की कार्य प्रणाली की याद दिलाती है। इसके साथ ही यह नीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, सूचना-संचार की तकनीकों और अत्याधुनिक उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में समर्थ तथा आधुनिक नवाचारों एवं ज्ञान-विज्ञान में दक्ष शिक्षकों की अवधारणा प्रस्तुत करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षक शिक्षा के संबंध में दिए गए महत्त्वपूर्ण सुझाव

इक्कीसवीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार इस शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिनके अनुपालन से न केवल शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक बदलाव लाया जा सकता है, बल्कि इसके साथ ही विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को गति दी जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा से संबंधित प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया है इसमें शिक्षक-प्रशिक्षण की चर्चा भी शामिल है शिक्षक शिक्षा पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (2012) की चिंताओं एवं शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र की समस्याओं तथा उपरोक्त शिक्षक शिक्षा संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित महत्त्वपर्णू सुझाव दिए गए हैं -

1. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम केवल बहु-विषयक शैक्षिक संस्थानों में ही आयोजित किए जाएँ।

2. वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़, बहु-विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित हों।

3. वर्ष 2030 से एकीकृत बी.एड. का अध्ययन केवल बहु-विषयक, गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित मानकों के आधार पर

संचालित संस्थानों में ही किया जा सकता है।

4. एकल विषय आधारित शैक्षणिक संस्थानों का वर्ष 2030 तक बहु–विषयक संस्थानों के रूप में उन्नयन करना, जो संस्थान ऐसा करने में असफल होंगे उन्हें बंद कर दिया जाए।

5. चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, दो वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और एकवर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को स्वीकृति, लेकिन केवल उन्हीं बहु–विषयी संस्थान को दो वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और एक वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति मिले, जो सफलतापूर्वक चार साल के शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम को चला रहे हों।

6. जिनके पास स्नातक की डिग्री है, उनके लिए दो वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम एवं जिनके पास विशिष्ट विषय के साथ चार वर्षीय स्नातक की डिग्री है, उनके लिए एकवर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा सकता है।

7. समाज की आवश्यकताओं को साकार करने वाली नई माँग आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।

8. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए विद्यार्थीवृत्ति की व्यवस्था के साथ ही साथ जरूरतमन्द प्रशिक्षुओं की मदद करना।

9. गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान द्वारा आयोजित विषय और शिक्षक योग्यता परीक्षा के आधार पर शिक्षक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश।

10. पीएच.डी. कार्यक्रम में नए नामांकित विद्यार्थियों को अपने शोध (शिक्षाशास्त्र या अध्ययन अथवा पाठ्यक्रम विकास) के लिए प्रासंगिक विषय में क्रेडिट आधारित अध्ययन करना होगा।

11. शिक्षकों के रूप में काम करने वाले सभी शिक्षकों को अपने व्यावसायिक विकास को जारी रखने के लिए प्रेरणा और सुविधाएँ दी जाएँ।

शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक सभी का एक–दूसरे के साथ बहुत गहरा संबंध है, जहाँ शिक्षा, विकास की एक प्रक्रिया है, सीखने वाला उस विकास का लाभार्थी है तो शिक्षक इस पूरी प्रक्रिया का समन्वयक, निर्माता और प्रशासक है। इसीलिए शिक्षा की प्रक्रिया को गुणात्मक और प्रभावी बनाने के लिए इक्कीसवीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है, जिसने शिक्षक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। शिक्षक शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए जो सिफारिशें और अपेक्षाएँ की गई हैं, उन्हें पूरा करने में कई चुनौतियाँ होंगी, जिनकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

12. स्वयं और दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों से जुड़कर आत्म–विकास के अवसर पैदा करना।

सुझावों के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ और समाधान

किसी भी नीति की सफलता इसके कुशल और व्यावहारिक कार्यान्वयन में निहित है। नीति या योजना कितनी व्यावहारिक और फलदायी होती है, यह कार्यान्वयन की योजना और निष्पादक के साथ–साथ कार्यकर्ता पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी की गई है, परंतु यह नीति प्रस्तावित सुधारों के कार्यान्वयन की स्पष्ट योजना या कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट रूप से दिशा–निर्देशित नहीं करती है। नीति, केवल इस बात पर चर्चा करती है कि क्या किया जाएगा या क्या होने की उम्मीद है, लेकिन इस नीति को अमल में कैसे लाया जाएगा, का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित शिक्षक शिक्षा से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ और इसके समाधान निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझे जा सकते हैं –

1. संरचनात्मक अस्थिरता संबंधित चुनौती – शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में की गई सिफारिशों में संरचनात्मक परिवर्तन सबसे महत्त्वपूर्ण है। इस सिफारिश को लागू करने से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पिछले 10 वर्षों में, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में इतने प्रयोग हुए हैं, जितने पूरी शिक्षा प्रणाली में नहीं हुए। एकवर्षीय बी.एड. कार्यक्रम को परिवर्तित कर दो वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम बना दिया गया। यदि शिक्षक शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाना है तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए ये परिवर्तन स्थायी होने चाहिए और कम से कम 10 साल तक चलते रहना नितांत आवश्यक है, अन्यथा इस परिवर्तन का भी शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में कोई खास योगदान नहीं होगा।

2. स्वरूपगत परिवर्तन से संबंधित चुनौती – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, चार वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम पर बल देती है, लेकिन इसके साथ ही दो वर्षीय और एकवर्षीय बी.एड. कार्यक्रम को फिर से स्थापित करने की पहल की गई है। अंतर यह है कि ये सभी कार्यक्रम अब केवल बहु–विषयक स्वायत्त कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में चलाए जा सकते हैं। वर्तमान स्थिति में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एकल पाठ्यक्रम आधारित कॉलेजों की संख्या बहुत बड़ी है। यदि निजी क्षेत्र के संस्थान इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो उन्हें इस शर्त के साथ अनुमति दी जानी चाहिए कि वे, इस कार्य से मुनाफा कमाने की न सोचें और शिक्षक शिक्षा से संबंधित नीतियों का सख्ती से पालन करें। साथ ही स्वरूपगत परिवर्तनों से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए स्पष्ट नीति बने।

सरकार वित्तीय एवं संसाधनों की उपलब्धता के प्रति अपनी जवाबदेही को निभाए तथा निजी क्षेत्र के संस्थान इसे सेवा कार्य मानते हुए आर्थिक उपार्जन की क्षुद्र भावना से ऊपर उठते हुए नीति-नियमों का पालन कर शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखें।

3. संसाधनों की कमी - राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुझाई गई गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों की भारी कमी दिखाई देती है प्रत्येक संगठन को सुविधाओं के मामले में एक आदर्श संगठन के रूप में विकसित किया जाना है। शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता शिक्षण प्रक्रिया को आसान, सुविधाजनक और प्रभावी बनाती है। बच्चों के चहुँमुखी, समन्वित और पूर्ण विकास के लिए व्यक्तित्व के हर पहलू का विकास आवश्यक है भावी शिक्षक के मानसिक विकास के लिए कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, गतिविधि कक्ष एवं समिति कक्ष के साथ-साथ शारीरिक विकास के लिए एक खेल का मैदान और व्यायामशाला की आवश्यकता होगी। वर्तमान परिदृश्य में, अधिकांश सरकारी और निजी संस्थानों में इन सुविधाओं का अभाव है। शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग चार प्रतिशत खर्च करके इन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मज़बूत इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए, सरकार को अगले तीन वर्षों में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत बढ़ा कर छह प्रतिशत करना होगा और इसे 2035 में अमल में लाने के बजाय आज से ही क्रियान्वित करना चाहिए। सभी शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं चाहे वे सरकारी हों या निजी, दोनों के लिए समान नीति नियम लागू हों। इसके साथ ही भौतिक और मानव संसाधन संबंधी खर्चों को सरकार स्वयं वहन करें।

4. शिक्षक-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में अस्पष्टता - राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों को तैयार करने के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि ऐसे शिक्षकों को तैयार करने वाले शिक्षक-प्रशिक्षक कैसे प्रशिक्षित होंगे। नीति में एम.एड. (शिक्षक-प्रशिक्षक तैयार करने वाले पाठ्यक्रम) के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। शिक्षक-प्रशिक्षकों की दक्षता पर भविष्य के शिक्षकों के प्रशिक्षण का दायित्व होता है जो शिक्षक की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। शिक्षक-प्रशिक्षण, वस्तुतः एक समग्र और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक एवं उन्हें प्रशिक्षित करने वाले शिक्षक-प्रशिक्षक एक बढ़ते क्रम में योजनाबद्ध रूप से आपस में जुड़े होते हैं। शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता स्थापित करने के लिए पहली आवश्यकता प्रशिक्षकों (जो एम.एड. में पढ़ा सकते हैं।) की तैयारी है, जो शिक्षक-प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसी तरह वर्तमान में प्रशिक्षण कार्य में लगे व्यक्तियों को भी सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इस चुनौती के निस्तारण के लिए तत्काल शिक्षक-प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माण एवं कार्यान्वयन इस योजना की जरूरत है।

5. शिक्षाशास्त्र में अप्रशिक्षित व्यक्ति से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षा – राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों के रूप में विकसित करना है। इसके लिए उन विषय-विशेषज्ञों को भी नियुक्त करने की सिफारिश की गई है, जिन्होंने शिक्षक-प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। जबकि शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेषीकृत कार्यक्रम है, जिसमें बाल-व्यवहार एवं मनोविज्ञान, अध्ययन-अध्यापन की तकनीक एवं शिक्षणशास्त्र, आकलन अथवा मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन एवं निर्देशन जैसे अनेक विषयों से संबंधित विशेषज्ञीय सेवा की आवश्यकता होती है। शिक्षाशास्त्र मात्र विषयों को ही पढ़ाने का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि ये अप्रशिक्षित एवं मात्र अपने विषय (गणित, अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, कला इत्यादि) में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति भावी शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षक-प्रशिक्षण का कार्य, क्या सीखना है, से ज़्यादा कैसे सिखाना है, पर जोर देता है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पीएच.डी. करने वाले शोधार्थियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने विषय से संबंधित शिक्षणशास्त्र से संबंधित कोर्स भी करें, जिससे आगे चलकर उन्हें पढ़ाने में कठिनाई न हो, जो एक अच्छी पहल है। अगर पीएच.डी. करने वाले शोधार्थी से यह अपेक्षा रखी जाती है, तो शिक्षक शिक्षा जैसे

विशेषीकृत कार्यक्रम में मात्र अपने विषय का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भविष्य के शिक्षक कैसे तैयार करेंगे, यह एक व्यावहारिक समस्या है। इसलिए शिक्षक शिक्षा संस्थान में शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए शिक्षाशास्त्र में कुशल होना आवश्यक किया जाए और यह महत्त्वपूर्ण निर्णय, बनाई जाने वाली कार्ययोजना में अवश्य शामिल किया जाए।

6. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करने की चुनौती – राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपेक्षा की गई है कि प्रतिभाशाली या उच्च श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी–शिक्षक बनने के प्रति आकर्षित हों। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए विद्यार्थीवृत्ति की व्यवस्था की गई है (अंक संख्या 15.5, पृष्ठ सं. 70)। यद्यपि विद्यार्थीवृत्ति का सुझाव प्रशंसनीय कदम है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को किसी भी व्यवसाय में आकर्षित करने के लिए उस क्षेत्र में शामिल होने के समान अवसर, सम्मानजनक वेतनमान, समाज में प्रतिष्ठा और उस व्यवसाय में काम करने के तरीके के साथ–साथ आगे बढ़ने के अवसर की अनुकूलता आवश्यक है। अत: अगर हम वास्तव में इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमें इस क्षेत्र में शामिल होने के लिए समान अवसर, सम्मानजनक वेतनमान, समाज में क्षेत्र की प्रतिष्ठा और उस व्यवसाय में काम करने के तरीके के साथ–साथ आगे बढ़ने के अवसर को भी सुनिश्चित करना होगा। अनावश्यक गैर–शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर शिक्षकों को शिक्षण का सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना होगा।

7. नए पाठ्यक्रम को डिजाइन करने की चुनौती – राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालय की शिक्षा संरचना को 5+3+3+4 (तीन से 18 साल के विद्यार्थियों के लिए) में बदल दिया गया है। मनोविज्ञान के अनुसार, मानव विकास के सात मुख्य चरण हैं– (शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था) इन चरणों में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के चरण का संबंध जीवन के लगभग 82 वर्ष (18 वर्ष से 100 वर्ष) से है, जिसमें वैचारिक और शारीरिक परिपक्वता को छोड़कर कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक मानव व्यक्तित्व में एक तेज और बहुआयामी परिवर्तन होता है, जो बच्चे की शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इस काल को ही सीखने का सर्वोत्तम काल माना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तुरंत लागू करने के लिए आवश्यक है कि नए पाठ्यक्रम का निर्माण तुरंत किया जाए। शिक्षक की भूमिका में एक बड़ी तब्दीली आई है, उसे अब तक ज्ञान के स्रोत के केंद्र रूप में स्थान मिलता रहा है और वही समूची सीखने–सिखाने की प्रक्रिया का संरक्षक एवं प्रबंधक रहा है। अब उसकी भूमिका ज्ञान के स्रोत के बदले एक सहायक की होगी, जो सूचना को ज्ञान अथवा बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों से शिक्षार्थियों को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करे

8. शिक्षक शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को बनाए रखने की चुनौती – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर तक ड्रॉप आउट दर को शून्य प्रतिशत पर ला देना, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन 50 प्रतिशत तक बढ़ाना तथा प्रत्येक एकल शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं को बहु–विषयी संस्था के रूप में विकसित करना है। वर्ष 2030 तक सभी एकल संस्थाओं को बहु–विषयी संस्था के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 के बाद मात्र बहु–अनुशासनात्मक संस्थानों में ही शिक्षक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम चलाए जा सकते हैं वर्तमान में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए यह लक्ष्य अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। स्वाभाविक रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालयों के साथ–साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलना होगा, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसमें शिक्षकों के साथ –साथ भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार की जाने वाली योजना को उपरोक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी नियामक संस्थाएँ निडर होकर काम करती हैं, तो इस चुनौती को पार करने में कोई विशेष बाधा नहीं होगी। मजबूत इच्छाशक्ति, स्पष्ट कार्य योजना और पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार, शिक्षक, प्रबंधन समिति एवं समाज सबकी निश्चित भूमिकाओं के निर्वाह की जरूरत है।

निष्कर्ष – शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक सभी का एक–दूसरे के साथ बहुत गहरा संबंध है, जहाँ शिक्षा, विकास की एक प्रक्रिया है, सीखने वाला उस विकास का लाभार्थी है तो शिक्षक इस पूरी प्रक्रिया का समन्वयक, निर्माता और प्रशासक है। इसीलिए शिक्षा की प्रक्रिया को गुणात्मक और प्रभावी बनाने के लिए इक्कीसवीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है, जिसने शिक्षक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। शिक्षक शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए जो सिफारिशें और अपेक्षाएँ की गई हैं, उन्हें पूरा करने में कई चुनौतियाँ होंगी, जिनकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है। यदि शिक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो उपरोक्त चुनौतियों का हल ढूँढ़कर भारतीय शिक्षा प्रणाली को फिर से विश्वस्तरीय बनाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ सरकार, समाज, शिक्षक, प्रबंध समिति एवं विद्यार्थियों के प्रयासों की जरूरत है। ❑

भारतीय ज्ञान परम्परा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति

डॉ. चेतना उपाध्याय

राजकीय जिला प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर (राज.)

अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।

उक्त सूत्र हमारी भारतीय ज्ञान परम्पराओं का विशिष्ट आधार रहा है। हमारे वेद, उपनिषद सदैव से उच्च मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों के वैज्ञानिक स्वरूप में प्रणेता रहे हैं। इनमें आम जन जीवन हेतु जिसे वर्तमान में जीवन कौशल कहा जा रहा है। मानवीय मूल्यों के आध्यात्मिक आधार के साथ पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। भारतीय ज्ञान परम्परा सदैव से ही उच्च मानवीय मूल्यों को समाहित करते हुए विश्वस्तरीय रही है। भारतीय दर्शन है..... 'सृष्टि विश्व परमेष्टि' अर्थात् आत्मा, परमात्मा और प्रकृति।

वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों के आंतरिक ज्ञान, गुण शक्ति एवं आदर्शों को ठीक रूप से पहचानने, समझने, अपनाने में, उसके उचित दिशा में प्रवाह को बरकरार रखने में हम भारतीयों से ही थोड़ी चूक हुई। इसमें प्रमुख भूमिका अंग्रेजों के आक्रमण पश्चात मैकाले की औपचारिक शिक्षण प्रणाली की रही। मैकाले की शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य ही यह रहा था कि भारतीय ज्ञान परम्परा को पूर्णतः तहस नहस किया जा सके ताकि समृद्धशाली ज्ञानी हिन्दुस्तानियों पर राज किए जा सके। उन्हें इसमें कामयाबी भी हासिल हो गई। यही कारण रहा कि अंग्रेज भारत को गुलाम बना उस पर शासन कर पाए और इतना ही नहीं हिन्दुस्तान को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुए 75 वर्षों बाद तक भी हम आज तक अंग्रेजी और अंग्रेजियत की मानसिक गुलामी ढोऐ चले जा रहे हैं। यह भारतीय ज्ञान परम्पराओं के तहस नहस किए जाने के परिणामस्वरूप संभव हो सका। अन्यथा भारतीय ज्ञान परम्पराओं के साथ भारत को गुलाम बनाकर उस पर शासन कर पाना आसान नहीं होता। क्योंकि भारतीय ज्ञान परम्परा की प्रमुख सूक्ति रही है-

'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात् विद्या वही जो विमुक्त करे।......... भारतीय ज्ञान परम्पराओं से विलग होते ही हम बंधन में जकड़ते गए।

यहाँ द्वितीय प्रमुख बिन्दु यह है कि भारतीय ज्ञान परम्परा से मानव को धरती पर पाए जाने वाले अन्य प्राणियों से पृथक कर मनुष्यता का अमृतपान करवाती है। अतः उक्त शिक्षा प्रणाली से दूर होना मानव द्वारा स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। अतः मैकाले की शिक्षण प्रणाली से यह स्वयमेव ही हुआ और हम इसे समझ ही न पाए।

आजादी के पश्चात् अब तक तीन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ आई हैं। पहली शिक्षा नीति कोठारी आयोग की अध्यक्षता में 1968 में लागू हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इसका हर पाँच साल में रिव्यू होगा। मगर ऐसा हो नहीं पाया। द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में बनी 1992 में इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी किए गए। अब चौंतीस वर्षों बाद 29-7-2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा के कस्तूरीगंन की अध्यक्षता में बनी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। जिसमें भारतीय ज्ञान परम्पराओं को समाहित करने पर पूरा जोर दिया गया है।

हालांकि पहले वाली दोनों शिक्षा नीतियाँ भी भारतीय ज्ञान परम्पराओं से प्रेरित थी।

मगर योजनाबद्ध क्रियान्विति का अभाव रहा। फिर क्रियान्विति भी मैकाले शिक्षण पद्धति से शिक्षित शिक्षाविदों के माध्यम से ही होनी थी। स्वाभाविक है उसे भारतीय ज्ञान परम्पराओं को प्राथमिकता प्रदान कर पाना संभव न हो पाया।

वर्तमान में नव शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान, परम्पराओं से प्रेरित हो औपचारिक शिक्षण प्रणाली में भारतीय ज्ञान परम्पराओं के अनुसरण की बाध्यता साथ लिए हैं। आज के दौर में उस पुरातन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से समय बहुत आगे निकल चुका है। सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत परिवर्तित हो चुकी हैं। वह शिक्षा प्रणाली पूर्णतः अनौपचारिक हुआ करती थी। वर्तमान दौर में चहुंओर औपचारिक शिक्षा प्रणाली व्याप्त है। विगत कई वर्षों में अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को मूल्यहीन समक्ष रख औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाने लगी है। समस्त सामाजिक, व्यावसायिक, राजनैतिक, व्यावहारिक व्यवस्थाएँ भी उसी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का अंग हो चुकी हैं। हमारा समाज उसे आत्मसात कर चुका है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नव शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परम्परा को समुचित स्थान प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय सनातनी ज्ञान एवं विचारों से समूह परम्परा के आलोक में निर्मित की गयी है। इस शिक्षा नीति के आधार स्तम्भों में भारतीय ज्ञान परम्परा को भी एक स्तम्भ माना गया है। इसमें ऐसा प्रयास किया गया है कि विद्यार्थी अपने ज्ञान, व्यवहार, बौद्धिक कौशल से स्थाई सर्वांगीण विकास, समृद्ध जीवन यापन व वैश्विक कल्याण हेतु प्रतिबद्धता को प्राप्त कर सके। आइए इसे थोड़ा, विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं।

नव शिक्षा नीति सम्पूर्ण मानव समाज की समग्रता को साथ समेटे प्रत्येक बालक की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानने, उसे निखारने के पश्चात् उसके सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देती है। इसमें शिक्षा के प्रमुख यथा, (पूर्व प्राथमिक शिक्षा) विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक शिक्षा प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन और अवलोकन शामिल है।

शिक्षा नीति 2020 का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बालक अपनी जन्मभूमि या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी अवसर से वंचित ना रह जाए। इसमें शैक्षणिक विषयों के साथ-साथ कला, मानविकी, खेल और व्यावसायिक कौशल के एकीकरण को बढ़ावा देते हुए शिक्षा हेतु एक समग्र और बहुविषयक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। परीक्षा हेतु सीखने की बजाय विषयगत अवधारणा की समझ को प्रधानता देने का प्रयास किया गया है।

औपचारिक शिक्षण प्रारम्भ हेतु न्यूनतम 6 वर्ष की उम्र का प्रावधान किए जाने के साथ ही 3 से 6 वर्ष की उम्र तक पूर्व प्राथमिक शिक्षण हेतु खेल गतिविधि आधारित शिक्षण व्यवस्था का निर्धारिण किया गया है। इसका उद्देश्य बालक को प्रारम्भिक शिक्षा हेतु पूर्व तैयारी मात्र ही है। इसके आगे भी विद्यालय एक ऐसा स्थान होगा जहाँ विद्यार्थी बुनियादी शिष्टाचार व जीवन कौशल को समझ व आत्मसात कर सके। ऐसी व्यवस्थाएँ की जाने का प्रावधान प्रारम्भिक योजना में ही रखा गया है। विद्यार्थियों में रचनात्मकता को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किए जाने का प्रावधान भी रहेगा।

नवीन शिक्षानीति के चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा भी शामिल है कि हर वर्ष न्यूनतम 50 घंटे निरंतर पेशेवर विकास का प्रशिक्षण भी प्राप्त करे इससे गुणवत्तापूर्ण आचार्यस्वरूप शिक्षकों की उपलब्धता हो पाएगी परिणामस्वरूप हमारा राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में नवीन पायदान चढ़ पाएगा। भारतीय ज्ञान परम्परा में भी शिक्षक स्वाध्याय को ही शिक्षक का तप माना गया है। यह पेशेवर विकास प्रशिक्षण भी शिक्षक का तप ही है। कुल मिलाकर नव शिक्षा नीति का उद्देश्य बालकों को 21वीं सदी के नव तकनीकी कौशलों के साथ कुशल सामाजिक जीवन हेतु तैयार करना है।

पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में मानवीय अनुभूतियों, नैतिकता, सहानुभूति, जिम्मेदारी, स्वच्छता, दूसरों का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति हेतु जवाबदेही, समानता, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा व उनका सम्मान जैसे तत्त्व शामिल होंगे।

उक्त समस्त प्रावधान भारतीय ज्ञान परम्परा बरकरार रखने के उद्देश्य से ही किए गए है। उक्त प्रावधानों को आकार देने हेतु विद्यालयी शिक्षा की नव संरचना 5+3+3+4 दी गई है।

5 वर्ष आधारभूत शिक्षा व अंक ज्ञान (आंगनबाड़ी कक्षा 1-2, बालक की उम्र 3-8 वर्ष), 3 वर्ष शिक्षण हेतु पूर्व प्रारम्भिक तैयारी (बालक उम्र 8 - 11 वर्ष, कक्षा 3 से 5), 5 वर्ष माध्यमिक शिक्षा (बालक उम्र 11 से 14, कक्षा 6 से 8), 4 वर्ष उच्च माध्यमिक शिक्षा (बालक उम्र 14 से 18, कक्षा 9-12) विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक सोच विचार प्रक्रिया व प्रयोगात्मक अधिगम प्रक्रिया, हस्त कौशलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने का प्रावधान है। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में विषय चयन में कला-विज्ञान-वाणिज्य की सीमाओं को समाप्त कर लचीलेपन का प्रावधान किया गया है। ताकि विद्यार्थियों को रुचि अनुकूल विषय चयन में सुविधा व उनके विकास में सहजता रह पाए इससे पाठ्यक्रम, पाठ्येतर गतिविधियों, शैक्षणिक व व्यावसायिक धाराओं के मध्य सहज समरसता स्थापित हो पाएगी। राष्ट्रीय

विकास में सकारात्मक वृद्धि दृष्टिगोचर होगी। जिस प्रकार पूर्व में भारतीय ज्ञान परम्परा के बदौलत भारत विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाता था। नवीन शिक्षानीति के परिणामस्वरूप पुनः भारत के विश्वगुरु बनने की संभावनाएँ स्थापित हो पाएंगी तथा आर्थिक सुदृढ़ता भी सहज, सुगमस्वरूप में प्राप्त हो पाएगी।

इस स्वप्न के पूर्ण होने में त्रिभाषाई सूत्र की भी बेहद महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा प्रत्येक पाठ्यक्रम का मूल हिस्सा होना। भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को भी शिक्षा के सभी स्तरों पर विकल्प के रूप में उपलब्ध होना साथ ही प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होने का प्रावधान भी शिक्षा के क्षेत्र में विकास की नव गाथा लिखने में कामयाबी हासिल करेगा। मातृ भाषा में प्राथमिक शिक्षा होने से बालक की शैक्षिक नींव मजबूत बन पाएगी कारण कि वह पाठ्यक्रम को सहजता से आत्मसात कर पाएगा तो उसका अधिगम बेहतर होगा ही। क्योंकि मातृभाषा में जो कहा जाता है वही किया जाता है, जो किया जाता है वही महसूस किया जाता है। यह बात भारतीय सामाजिक परिवेश में शत प्रतिशत लागू होती है। मातृभाषा में कथन के साथ व अन्य अंगों के संचालन अथवा मुद्राओं का भी योगदान होता है। जैसे नमस्ते के दौरान दोनों हाथ जुड़ सीने के समक्ष आ जाते हैं

गर्दन स्वतः सम्मानजनक स्वरूप में झुक जाती है।

आंग्ल भाषायी माध्यम में प्रारम्भिक शिक्षा होने से बालक में वह सहज मौलिक अहसास जाग्रत नहीं हो पाता। वह भ्रमित हो रट्टू तोता मात्र होकर रह जाता है। बालक अपने अपेक्षित विकास के चरम को प्राप्त नहीं कर पाता। मातृभाषा में शिक्षण से विद्यार्थियों में मौलिकता व सृजनात्मकता को पोषण प्राप्त होगा। अभिव्यक्ति क्षमता में भी सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो पाएगा। विद्यार्थियों की जिज्ञासु प्रवृत्ति अन्वेषणात्मक रूप में गति ले पाएगी। जिससे विद्यार्थियों को चहुँमुखी विकास के अवसर प्राप्त हो पाएँगे।

वैश्वीकरण के इस तकनीकी युग में शिक्षा में प्रौद्योगिकी व तकनीकी शिक्षा का प्रावधान भी रखा गया है। जिससे वैश्विक तकनीकी में भारत सदैव अग्रणी रह पाएगा। नव शिक्षा नीति में इस हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच एक स्वायत्त निकाय बनाए जाने का प्रस्ताव है जो प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों से मुक्त आदान प्रदान के लिए एक समृद्ध मंच प्रदान करेगा। जो कि निश्चित ही भारतीय ज्ञान परम्परानुसार विद्यार्थियों में जीवन कौशल आयाम को समृद्धि प्रदान कर पाने में कामयाबी हासिल कर पाएगा।

शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में पाठ्यक्रम सहज व गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। जिसमें विषयगत क्षेत्र के मूल केन्द्रीय भाव को प्राथमिकता दी जाएगी। जिससे विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक, गहन संशलेषणात्मक, सृजनात्मक अधिगम के प्रति उत्सुकता व प्रेरणा जाग्रत हो पाएगी। भारतीय ज्ञान परम्परा का मूलाभाव भी यही रहा है।

इसके आगे महाविद्यालयी शिक्षा स्नातक स्तर उसे 4 वर्ष तक का लचीला व छात्र हित सर्वोपरी मानते हुए बेहतरीन प्रारूप तैयार किया गया है इसमें शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम को एकीकृत कर 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम प्रस्तातिव किया गया है। इसमें छात्र अध्ययन के प्रत्येक वर्ष का सदुपयोग प्रामाणिक दस्तावेज आधारित होगा। यह विशिष्ट प्रणाली पहली बार प्रस्तुत की गई है। यह व्यावसायिक शिक्षण के दृष्टिकोण से भी बेहतरीन है। क्योंकि स्नातक का प्रत्येक वर्ष मूल्यवान बना दिया गया है इससे अध्ययन की निरंतरता को बनाए रख पाने में असमर्थ छात्र जब भी एक वर्ष या दो वर्ष में शिक्षण छोड़ता है तो वर्षानुरुप प्रामाणिक दस्तावेज उसके पास होने से वह संबधित व्यवसाय में सहज ही शामिल हो पाएगा।

उदाहरण – 1 वर्ष बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष बाद डिप्लोमा, 3 वर्ष बाद स्नातक, 4 वर्ष बाद स्नातक के साथ व्यावसायिक डिग्री।

इसका सर्वाधिक लाभ शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को हो पाएगा क्योंकि इससे पूर्व तीन वर्षीय स्नातक पश्चात् दो वर्षीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में अध्ययन करने का होता था।

एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम से छात्रों का एक वर्ष बचेगा व दूसरा लाभ यह है कि शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में अभिरुचि रखने वाले छात्र ही उक्त चार वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे। और इन चार वर्षों में वे शिक्षक शिक्षा के प्रति केन्द्रित व समर्पित रह पाएंगे। इससे समर्पित शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी। पूर्व प्रावधान में स्नातक करने के साथ ही विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की तलाश प्रारंभ कर देते हैं। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् भी उनकी यह तलाश जारी रहती है कि कहीं भी कोई नौकरी प्राप्त हो जाए। इस सोच के साथ समर्पित शिक्षकों की उपलब्धता में कमी दृष्टिगोचर हो जाया करती है।

नवीन शिक्षानीति के चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा भी शामिल है कि हर वर्ष न्यूनतम 50 घंटे निरंतर पेशेवर विकास का प्रशिक्षण भी प्राप्त करे इससे गुणवत्तापूर्ण आचार्यस्वरूप शिक्षकों की उपलब्धता हो पाएगी परिणामस्वरूप हमारा राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में नवीन पायदान चढ़ पाएगा। भारतीय ज्ञान परम्परा में भी शिक्षक स्वाध्याय को ही शिक्षक का तप माना गया है। यह पेशेवर विकास प्रशिक्षण भी शिक्षक का तप ही है।

कुल मिलाकर नव शिक्षा नीति का उद्देश्य बालकों को 21वीं सदी के नव तकनीकी कौशलों के साथ कुशल सामाजिक जीवन हेतु तैयार करना है। यह भारत को ज्ञानी महाशक्ति, विश्वगुरु जैसा विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता के तीन स्तंभों पर आधारित है जो कि समान व समावेशी शिक्षा पर बल देती है। ❑

परिवर्तन की प्रतीक्षा में पाठ्यक्रम

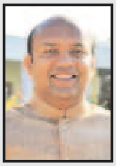

प्रणय कुमार
शिक्षाविद एवं
वरिष्ठ स्तंभकार

किसी भी राष्ट्र का भविष्य शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा ही वह सुदृढ़ नींव है, जिस पर राष्ट्र रूपी भवन की ऊँचाई और मजबूती टिकी होती है। शिक्षा के अभाव में विकास की सारी बातें निरर्थक हैं, बेमानी हैं। पिछले 10 वर्षों में देश ने लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, परंतु शिक्षा का क्षेत्र कमोवेश उपेक्षित ही रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रचार-प्रसार तो खूब हुआ, परंतु धरातल पर उसका क्रियान्वयन, प्रभाव और परिणाम दिखाई नहीं देता। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुनाव-प्रचार के दौरान छोटे-बड़े सभी चैनलों पर दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रीय जीवन के अधिकांश विषयों एवं पहलुओं पर खुलकर बात की। परंतु इसे विडंबना ही कहेंगे कि लोकतंत्र में प्रहरी की भूमिका का दावा करने वाले तमाम चैनलों में से किसी ने भी उनसे शिक्षा में सुधारों से जुड़े प्रश्न नहीं पूछे! यह शिक्षा के प्रति हमारी उपेक्षा एवं सरोकारहीनता को दर्शाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भावी पीढ़ी के भविष्य व निर्माण से जुड़ा विषय - समाज और सरकार की प्राथमिकता-सूची में सबसे निचले क्रम पर दिखाई देता है। राजनीतिक दलों के लिए जब सत्ता-प्राप्ति का सीमित और तात्कालिक लक्ष्य सर्वोपरि हो जाता है, तब विचारों के गठन और व्यक्ति-निर्माण का प्रश्न पीछे छूट जाता है। नि:संदेह मोदी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में अधिक आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजेज एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि खोले हैं। परंतु क्या केवल उतने भर से संतुष्ट हुआ जा सकता है? क्या हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की शिक्षा की स्थिति, शिक्षण का स्तर, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, विश्व में उसकी साख एवं विश्वसनीयता, वर्षों से लंबित एवं रिक्त पदों पर नई नियुक्ति, मौलिक शोध एवं नवोन्मेष, कौशल एवं तकनीक की दक्षता, अध्यापकों का प्रशिक्षण, नियमित सत्र, अनुशासित शैक्षिक वातावरण, रोजगारपरक शिक्षा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त परीक्षा तथा भारी धन खर्च कर भी विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की बढ़ती लालसा आदि पर समाधानपरक काम नहीं किया जाना चाहिए?

उम्मीद थी कि बीते दस वर्षों की पूर्ण बहुमत वाली सरकार में पाठ्यक्रम में सुधार की दृष्टि से ठोस एवं निर्णायक पहल की जाएगी। परंतु इस दिशा में अभी तक खानापूर्ति ही अधिक हुई है। जहाँ बुनियाद

बदलने की शर्त हो, क्या वहाँ केवल रंग-रोगन अथवा साज-सज्जा से काम चलाया जा सकता है? आवश्यकता संशोधन-संक्षिप्तीकरण की नहीं, अपितु राष्ट्र की चिर-प्रतीक्षित आकांक्षा के अनुरूप पाठ्यक्रम में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की थी, और है। क्या इसमें भी कोई दो राय हो सकती है कि भाषा, साहित्य, इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन जैसे मानविकी के विभिन्न विषयों के माध्यम से सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता को मजबूती मिलनी चाहिए, भारतीय ज्ञान-परंपरा को पोषण मिलना चाहिए, अस्तित्ववादी विमर्श एवं विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर विराम लगना चाहिए, सहयोग, समन्वय, संतुलन, सामाजिकता, संवेदनशीलता एवं देशभक्ति जैसे मूल्यों को प्रश्रय एवं प्रोत्साहन मिलना चाहिए, भारतीय संस्कृति में व्याप्त बहुलता, शांति एवं सह-अस्तित्व के मूल स्रोत की खोज व पहचान की जानी चाहिए? कैसी विचित्र विडंबना है कि हमारे बौद्धिक-राजनीतिक-अकादमिक विमर्श में 'भारत वर्ष में व्याप्त विविधता में एकता' का उल्लेख तो भरपूर किया जाता है, पर उस एकत्व को पोषण देने वाले मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, प्रमुख घटकों, मंदिरों, मठों, तीर्थों, त्योहारों आदि की कोई चर्चा नहीं होती? क्या पाठ्यक्रम में इन्हें यथोचित स्थान नहीं मिलना चाहिए? कौन नहीं जानता कि इतिहास की हमारी पाठ्यपुस्तकों में विदेशी आक्रांताओं की अतिरंजित विवेचना की गई है, भारतीयों के साहस, संघर्ष एवं प्रतिरोध को अपेक्षाकृत कम महत्त्व दिया गया है, संपूर्ण देश के वैशिष्ट्य एवं गौरवशाली अध्यायों की अपेक्षा केवल दिल्ली-केंद्रित इतिहास को केंद्र में रखा गया है तथा देश के अमर सपूतों, बलिदानी धर्मरक्षकों, महान संतों, समन्वयवादी समाज-सुधारकों, साहसी क्रांतिकारियों, राष्ट्रनिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों को नेपथ्य में रख, दो-चार का महिमामंडन किया गया है! क्या यह सत्य नहीं कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था व पाठ्य-सामग्रियों में श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास पर संदेह, अनास्था एवं अविश्वास को वरीयता दी गई है। उसमें अधिकार भाव की प्रबलता है, कर्त्तव्य-भावना गौण है, नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों का अभाव है तथा सफलता एवं प्रतिस्पर्द्धा का प्राधान्य है? औपनिवेशिक मानसिकता, अस्मितावादी विमर्श एवं वर्गीय चेतना के नाम पर हीन भावनाओं, अलगाववादी वृत्तियों तथा पारस्परिक मतभेद, असहमति एवं संघर्ष को शिक्षा के माध्यम से पाला-पोसा-बढ़ाया गया है। मूल बनाम बाहरी, उत्तर बनाम दक्षिण, राष्ट्रभाषा बनाम क्षेत्रीय भाषा, स्त्री बनाम पुरुष, व्यक्ति बनाम समाज, वर्गीय/जातीय/सामुदायिक अस्मिता बनाम राष्ट्रीय अस्मिता, परंपरा बनाम आधुनिकता, नगरीय बनाम ग्रामीण, मजदूर बनाम किसान, गरीब बनाम अमीर, उपभोक्ता बनाम उत्पादक, उद्योगपति बनाम सर्वहारा, मनुष्य बनाम प्रकृति, विकास बनाम पर्यावरण जैसी मिथ्या एवं कृत्रिम लड़ाइयाँ, शिक्षा, साहित्य, कला व संस्कृति के माध्यम से खड़ी की गईं हैं। परिवार, समाज एवं राष्ट्र की विभिन्न इकाइयों को परस्पर विरोधी मानने वाली ऐसी खंडित एवं विभेदकारी दृष्टि के स्थान पर, क्या शिक्षा-व्यवस्था में समन्वय और समग्रता पर आधारित सनातन दृष्टि को स्थान नहीं मिलना चाहिए? सच तो यह है कि हमारी पूरी शिक्षा-व्यवस्था व पाठ्य-सामग्रियों में जोड़ने वाले तत्त्वों का अभाव है और तोड़ने वाले तर्कों, कारकों, धारणाओं, पूर्वाग्रहों का प्रभाव है। इतना ही नहीं, हमारी

हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति में तब तक अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सकता, जब तक कि उन्हें विद्यालयी शिक्षा में अनिवार्यतः लागू नहीं किया जाता। विभिन्न स्तरों की परीक्षा-पद्धति, प्रश्नपत्र के प्रारूप, मूल्यांकन की प्रक्रिया आदि में अनेक सुधार अपेक्षित एवं अत्यावश्यक हैं। प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। उसके कारण विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में व्यवस्था के प्रति अनावश्यक असंतोष पनपता है। चाहे वह राज्यों की सरकार हो या केंद्र की, उन्हें विद्यार्थियों-परीक्षार्थियों के प्रति अतिरिक्त संवेदना दर्शानी होगी और व्यवस्था में व्याप्त ऐसे सभी छिद्रों को अनिवार्यतः बंद करना होगा।

आधुनिक शिक्षा की दृष्टि में रामायण-महाभारत गल्प हैं, वेद-वेदांग-गीता-उपनिषद-षड्दर्शन वायवीय एवं पारलौकिक हैं, भारत विभिन्न राष्ट्रीयताओं एवं अनेक संस्कृतियों का गठजोड़ है। अब कोई बताए कि ऐसे पाठ्यक्रमों को पढ़कर कैसे नागरिक, कैसे मतदाता, कैसे नौकरशाह, कैसे राजनेता, कैसे न्यायाधीश तैयार होंगे? पराए राग-रंग व सोच में आकंठ डूबे लोगों से स्व के साक्षात्कार व भारत के बोध की भला क्या और कितनी उम्मीद की जा सकती है? क्या यह भी बताने की आवश्यकता है कि स्वतंत्र भारत की अनेक गौरवशाली उपलब्धियाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने की बाट जोह रही हैं? क्या भारत की सफल लोकतांत्रिक यात्रा के क्रमिक सोपानों का उल्लेख पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए, क्या आपातकाल के दौरान सर्वसाधारण एवं प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा किए गए संघर्ष व झेली गई यातनाओं की व्यथा-कथा पढ़कर लोकतंत्र के प्रति भावी पीढ़ी की आस्था मजबूत नहीं होगी, क्या चंद्रयान, मंगलयान की सफलता की गाथा नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, क्या उपग्रह, प्रक्षेपास्त्र, तकनीक, प्रौद्योगिकी, संचार-क्रांति एवं सैन्य-क्षेत्र की भारत की नित-नवीन उपलब्धियाँ वर्तमान के लिए प्रेरणादायी नहीं हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रयोग, अनुसंधान व व्यवहार की कसौटी पर कसे जाने वाले गणित और विज्ञान जैसे विषयों में भी बीते कई दशकों से परिवर्तन नहीं किए गए हैं। हर दस-पंद्रह वर्ष में पीढ़ियाँ बदल जाती हैं, उसकी सोच, स्वप्न, सरोकार व प्रेरणाएँ बदल जाती हैं तो क्या पाठ्यक्रम नहीं बदला जाना चाहिए?

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन-अध्यापन की भाषा के रूप में मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं की पुरजोर पैरवी की गई है। शिक्षाविदों ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आत्मा के रूप में चिह्नित-प्रतिपादित किया है। परंतु अभी तक इस दिशा में किसी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने तथा माध्यमिक स्तर पर दो राष्ट्रीय (नैटिव) एवं एक विदेशी (फॉरेन) और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक भारतीय (नैटिव) एवं एक विदेशी (फॉरेन) भाषा पढ़ाए जाने की संस्तुति की गई है, परंतु विभिन्न बोर्डों की ओर से इस दिशा में अभी तक कोई दिशानिर्देश (गाइडलाइंस) नहीं जारी किए गए हैं। यथार्थ यह है कि हिंदी भाषी राज्यों में कुकरमुत्ते की तरह अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुलते चले जा रहे हैं। कई निजी विद्यालयों में तो स्थिति इतनी भयावह है कि वहाँ न केवल हिंदी बोलने पर प्रतिबंध है, अपितु दंड का भी प्रावधान है। उच्च शिक्षा की कौन कहे, ग्यारहवीं-बारहवीं में भी अधिकांश छात्र हिंदी को एक विषय के रूप में नहीं चुनते हैं, क्योंकि उनके पास हिंदी के विकल्प के रूप में अधिक अंक दिलाने वाले अनेक विषयों के विकल्प उपलब्ध हैं। उन्हें हिंदी का पाठ्यक्रम रोचक, ज्ञानवर्द्धक, रोजगारोनुकूल एवं परिवेशगत नहीं लगता। चूँकि हिंदी भाषा व साहित्य को छोड़कर शेष सभी विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी में कराई जाती है, इसलिए हिंदी लिखना भी उन्हें कठिन जान पड़ता है। वहीं जेईई, नीट, यूपीएससी, क्लेट, कैट, सीडीएस, एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में पाठ्य-सामग्रियों का अभाव और प्रश्नपत्रों का प्रारूप भी नई पीढ़ी को उनसे दूर ले जाता है। घिसी-पिटी परिपाटी, नौकरशाही एवं राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थ तथा सरकार की इच्छाशक्ति की कमी के कारण भारतीय भाषाओं की उपेक्षा का क्रम यथावत जारी है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति में तब तक अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सकता, जब तक कि उन्हें विद्यालयी शिक्षा में अनिवार्यतः लागू नहीं किया जाता। विभिन्न स्तरों की परीक्षा-पद्धत्ति, प्रश्नपत्र के प्रारूप, मूल्यांकन की प्रक्रिया आदि में अनेक सुधार अपेक्षित एवं अत्यावश्यक हैं। प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। उसके कारण विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में व्यवस्था के प्रति अनावश्यक असंतोष पनपता है। चाहे वह राज्यों की सरकार हो या केंद्र की, उन्हें विद्यार्थियों-परीक्षार्थियों के प्रति अतिरिक्त संवेदना दर्शानी होगी और व्यवस्था में व्याप्त ऐसे सभी छिद्रों को अनिवार्यतः बंद करना होगा। संयोग से कुछ दिनों पूर्व ही किए गए मंत्रिमंडल के गठन में निरंतरता का विशेष ध्यान रखा गया है। निःसंदेह इससे शिक्षा-क्षेत्र में भी सुधारों को गति एवं दिशा मिलेगी, नीतियों के क्रियान्वयन में सुविधा होगी तथा समाधान को बल मिलेगा। ❑

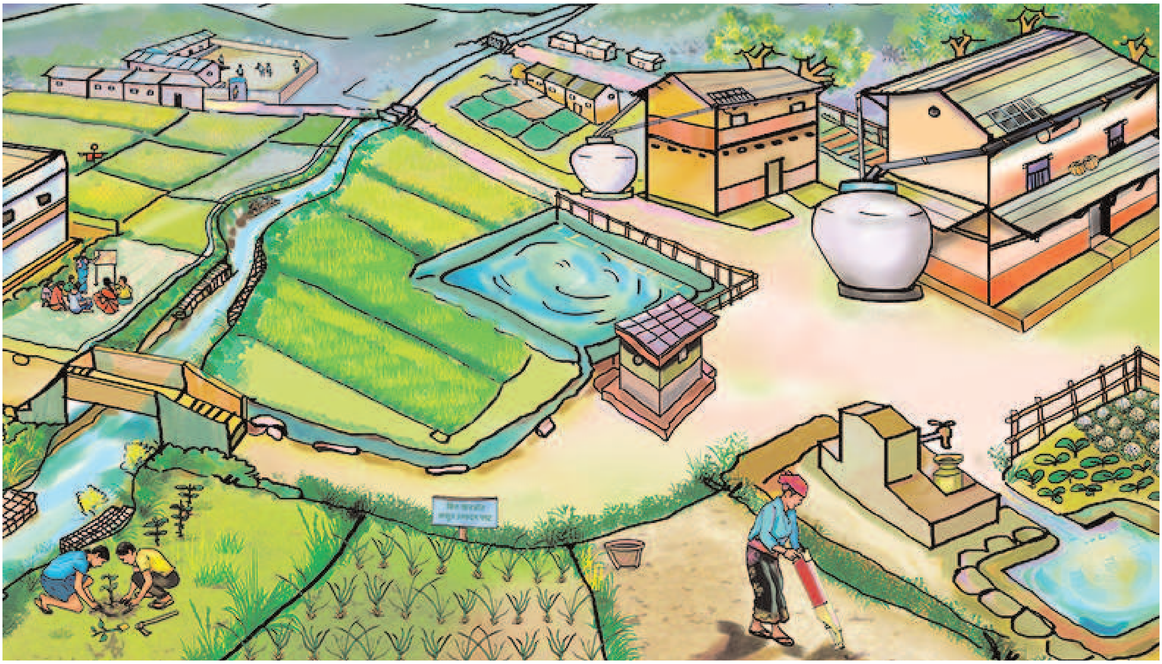

प्रकृति केन्द्रित विकास की अवधारणा

डॉ. विजय वशिष्ठ

सेवानिवृत्त प्राचार्य,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

नई जमीन नया आसमाँ बनाते हैं, हम अपने वास्ते अपना जहाँ बनाते हैं।

पृथ्वी का कुछ करो नहीं तो अनर्थ हो जायेगा।

आज जब भी विकास की चर्चा प्रारम्भ होती है तब हमारा ध्यान बड़ेभवन, बड़े कारखाने, चमकदार सड़कें, उस पर दौड़ती बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े मॉल्स, होटल, विश्वविद्यालय आदि की ओर जाता है और हम बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हमारा देश विकास कर रहा है। हमारी जी.डी.पी. बढ़ रही है, विदेशी मुद्रा भण्डार बढ़ रहा है, हमारा शेयर मार्केट उछाल पर है, हमारा उपभोग का स्तर बढ़ रहा है। यह सब देखकर हम खुश तो होते हैं लेकिन इसके दूसरे पक्ष पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। यह विकास किस लागत पर हो रहा है। इसको पाने के लिए हमें क्या खोना पड़ रहा है। विकास के नाम पर हम कितना विनाश करते जा रहे हैं, प्रकृति का हम कितना शोषण कर रहे हैं, हम यह भूल गये कि मनुष्य प्रकृति का अंश है, प्रकृति का विजेता नहीं। जैसे इस सृष्टि में मनुष्य का स्थान और अधिकार है वैसे ही प्रकृति के अन्य घटक नदी, पेड़-पौधे, पर्वत, पशु-पक्षी, कीट-पतंग सभी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भगवान ने मनुष्य को बुद्धि और विवेक दिया है, ना कि उन सबके शोषण और विनाश के लिए।

भारत में विकास का मतलब है शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का संतुलित सुख। हम कैसा समाज चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी ही प्रकृति का विनाश कर अपना विकास करे तथा आगे आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं करें! हम दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। वास्तविक विकास मानव केन्द्रित न होकर परिस्थितिकी केन्द्रित होना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जमीन, जल, जंगल, जानवर एवं जन का परस्पर शोषण नहीं, पोषण होता रहे तथा व्यक्ति, समाज, देश, विश्व तथा प्रकृति के साथ तालमेल बना रहे।

आधुनिक विकास के कारण जलवायु परिवर्तन के संकट ने मानवता के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण अब ऋतुएँ भी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। बसंत का मौसम मानो गायब हो गया है। सर्दियों से सीधे अचानक गर्मी का मौसम आ गया। बे-मौसम होने वाली वर्षा से फसलें नष्ट हो रही हैं। चेरापूंजी सूख रहा है। लद्दाख के ग्लेशियर पिघलने से वहां की झील एवं तालाबों में क्षमता से अधिक पानी भर रहा है हिमालय के कच्चे पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखण्ड एवं रामबन (जम्मू कश्मीर) इसके उदाहरण हैं।

हम हमारे वनों को नष्ट करते जा रहे

हैं। इससे हवा, पानी, मिट्टी सब दूषित हो रहा है। देशभर में अनावश्यक भूमि जल का दोहन हो रहा है। हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदियाँ, तालाब, बांध आदि के जल भराव एवं जल प्रवाह क्षेत्र अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे ज्यादा 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर सम्मिलित हैं। भारत में लगभग 6.5 लाख लोग प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। हमारे नदी-नाले सब प्रदूषित हो चुके हैं। प्रकृति के पाँचों तत्त्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु एवं अग्नि सभी प्रदूषित हो चुके हैं। आधुनिक विकास की गति यही रही तो प्रकृति का विनाश निश्चित है। कुछ लोगों की सुख-सुविधा में वृद्धि के लिए हम आम-जन जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। आज हमें भारतीय संस्कृति के आधार पर विकास का विचार करना होगा। हमारा देश समृद्धि तो चाहता है लेकिन प्रकृति का विनाश करना नहीं। हम प्रकृति के उपासक हैं प्रकृति की पूजा करते हैं। हम पृथ्वी को माँ कहते हैं। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति को माता माना है। इसलिए कहा 'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या'।

वैदिक शांति पाठ में कहता है 'ॐ द्यौ शान्तिरन्तदिक्षः शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्मा शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।। ॐ विश्वानिदेव सर्वित-दुंरितानि परासुव यद्भद्रं तम आसुव।

ईशावास्य उपनिषद के अनुसार वन, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण तथा सृष्टि के हर छोटे से छोटे जीव का आविर्भाव ईश्वर द्वारा किया गया है। इस अंतर्सम्बंध को विज्ञान बहुत समय बाद (1960 के दशक में) समझ पाया। लेकिन हमारे ऋषि-मुनियों को इस बात का ज्ञान हजार वर्ष पहले ही हो गया था। उन्होंने मनुष्य द्वारा पवित्र वनों, पर्वतों, नदियों, धरती, जल की देवता के रूप में पूजा करवाई। क्योंकि एक दूसरे के सहारे के कारण ही सब अस्तित्व में है। हमारे वैदिक स्वस्ति वाचनम् में कहा गया-

"ऊं अग्निदेवता, वातोदेवता, सूर्योदेवता, चन्द्रमादेवता, वसवोदेवता, रूद्रोदेवता, अदित्यदेवता, मरुतोदेवता, विश्वेदेवा देवता, बृहस्पति देवतेन्द्रोदेवता, वरुणोदेवता।।

प्रकृति आत्म संतुलित और आत्म निर्भर है, लेकिन इंसान के उस लालच से परेशान है, जिसे आधुनिक शिक्षा द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका कारण है आधुनिक धर्म निरपेक्ष शिक्षा का पवित्रता की भावना से परे होना। इसलिए प्रकृति को कष्ट झेलना पड़ रहा है।

आज पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत चर्चा हो रही है। आधुनिक विकास की होड़ में हमने पर्यावरण को जहरीला बना दिया।

अधिक ए.सी., अधिक फ्रिज, अधिक कारें, अधिक टीवी, अधिक माईक्रोवेव, अधिक मकान, अधिक वेतन, अधिक व्यवसाय, अधिक जीडीपी, अधिक व्यापार, अधिक आयात-निर्यात, अधिक विदेशी मुद्रा भण्डार सब कुछ अधिक....। फिर क्यों न होगा अधिक असंतोष, अधिक दुराचार, अधिक विषाद, अधिक कार्बन उत्सर्जन, अधिक मिलावट, अधिक भ्रष्टाचार...... कैसे बच पायेगी यह पृथ्वी।
यदि हम गंभीरता से इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो हमें भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाना होगा। जिनको आज जापान अपना रहा है। जापान अधिक का आनंद ले चुका है इसके दुष्परिणाम उसने भुगते हैं। आज वह भारतीय सिद्धान्त संतोष (संतोषी सदा सुखी) पर आ रहा है। और हम पश्चिम का अंधाधुंध अनुसरण कर रहे हैं।

हवा, पानी, मिट्टी सबको प्रदूषित कर दिया। प्रदूषण बढ़ाते जा रहे हैं एवं पर्यावरण संरक्षण की चर्चा भी कर रहे हैं। सृष्टि का पोषण हमारा कर्तव्य है। प्रकृति केन्द्रित विकास में हमें यह देखना होगा कि क्या विकास के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है या घट रही है। आज तो ऐसा लग रहा है कि विकास के नाम पर हम भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करते जा रहे हैं। आधुनिक कृषि पद्धति के कारण लाखों हेक्टर भूमि बंजर होती जा रही है। पहले एक क्विंटल रासायनिक खाद डालकर जो उत्पादन किया जाता था, उसके लिए अब 5 क्विंटल रासायनिक खाद डालनी पड़ रही है। इससे यह स्पष्ट है कि भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है जो हमें विनाश की ओर ले जा रही है। भूमि का जल स्तर घट रहा है।

हमारे देश में वर्षा केवल 2 महीने होती है, उसमें भी भारी वर्ष केवल 15 दिन होती है। हमारे पूर्वजों ने वर्षा जल को संचित करके 'अदेव मातृका कृषि' को जन्म दिया था। आज हम इस विद्या को भूल चुके हैं और अंधानुकरण में भू-जल का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप देश के अनेक भागों में भू-जल सैंकड़ों फीट नीचे चला गया है। देश में पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है। आधुनिक विकास के नाम पर हम न केवल जल का दुरूपयोग कर रहे हैं बल्कि उपलब्ध जल को दूषित भी करते जा रहे हैं। हम जिन नदियों को माँ मानकर पूजा करते हैं उन्हें ही प्रदूषित करते जा रहे हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा कावेरी, आदि पवित्र नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। औद्योगिक अपशिष्ट हम नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। गटर लाईन की गंदगी हम पवित्र नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं।

विकास के नाम पर हम वनों का विनाश कर रहे हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिए कम से कम एक तिहाई भू-भाग पर वन होने चाहिए। भारत में इस समय केवल 17 प्रतिशत भूमि पर वन हैं। भूमि पर यदि

वन कम होते हैं तो प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। परिणाम स्वरूप जीवमात्र का जीवन प्रभावित होता है। पृथ्वी पर यदि जंगल का हिस्सा घटता है तो उसे विकास नहीं कह सकते। आज हम उस स्थिति में पहुँचे हैं कि जिन प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्जनन संभव है अथवा नहीं यह सब सांसत में है। उत्पादन के दौर में प्रदूषण का फैलाव हो रहा है। धरती में उष्णता बढ़ रही है। वातावरण गर्म हो रहा है। ओजोन की परतों में छिद्र हो रहा है। भूमि का क्षरण हो रहा है – इससे मानव जीवन दूभर हो रहा है। विकास की लालसा में हम अपने संसाधनों का आपराधिक उपयोग कर रहे हैं। हम विकास को गतिरोध में बदल रहे हैं। विकास की इस पागल दौड़ में हमने प्रकृति की मर्यादा को समाप्त कर दिया। आधुनिक विकास का परिणाम असहनीय बनता जा रहा है। पर्यावरण में हम जहर घोल रहे हैं। मानवीय जीवन विनाश की ओर बढ़ रहा है।

आज पशु–पक्षी और कीट पतंगों का तो और भी बुरा हाल है। पशु–पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ लुप्त हो गयी हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। बंदरों, आवारा कुत्तों, नील गाय आदि की बढ़ती संख्या मनुष्य, कृषि और बागवानी के लिए समस्या बन गयी है। गायों की संख्या घट रही है। अच्छी नस्ल की गायें लुप्त होती जा रही हैं।

आधुनिक विकास जिससे हम देश की जीडीपी बढ़ा रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा रहे हैं, इससे कुछ लोगों का रहन–सहन का स्तर (Standard of Living) तो बढ़ सकता है लेकिन जीवन स्तर (Standard of Life) नहीं बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के धनवान होने से देश धनवान नहीं हो सकता। आधुनिक विकास की विचारधारा से आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, गरीबी, मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार आदि अनेक समस्याएँ बढ़ रही हैं। आज औद्योगीकरण प्रगति का मापदण्ड बन जाने के कारण विश्व संघर्ष तथा युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। अतिरिक्त उत्पादन की खपत अन्य देशों में करने की दौड़ से एक सीमा के बाद बाजार के लिए संघर्ष जन्म लेने लगता है जिसकी परिणति युद्ध में होती है। हमें विकास के सिद्धान्त पर पुनर्विचार करना होगा। विकास भारतीय जीवन मूल्यों एवं संस्कृति के आधार पर करना होगा। जिसमें न्यूनतमता तो सभी को मिले लेकिन अधिकतम की भी कोई सीमा हो। हमें भोग की लालसा पर लगाम लगानी होगी। इसके लिए मन–मस्तिष्क को नियंत्रित करना होगा। इससे आंतरिक विकास होगा, उपभोग की गति कम होगी, संसाधनों के पुनर्जनन की गति तेज होगी। संसाधनों का संरक्षण होने से प्रकृति संतुलन का चक्र बिना रोक–टोक के घूमेगा। जैव विविधता बनी रहेगी, प्रदूषण नहीं होगा। अधिक उत्पादन अधिक लोगों के द्वारा (Mass Production by masses) के सिद्धान्त से लोगों को रोजगार मिलेगा। उपयोग मर्यादित होने से सबकी न्यूनतम आवश्यकताएँ (Minimum Needs) पूरी होंगी। लोगों के जीवन स्तर (Standard of Life) में सुधार होगा।

संतोषपूर्ण जीवन का विचार आज जापान में व्यवहार में दिखायी दे रहा है। इससे खुशी का स्तर (Happyness Index) बढ़ रहा है। हमारे देश में हैप्पीनेस इन्डेक्स घट रहा है। लोग ज्यादा उपभोग करके भी संतुष्ट नहीं हैं। लोगों के चेहरों पर हैप्पीनेस नहीं है। लोग जीवन को बोझ मानने लग गये हैं।

आज जापान में मिनिमलिज्म (न्यूनतमवाद) का सिद्धान्त लागू किया जा रहा है। यह विचार चल रहा है, थोड़ा है ज्यादा की जरूरत नहीं। जापान में लोग बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, ज्यादा सामान को तिलांजलि दे रहे हैं। सीमित कपड़े, न्यूनतम सामान को पसंद कर रहे हैं दिखावटी साजो सामान को लोग नापसंद करने लगे हैं।

धीरे ही सही, लेकिन पनपते रहेंगे और जीयेंगे या सर्वनाश देखते देखते मरेंगे। इन दो विकल्पों में से यदि एक को चुनना पड़े तो मानव जात पहला ही विकल्प चुनेगी। लेकिन इसके पहले यह दृष्टि पैदा होनी चाहिए जो जापान में हुई है।

अधिक ए.सी., अधिक फ्रिज, अधिक कारें, अधिक टीवी, अधिक माईक्रोवेव, अधिक मकान, अधिक वेतन, अधिक व्यवसाय, अधिक जीडीपी, अधिक व्यापार, अधिक आयात–निर्यात, अधिक विदेशी मुद्रा भण्डार सब कुछ अधिक....। फिर क्यों न होगा अधिक असंतोष, अधिक दुराचार, अधिक विषाद, अधिक कार्बन उत्सर्जन, अधिक मिलावट, अधिक भ्रष्टाचार...... कैसे बच पायेगी यह पृथ्वी।

यदि हम गंभीरता से इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो हमें भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाना होगा। जिनको आज जापान अपना रहा है। जापान अधिक का आनंद ले चुका है इसके दुष्परिणाम उसने भुगते हैं। आज वह भारतीय सिद्धान्त **संतोष** (संतोषी सदा सुखी) पर आ रहा है। और हम पश्चिम का अंधाधुंध अनुसरण कर रहे हैं। ❑

Shoodras, the Ancient Producers under Varna Vyavastha and Caste Equanimity

Prof. Bhagwati Prakash
Chairman, UNESCO MGIEP (Mahatma Gandhi Institute of Eductaion for Peace and Sustainable Development)

Caste-Indifferent Equanimity of Ancient Bharat

The ancient vedic civilsation across the country had been devoid of any caste discrimination, caste stratification or the evils like untouchability. The core tenet of the ancient Hindu philosophy has been to perceive all living beings as the divine manifestation of the Almighty. The caste discrimination and stratification that erupted and perpetuated in the last millennium, under the evil influence of the Arabic, Turk and other foreign invaders, followed by jehadi persecution and British colonial rule, has led to the worst social evil of untouchability in the country. This evil had no place in the fabric of social life, prior to the advent of Arab invasion in the 8th century. India has, in the past millennium, faced the most fierce and anarchical aggressions of Arabs, Turks, Mamluks (i.e. Slaves or Gulams), Khiljis, Tughlaqus, Lodhis, Bahamanis, Mughals, Portuguese, and British in the last more than 12 centuries. The invaders had endeavored to persecute, butcher, humiliate and convert the innocent and self righteous Hindu populace from Indonesia in Far East to Sindh and Afghanistan in the west and even beyond. The Hindu society, the sole inhabitants of Bharat, before the Arab aggression had a deeply ingrained sense for values and ethics in their conduct and behaviour. Their preaching for self-righteousness, aimed at ensuring an eternal commitment to one's multifarious duties in the society are well enshrined in the Vedic texts, the six Vedangas, Upnishads, Aranyaks, or the twin epics. All of these have no mention of any kind of such caste stratification and untouchability. All the ancient scriptures, which had largely been beyond the scope for any kind of interpolation due to their advance linguistics, are devoid of any narration of any sort of social discrimination. The Vedic and allied scriptures always talk of equity, and forbid any kind of discrimination; not only among humans, but inter se all the living beings as well.

On top of all, scores of archeo-genetic studies based on the study of gene pools of castes reveal that the current tradition of intra-caste marriages is found to have existed only in last 60-70 generations across a span of the last twelve centuries. The genome studies indicate that the marriages were not confined with castes around 1200 years ago. The study conducted at National Institute of Biomedical Genomics (NIBMG) in West Bengal (The Hindu, Dated January 27, 2016 Bangalore - Mohit M. Rao) and several other agencies, after having studied the genes of various communities corroborate the fact that intermarrying was quite common 1200 to 2000 years back among all castes. According to Analabha Basu, assistant professor at NIBG and lead author of such a study is reported to assert that the Iyer Brahmins of southern Indian state Tamilnadu and Irula tribals of Nilgiri Hills have ancestral North Indian genes, but in varying degrees. According to this study, the ancestries mingled in India until caste based endogamy (practice of marrying within the caste) was introduced about 1600 years ago [www.scidev.net/south-asia/genomics/news/ tracing-the-indian-genome.html]. Most of the archeogenetic studies reveal that endogamy was not in vogue in India in ancient past. The time varies form 1000-2000 years. But well within the era after the Mahabharat period and lasted beyond Gupta period. Endogamy has begun only in the last 1600 years. Thus intermarriages inter se Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shoodra casters were prevalent before 1600 years. This rules out the prevalence of any birth based caste system.

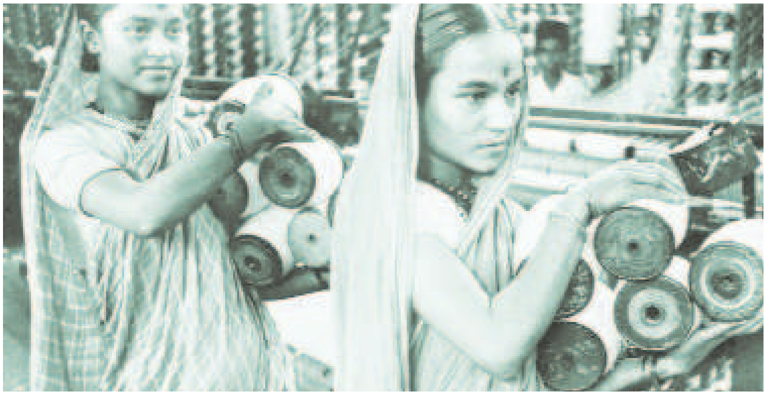

There had been no place for any ethnic or caste discrimination, social stratification of superiority-inferiority of castes in the ancient past in the country, before the advent of the 8th century. Rather, the Vedic scriptures, the Upanishads, the tenets enshrined in the epics and the sermons of Shrimad Bhagwat Gita, all instruct every individual to deal every living being with compassion, cohesiveness of divine fraternity and the way, one wants to be treated himself or herself by others. It is enshrined as "Aatmavat Sarv Bhuteshu" (आत्मवत सर्वभूतेषु) in the Upnishads and in the same way but in different words in various other major Hindu scriptures. It means every living being be treated like himself or herself. Our scriptures do not allow contempt towards any living being.

When the Indian or Hindu Philosophy asserts that the same divine Almighty is pervading across all living beings, how an individual can be untouchable or superior or inferior on the basis of his birth. Why this evil practice should have any place in our social life? All Bhartiya or the Indians the descendents of the ancient Hindu polity Hindus should behave and act as a seamless cohesive caste like true brethren and sistren. Besides, we should also revive the decentralised production of goods and services for inclusive growth, sustainable development and full employment.

Shoodras : The Producer Class of Valuable Goods

One of the common and oft-repeated allegations on Hindu traditions is that the 'Shoodras' had been treated contemptuously, alleging that 'shoodra' word has been derived from the word as 'Kshudra' (क्षुद्र) meaning mean people with menial occupations, deprived of dignity. It was not so in the ancient past. The nirukti (etymology) of the word 'shoodra' in Brahminical auxillaries of Atharv Veda speaks that Shudras are the producers of valuable goods by the sweat of their labour. The nirukti (etymology) reads as under:

Shramasya sveden
utpadan rat ev shoodrah
श्रमस्य स्वेदेन उत्पादन रत एव शूद्र

Meaning in Hindi: अपने श्रम के स्वेद (पसीने) से मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन उत्पादकीय कार्य में रत या संलग्न

वर्ग को 'शूद्र' कहा गया है।

Meaning in English : Those who produce various valuable goods by the sweat of their labour i.e. by their physical efforts are termed as shoodras

Thus, shoodras had been producer class to produce all kind of products, which can fetch a price. This means that the shoodras produced valuable products, to be traded at a price with profit by the Vaishya (oS';) who then used to pay tax to the king. In pursuance of this doctrine, the 'Kamandak Neetisaar' recommends that **while setting up a new township (नगर), the king should ensure that it is inhabited by a larger number of Shoodras, who produce valuable products, and equally large number of Vaishyas who indulge in trading and commerce of these goods, produced by Shoodras and so they pay higher amount of taxes from such a higher level of trade. This Neetisaar emphatically states that number of Brahmins and Kshatriyas should be in relatively lesser number, as they are dependent upon the state exchequer for their livelihood.** This system of production and trade had been prevalent till the invasion of the Arabs and even beyond, till the turn of the eighteenth century, when the European goods under British rule flooded to erode the Shoodras, the productive entrepreneurial-class of India, engaged in the decent production of valuable goods. So, Bharat was a very rich nation till all goods were produced indigenously by various craft guilds of shoodras.

Since, Brahmans were supposed to study and teach, and to live on beggary with mendicany who had lived an impoverished life, without collecting any personal wealth. The Kshatriyas also had to protect the society from unjust attrocities. Kshatriya means 'Kshatat rakshati iti Kshatriya' (क्षतात् रक्षति इति क्षात्रिय). Since, Shoodra Class used to produce goods to be traded at a price, had access to abundant wealth. Therefore, they had the responsibility to extend hospitality to state guests in Mahabharat era. The relevant verses of Mahabharat is quoted in the succeeding pages. Likewise, even the measuring tape of Shoodras was gold embedded in pauranik era. Citation is given in later section.

Table: 1
The position of India in the world economy since 0 AD till 18th century
GDP (PPP) in millions of dollars

Country/ Region	1	1000	1500	1600	1700
Western Europe	14,433	10,925	44,183	65,602	81,213
Eastern Europe	1,956	2,600	6,696,	9,289,	11,393
Russia	1,560	2,840	8,458	11,426	16,196
USA	272	520	800	600	527
Total Latin America	2,240	4,560	7,288	3,763	6,346
Japan	1,200	3,188	7,700	9,620	15,390
China	26,820	26,550	61,800	96,000	82,800
India	33,750	33,750	60,500	74,250	90,750
World	105,402	120,379	248,445	331,562	371,428

Our Past Riches were from the Economic Value Added by Shoodras

India had been the richest nation on the planet, with around one third contribution in the world GDP till the onset of the sixteenth century. It was from the economic value added by Shoodras as the producer of all kinds of goods, to be traded at a price. India had the system of decentralised production of various goods of value, with widest participation of the Shoodras. So, India remained the richest country of the world till the turn of 18th Century. This has been testified by Angus Madison, the renowned British Economic historian in his book, entitled 'World Economic History - A millennium perspective", published by the OECD headquarters at Brussels, capital of Belgium in Europe, wherein he has stated that India had 33 percent contribution in world GDP in 1 AD, 30% in 1000 AD, 25% in 1500 AD and 22% in 1700 AD. Europe, Russia, US, Latin America, Japan and China had not been anywhere near India in their contribution to the world GDP, till the Shoodras had been the productive entrepreneurs of ancient MSME (Micro, small and medium scale Industrial Enterprise) sector (see Table: 1).

Source : World Economic History - a millennium perspective by Angus Maddison

Collaborative Reciprocity of Castes for Decentralised Production

In fact, the ancient Indian system of production of all goods was based upon highly advanced wisdom and production technology, in diverse fields with reciprocal interdependence of the

Brahmans and Shoodras. Indeed, the scriptural descriptions, etymology of terms in niruktas or nirvachans and scriptural shlokas on production technologies have been the basis of production processes and techniques being undertaken by the Shoodras in consultation with Brahmans. Even the archeological excavations being undertaken across the country speak of well advanced production technologies. The archeological excavations undertaken at Kodumanal in Tamilnadu have revealed production of Iron & steel, textiles, gems (processing) etc 2500 years back by such reciprocal dependence of the Brahmans and Shoodras (Comprising Khaniks i.e. Miners & excavetors, Paridravaks i.e. metallurgical blasters & smelters, Luhars i.e. blacksmiths etc). The rust proof Vitrified crucibles found there, prove, India had mastered vitrification process, 2000 years back. Likewise, the evidence has come to surface about mining and production of Zinc at Zawar in Udaipur district and Copper at Khetri in Neem Ka Thana (old Jhunjhunu District) of Rajasthan about 4000-5000 years back. These production processes were a result of collaborative cooperation between the Shoodras and Brahmins. It was an integral reciprocity of scriptural intellect of Brhaminical scriptures and technology driven skills of shoodras.

A representative example of collaborative knowledge sharing and employment for production would help the readers to understand the reciprocity of Shoodras and Brahmins in technology based production

which being the key to production in the country in joint collaboration and ongoing association between Brahmans, Brahaminical scriptures and Shoodras. In this case the reciprocity of khaniks (miners) dhatukarmis (metal smelters) and kanseras (metallurgical product producers) and Bhrahmans especially gramnerians is being taken here. The niruktas give the etymology of the term yashad i.e. Zinc as 'Tamrah Yash Pradayate iti Yashadah' (ताम्रः यश प्रदायते इति यशदः). It means Zinc is one which gives credit to the copper. This word-etymology of zinc is based on metallurgical chemistry used in the production of Zinc in the ancient times in 2000-3000 B.C. by the producers of zinc at Zawar etc. Since Zinc melts at 8200C and oxidises at 910^{0}C. To prevent oxidation the khaniks and Metal Producing Shoodras are said to be covering the crucible by a Copper plate. Thus, this knowledge was codified by Brahmans and applied by Shoodras, which constituted a major basis of India's riches, as India was the only producer and exporter of Zinc in the world till the medieval period. Basically, the ancient wisdom enshrined in Indian scriptures compiled by Brahmans was applied in production technology by the Shoodras. Thereby, in the ancient times, the Shoodras, who used to produce all kinds of goods were the richest community till 700 CE. Another example to elucidate, how changing dynamics of occupations with time has led to ups and downs among the relative affluence of castes over a broad span of time. The example is of the Banjara Community.

Prosperity of Shoodras in the Ancient Past

Coming back to the past life of the Shoodras in ancient times Shoodras must have been a very rich class by virtue of their engagement in producing various goods of high value. Therefore in the Mahabharat era, the shudras had probably been so affluent people in the country to be given the responsibility for extending hospitality to the state guests.

In the Anushasan Parv of the Mahabharat, one of the major role

for Shudras has been stated to provide hospitality, including lodging and boarding to the state guests. The Shloka reads as under:

Sashoodrah sanshit tapa jitendriyah. sushrodshutrithim tapah sanchinute mahat (Mahabharat at Anushasanparv)

सशूद्रः संशिततपा जितेन्द्रियः।
सुश्रुर्तिथिं तपः संचिनुते महत्।।

(महाभारत–अनुशासन पर्व)

To corroborate this fact of hyper affluence of Shudras as MSME entrepreneurs in that era, most of the Vaastu Granth and several Puranas state that in the ancient past the measuring tape for construction of housing unit of Shudras was embedded with golden fabric. A shloka from Vishwakarma Prakash reads as under:

Brahmanasya sutra darbhajam
maanjanta ta kshtiriyasya.
karpasiam cha bhavedvaishyam
svarnirmitam shoodraya sootram.

(Vishwakarma Prakash)

ब्राह्मणस्य सूत्र दर्भजं,
मौजन्तु त क्षत्रियस्य।
कार्पासं च भवैद्वैष्ये,
स्वर्णनिर्मितं शूद्रस्य सूत्रम्।।

(विश्वकर्मा प्रकाश)

It means that the house measuring tape or the lining and sizing thread of Brahmins was of Kusha or Darbh category grass, for Kshatriya it was made of Munj category grass. For Vaishya it used to be a cotton thread and for Shudra it was a gold embedded or golden thread in that era.

Study of Vedas was well Accessible to Shoodras and Tribes :

There is lot of misgivings about the access of Vedas to Shudras, which is not true. The Yajurveda in its chapter 26 mantra 2 clearly states that Rishis to teach Veda to all the four Varnas. The mantra reads as under:

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याज्या शूद्रायचार्याय च स्वाय चारण्याय।

प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयज्मे कामः समृद्धतामुपमादो नमतु।। यजुर्वेद अ. 26 मंत्र 2

Yathemam vacham kalyanim adadami Janebhya;

Brhma rajanyabhyam Sudraya cha Aryaya ch Svya-charanaya ha priyo devanam ... (Yajuraved Ch. 26 (2))

It means that "Just as I am speaking these blessed words of Vedas to you people (rishis), you should teach these to all the men and women, the Brahminas, Kshtriyas, Vishayas. Shudras, tribes and all others irrespective of they being our own people or aliens." The words 'Shoodra' and 'Aranyay' i.e. forest dwellers are there.

Nondiscriminatory Access to sources of water and Food for All

In the ancient past, all Hindus had access to places of water and food, without any discrimination. This ancient practice of non-discrimination and uniform access to all as enshrined in the vedic hymns must have perpetuated till the early medieval period, as is evident from the Ramcharit Manas of Tulsidasji authored in 1574 CE i.e. Vikram Samvat 1631. Thus, even 442 years back when Tulsidasji composed Ramcharit Manas, he had stated that Rajghaat on the Sarayu river of Ayodhya was equally accessible for water to all the four Varnas i.e. all castes. This Choupai reads as under:

Raajghat bandheu param manohar. Tanha nimajjiu. varan chaariu nar.

(Ramcharit Manas Uttar Kaand)

राजघाट बांधेऊ परम मनोहर।
तहाँ निमज्जिउ वरण चारिउ नर।।

(रामचरित मानस उत्तर काण्ड)

Likewise, Atharva Veda also clearly directs all the people i.e. human beings, indifferent of their castes or varnas to have equal access to water and food together through its shlok 3.30.06

Samani prapa saha voannabhagha samane yoktre saha vo yunajmi

Samyachognim saparyataara naabhimivabhitah ... Atharvved 3.30.06

It means: Let the source and place of your drinking water be the same, let your food be taken together, let your yoke to be the same united like spokes of the cart wheels and you all People worship of god as a symbol of knowledge.

समानी प्रपा सहवोऽन्नभागः
समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि।
सम्यंचेःग्निं सपर्य
तारा नाभिमिकाभितः।।

अथर्व : 3.30.06

भावार्थ : तुम्हारी जल शाला एक हो, अन्न एवं भोजन भी साथ–साथ हो, एक ही जुए में तुम प्रजाजन जुड़े हुए हो। जैसे पहिये के अरे नाभि (केन्द्र) में चारों ओर जुड़े होते हैं, वैसे ही तुम सब प्रजाजन मिलकर ज्ञान रूप प्रभु की पूजा करो।

Likewise all persons should treat each other as brothers and sisters.

मा भ्राता भ्रातरम् द्विक्षन
मा स्वसर मुत स्वसा।
सम्यांचा सव्रता भूत्वा
वाचं वदत भद्राया।

ma bhrata bhrataram dwikshan ma swasara muta swasa.

Samyanchah savrata bhutva vacham vadata bhadraya.

Let not a brother hate a brother, nor a sister hate a sister;

unanimous, united in aims, speak your words with friendliness.

Thus our tradition, before the foreign invasions, which began from 8th century, had been of egalitarian and benevolent equanimity and parity to all. In this regard the most common Mantra from Upnishad reads for bliss for all, healthy life to all and emancipation from all sorrows. It reads as under:

Sarveutra sukhinah santu sarve santu niramayah. sarve bhadrani Pashyantu ma kashchid dakhbhagbhavet

सर्वेऽत्र सुखिनः
सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत।

It means "May every being be happy on the earth May every being be free from all the diseases and deprivations, May every being should give a benign response to every other being. May there not be any trace of sorrow anywhere and let the bliss prevail everywhere.

Example of Rise and Decline of Castes : The Banjara Community

With the change in time, how the modus operandi of any craft, trade, commerce or business changes and how it brings change in the wealth and well being of any group or community, can be best understood from the rise and decline of economic status of the Banjara community in India. Even, the 'Roma People' spread across the globe who have also, probably descended from the mobile commerce of Banjara community of India have suffered. It can well explain the economic rise and decline of people engaged in any craft or business. Even the Gadia Luhars (Blacksmiths moving on the carts i.e. bullock carts) of Rajasthan too had been quite affluent 5-6 decades earlier. But now with the advent of modern technology in making Iron implements, they are getting marginalised. Let us now take the example of 'Banjaras'.

The term Banjara has evolved from Sanskrit word Vanijyara (वाणिज्यारा) meaning the "one dealing in Commerce" i.e. those dealing in cross boarder trade and activities associated with trade. Banjaras had been the most affluent class in past, whose hundies had been quite popular. Till the advent of European traders, Banjaras had been very active to undertake the trade on the back of the herds of vast number of bullocks. They were hyperactive even before the advent of Arab traders. On account of their pre-dominance in understanding cross boarder trade and commerce with vast herds of bullocks and ships with up to 100 oars (called 'Shataritra in Rigved) from far east to far west, they had spread across the globe in past. The Rigved mentions for cross boarder trade through Shataritra ('Shat' means hundred and Aritra means Oars in Sanskrit language). Their trade being based, predominantly on the back of herds of bullocks. Very vast sized lakes, probably made by them for their herds of bullocks (for drinking water) are found all over from South East Asia to Europe. For instance, the lake Pichhola of Udaipur, Lake Banjari of Ajmer and so on. Their role and ancient affluence is well depicted in several folk tales and folk dances. For instance, the 'Gauri' or 'Gawari' an annual spiritual dance-drama or ballet of the Bhil tribe played for fortnight and across the 15 days based on historic evolution portrays Banjara as the richest category above the king and nagarseth. They were the mobile cross boarder traders known for trading from South - East Asia to Iran and beyond, even up to Europe and (may be even up to America) through their herds of vast number of bullocks and large boats. Today, with the advent of new era trade and commerce to which probably they could not adapt, they are now listed in the category of Scheduled castes, tribes and other backward castes in different states. No one knows, they could be part of the vaishya

community undertaking the trade and commerce since time immemorial.

Romas: The Descendants of the Banjara styled Trading Class

It would not be out of place to mention that the 11 million (1.1 crore) Roma, Romani or the Roma Gypsies (i.e. travelers) may be in all possibility the descendents of these ancient globe trotters, travelling to undertake cross boarder trade and commerce i.e. mobile-commerce. In the later age, they might have settled, wherever they were engaged in trade before the new mode of international commerce took over.

Common Gene Pool A Recent Study published in 2010 has also drawn a conclusion that Romani populations i.e. Romas have a high frequency of a particular Y chromosome and mitochondrial DNA that are only found in populations from South Asia. So it may now be well accepted that the Roma people must have migrated to Europe from North India about 1,500 years ago as travelling traders. Broad groups of all such people, settled across the globe are collectively classified as "Roma" or "Roma Gypsy". Throughout the Europe and the US, the Romani people comprise ethnic groups who are spread out all over the world, having common ties and traits. These groups of Roma are referred to as Romanichals in England, Beyash in Croatia, the Kale of Wales and Finland, Romanlar in Turkey and Domari in the Palestine and Egypt. As per the age-old convention, necessitated by the nature of their occupation, the Romanis were continuously on the move to cross border trade conduct with a nomadic lifestyle and a highly insular culture. Because of their outsider status across the globe at most of the places and migratory nature for cross-boarder trade across the globe, few used to attend school and consequently in the later age literacy was not widespread among them. Much of what is known about their culture has come through stories told by singers and oral histories which are replete with Indian legendary tales.

Need to Restore Ancient Equanimity or and Decentralised Production

Now, to restore the same equanimity, samarasata (समरसता) and divinity of every soul, as preached by our ancient scriptures, there should be perfect equality in our behaviour towards each other as true brethren and sistren. India is home to one sixth of global humanity and an ancient nation, and rather with ever-perpetuating nation-hood since time immemorial, where every living being is seen as the divine manifestation of the Almighty. The caste stratification and discrimination as a transient evil should have no place, when we have done away with the untouchability. In light of this now there should be no caste discrimination in any form and all Bhartiya citizens should behave with each other with total egalitarian equanimity and parity, to build a strong and Samras Bharat, based upon casteless and a cohesive cooperation. When the Indian or Hindu Philosophy asserts that the same divine Almighty is pervading across all living beings, how an individual can be untouchable or superior or inferior on the basis of his birth. Why this evil practice should have any place in our social life? All Bhartiya or the Indians the descendents of the ancient Hindu polity Hindus should behave and act as a seamless cohesive caste like true brethren and sistren. Besides, we should also revive the decentralised production of goods and services for inclusive growth, sustainable development and full employment. ❑

National Education Policy 2020 Owing to 'Unnat Bharat'

Dr. Anil Kumar Biswas

Associate Professor, Department of Political Science,The University of Burdwan,West Bengal

Article 1(1) of the Constitution of India mentions that India, that is Bharat, shall be a Union of States. The term 'Bharat' is derived from the name of the king Bharata, the son of Dushyanta and Shakuntala. The present Bharat is known as 'Bharatvarsa' in the Mahabharata period. The term 'Bharat' signifies because it comes from the name of the then king Bharata and 'Varsa' means a division of the continent. The term 'unnat 'is synonymous with the English term Developed. The terms developed or 'unnat' have their inner meaning. The term developed bears the essence of Western culture and the term popularized in the West since the Industrial Revolution. The term bearing a colonial legacy and economic parameter is the core theme of it. On the other hand the term 'unnat' is an Indigenous concept different from the Western concept of development. The term development is used differently in diverse contexts. Simply the term development means unfolding, revealing something; which is latent. Generally, the term development implies a desirable change. However Western scholars used the term from the viewpoint of economic parameters. They wanted to measure the development of a region, the development of a community, development of a nation from the viewpoint of economic indicators. But the term 'unnat' is used by Indian culture not only to measure something from the viewpoint of the economy; Indian culture and tradition are given due importance to other indicators along with the economy. Traditionally India, that is Bharat gives due importance to tolerance, resilience, customs, traditional laws, spiritual spirits, indigenous practices, and harmony. The Indian concept 'unnat' means, it makes an individual a complete human being for the demands of society. The Indian concept 'unnat' aims to make a spiritually liberated human being based on the Indian richest Culture and Philosophy; those who are not only ready for their nation; they are ready for the

whole world. Bharat targeted that she will reach the peak of 'Unnati' (development) by 2047. For the fulfillment of the aims, the government of India introduced a National Education Policy in 2020 seeking to reach the goal within the stipulated timeframe.

National Education Policy 2020

Education is a basic human right. Education turns an individual into a good citizen; which means education trains individuals for harmonious relationships with the other members of the community and society. Education also allows an individual to build a strong and healthy body; which helps him or her in building up his or her character and attaining self-reliance; making the capability of individual to act properly with others and overall environment. In short, education transforms human beings from ignorance to enlightenment, from underdevelopment to faster economic and social development. According to Swami Vivekananda, 'education is the manifestation of perfection already in man'. According to Rabindranath Tagore, 'knowledge is liberation. The spiritually liberated man is the aim of Indian education'. According to Shri Aurobindo, 'the great purpose of education is to help the soul to come forward, to assert its mastery over its instruments, gain experience and grow, and eventually manifest the powers it has to outline in life' (Sri Aurobindo Ashram Trust). All Nobel thinkers from ancient times to contemporary have given importance to character building, self-dependency, harmony, tolerance, resilience, and spiritual liberation through education along with the modern need to use technologies for increasing employability. For the fulfillment of the aims, a National Education Policy is started to implement in 2020 with new visions along with previous.

If the policy is implemented properly across the country desirable change may come; which leads the nation to 'Unnat Bharat' (developed India). Under the combination of indigenous knowledge of India along with present super technological innovation Artificial Intelligence (AI) may make the present Bharat an 'Unnat Bharat' (developed India) and will be able to make herself a super powerhouse of trained quality human resources as per global demand of 21st century; which may lead Bharat to 'Viswa Guru'.

The draft of education policy was drafted by the Kasturirangan Committee; which was set up in 2017. The committee drafted the policy giving due importance to the foundational pillars of education like access, equity, quality, affordability, and accountability. National Education Policy 2020 come into force aims to address the many growing developmental issues for the demand of the 21st century. The policy aims to achieve SDG4 by 2030 and make India an 'Unnat' Bharat' by 2047. For fulfillment of the dream, the policy framed a few valuable principles

that education develops the cognitive capacities of the learners in every stage along with social, ethical, and emotional capacities including cultural awareness and empathy, teamwork and leadership, service and sacrifice, courtesy and sensitivity, oraland written communication, integrity and work ethic.

How National Education Policy 2020 Owing to 'Unnat Bharat'

The vision of the National Education Policy 2020 is to build up an education system based on the Indian spirit that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high-quality education to all, thereby making India a global knowledge superpower (Ministry of Human Resource Development). For fulfillment of the vision of the act, the act gives priority to

- The holistic development of the learners for building unique capabilities in the overall sphere of development;
- There is a choice of freedom of learners in the policy;
- There is no hard separation between sciences and arts, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams;
- Emphasis is given on conceptual understanding rather than rote learning;
- Stresses given on the multidisciplinary nature of education;
- Emphasis is given on critical thinking to encourage logical decision-making and innovation;
- The policy has emphasized ethics, human values, and constitutional values;
- Life skill education is one of the important aims of NEP;
- There is scope for extensive use of technology in education;
- The policy has provision to use the Artificial Intelligence (AI) in education;

- The policy focuses on the local context to respect the spirit of federalism;
- The policy is inclusive and equitable;
- Teachers and faculties are the core pillars of education;
- The policy says the importance of research.

Under these principles, the present Education Policy 2020 is different from previous education policies since independence. There are provisions in the policy to make a bridge between Indian indigenous knowledge with super modernism. The policy can make a bridge between Indian indigenous ethos and contemporary modern demands of the society.However, there is a need to give priority importance to the implementation of the policy with proper infrastructure and financial support from the side of government and other philanthropic agencies. If the policy is implemented properly across the country desirable change may come; which leads the nation to 'Unnat Bharat' (developed India). Under the combination of indigenous knowledge of India along with present super technological innovation Artificial Intelligence (AI) may make the present Bharat an 'Unnat Bharat' (developed India) and will be able to make herself a super powerhouse of trained quality human resources as per global demand of 21st century; which may lead Bharat to 'Viswa Guru'. ❑

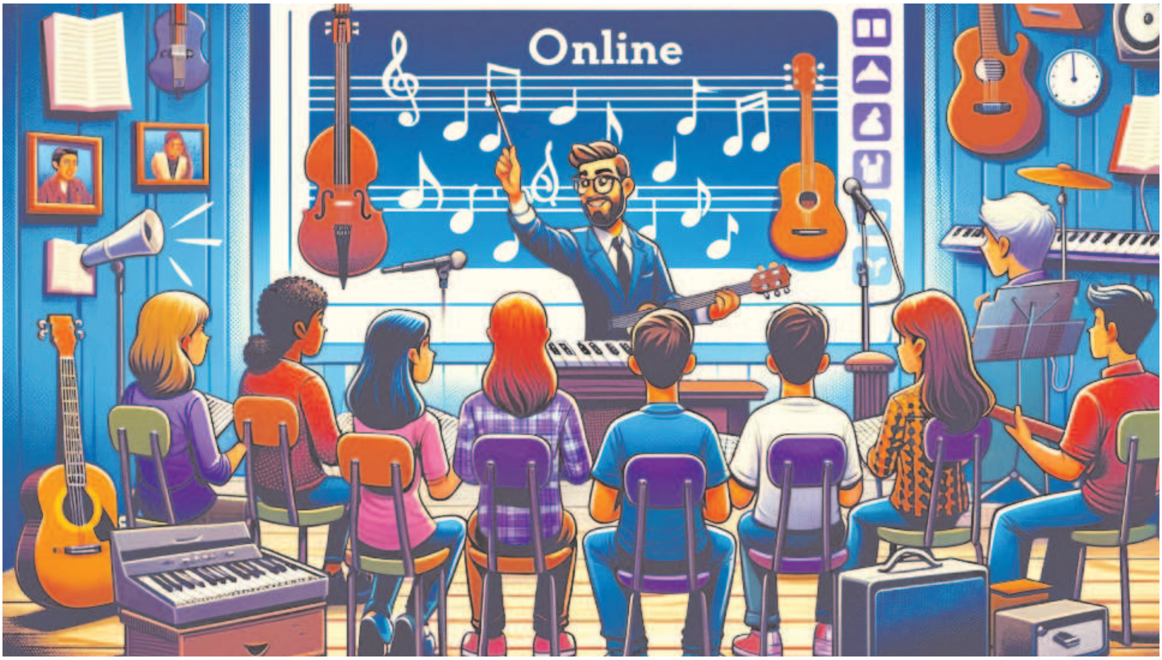

Harmonizing Education and Development : NEP 2020 and UBA's Vision for Rural India

Prof. Prakash Chandra Agarwal

Principal
Regional Institute of
Education, Bhubaneswar

India, with her diverse population and vast potential, stands on the cusp of transformation. The National Education Policy (NEP) 2020 and the Unnat Bharat Abhiyan (UBA) represent pivotal steps in this journey towards progress. NEP 2020, unveiled after a gap of over three decades, seeks to revolutionize the education system, aligning it with the needs of the 21st century. On the other hand, UBA aims to foster rural development by leveraging the knowledge and resources of academic institutions. The initiatives collectively embody India's commitment to inclusive growth and sustainable development. NEP 2020's emphasis on holistic education and skill development complements UBA's goal of addressing the socio-economic challenges faced by rural communities. By bridging the gap between urban and rural areas, these initiatives aim to create a more equitable and prosperous society. Through collaborative efforts between educational institutions, government agencies, and local communities, NEP 2020 and UBA pave the way for a transformative journey towards a progressive India. This synergy between education reform and rural development underscores India's determination to build a future where every individual has the opportunity to thrive and contribute to the nation's advancement.

NEP 2020: Transforming Education for Sustainable Development

1. **Holistic Development :** NEP 2020 emphasizes the holistic development of learners, recognizing the importance of cognitive, social, emotional, and physical development. It advocates for an education system that goes beyond academic excellence to include all curricular activities, vocational skills, and values-based education. This holistic approach aims to nurture well-rounded individuals capable of navigating the complexities of modern society.

2. **Flexibility :** NEP 2020

introduces a flexible curriculum framework that allows students to choose from a wide range of subjects and pathways based on their interests, aptitudes, and career aspirations. It promotes multidisciplinary learning, enabling students to explore diverse fields and develop a broad understanding of the world.

3. Inclusivity : NEP 2020 emphasizes inclusivity and equitable access to quality education for all learners, regardless of their socio-economic background, gender, ethnicity, or disability. It seeks to address disparities in educational outcomes by providing support mechanisms, scholarships, and other interventions to marginalized communities.

4. Promotion of Multilingualism : NEP 2020 recognizes the importance of multilingualism in a diverse country like India. It advocates for the promotion of mother tongue or regional language as the medium of instruction until at least Grade 5 but preferably grade 8 and beyond, while also encouraging the study of other languages, including classical languages and foreign languages. This approach aims to preserve linguistic diversity and promote cultural understanding.

5. Integration of Vocational Education : NEP 2020 emphasizes the integration of vocational education into mainstream schooling from an early age. It seeks to equip students with practical skills and competencies relevant to the rapidly evolving job market, thereby enhancing employability and promoting entrepreneurship.

The combination of NEP 2020 and UBA has huge potential to speed up positive and peaceful development in India's rural areas. By matching changes in education with direct actions in villages, can give power to rural communities, encourage new ideas, and support growth that includes everyone. As India works towards lasting progress, NEP 2020 and UBA shine as guides, showing a path where education sparks good things in every corner of the country.

6. Emphasis on Experiential Learning : NEP 2020 promotes experiential learning approaches such as project-based learning, internships, and apprenticeships to provide students with real-world exposure and hands-on experience. This pedagogical shift aims to foster creativity, critical thinking, problem-solving skills, and innovation among learners.

7. Environmental Consciousness and Sustainable Development : NEP 2020 underscores the importance of environmental consciousness and sustainability in education. It advocates for the integration of environmental education, climate change studies, and sustainable development goals across the curriculum to raise awareness and empower students to become responsible global citizens.

UBA : Empowering Rural Communities through Knowledge Sharing and Participatory Development

Unnat Bharat Abhiyan (UBA) stands as a crucial initiative, born from a profound understanding of the disparity between academic knowledge and rural development needs, deeply rooted in the principles championed by Mahatma Gandhi – self-reliance and community empowerment. It serves as a bridge, connecting the vast reserves of expertise within educational institutions with the pressing challenges confronting rural communities.

At its core, UBA is guided by a profound ethos : the empowerment of rural communities through a collaborative effort that respects local wisdom and integrates modern advancements. Drawing inspiration from Mahatma Gandhi's vision, UBA envisions a landscape where villages are self-sufficient and resilient, capable of addressing their own needs through sustainable practices and empowered decision-making.

The essence of UBA lies in its approach – one that is participatory, inclusive, and mindful of local context. Rather than imposing solutions from above, UBA mobilizes the collective knowledge and resources of educational institutions, local stakeholders, and governmental bodies to co-create interventions tailored to the specific challenges faced by rural communities. This approach ensures that solutions are not only effective but also sustainable, as

they are rooted in the realities and aspirations of the people they seek to serve.

Eco-friendly technologies serve as the cornerstone of UBA's interventions, reflecting a commitment to environmental stewardship and long-term sustainability. By harnessing the power of innovation and scientific advancements, UBA endeavours to address pressing issues such as access to clean water, renewable energy, and efficient agricultural practices. Through the deployment of these technologies, rural communities are empowered to improve their quality of life while minimizing their ecological footprint.

However, UBA is more than just a vehicle for technological innovation – it is a platform for knowledge sharing, capacity building, and collective action. By fostering collaborations between academia, government, and grassroots organizations, UBA creates opportunities for mutual learning and growth. Through workshops, seminars, and field visits, stakeholders come together to exchange ideas, share best practices, and co-design solutions that transcend disciplinary boundaries and bureaucratic silos.

In essence, UBA embodies the spirit of convergence – of knowledge, resources, and stakeholders – towards a shared vision of sustainable rural development. It is a testament to the power of collaboration and community-driven change, reminding us that the path to progress lies not in isolation but in solidarity. As UBA continues to expand its reach and impact, it holds the promise of a future where every village is empowered to realize its full potential, guided by the principles of self-reliance, equity, and sustainability.

Synergies between NEP 2020 and UBA: Towards Holistic Rural Empowerment

The blending of the National Education Policy 2020 (NEP 2020) with Unnat Bharat Abhiyan (UBA) marks a significant moment, ready to bring together educational changes with actions directly in villages, all to empower rural areas fully. This combined effort, rooted in a shared dedication to community-focused growth, holds the promise of creating deep connections that go beyond typical boundaries.

At the heart of this collaboration lies the unity of educational goals with the hopes and struggles of rural areas. NEP 2020's focus on complete growth, accessible education, and learning through experience fits perfectly with UBA's belief in involving communities and staying true to their needs. By basing educational efforts on the everyday experiences of rural living, this joint effort ensures that learning connects with students, helping them understand their surroundings better and develop empathy, critical thinking, and problem-solving abilities.

Moreover, NEP 2020's emphasis on vocational education and skill development finds resonance in UBA's commitment to empowering rural youth with practical competencies and employability skills. By integrating vocational training into the curriculum and promoting hands-on learning experiences, students are not only equipped with market-relevant skills but also inspired to contribute meaningfully to local development initiatives. This symbiotic relationship between education and rural empowerment cultivates a cadre of socially conscious, skilled professionals who are proficient at addressing the multifaceted challenges facing rural communities.

Furthermore, the collaborative nature of NEP 2020-UBA integration fosters the co-creation of knowledge, solutions, and opportunities. Educational

institutions, government agencies, NGOs, and local communities converge to exchange ideas, share best practices, and co-design interventions that address the unique needs and aspirations of rural India. By establishing a sense of empowerment and ownership among stakeholders, this participatory approach not only guarantees the relevance and efficacy of initiatives but also serves as a catalyst for sustained, community-driven development.

The synergy between UBA and NEP 2020 essentially signifies a fundamental change in development and education frameworks, where education acts as a catalyst for comprehensive rural empowerment. Through the utilization of education's transformative power that promotes empathy, skills, and agency in students, as well as the pooling of resources and collective wisdom from a wide range of stakeholders, this integrated approach sets the stage for a future in which every rural community is enabled to reach its maximum potential while living in harmony with its cultural, social, and environmental surroundings.

Leveraging Technology and Innovation for Rural Development

Technology serves as a powerful enabler in transforming rural landscapes, offering scalable and sustainable solutions to complex challenges. Through the integration of digital platforms and innovative applications, NEP 2020 and UBA can facilitate access to essential services such as telemedicine, e-learning, and agricultural extension services, bridging the gap between rural communities and critical resources. Renewable energy solutions, such as solar power and biogas, hold immense potential in addressing energy poverty and promoting environmental sustainability in rural areas. By harnessing these clean energy sources, NEP 2020 and UBA can mitigate reliance on fossil fuels, reduce carbon emissions, and enhance energy access for underserved populations, thereby fostering inclusive and resilient rural economies.

Furthermore, the cultivation of digital literacy and entrepreneurship skills among rural youth empowers them to leverage technology as a tool for socio-economic empowerment. By providing training in digital skills, financial literacy, and business management, NEP 2020 and UBA equip young people with the knowledge and resources to innovate, create employment opportunities, and drive local economic growth, thereby fostering a culture of innovation and entrepreneurship in rural communities.

Empowering Local Communities and Fostering Inclusive Governance

At the heart of NEP 2020 and UBA is the empowerment of local communities and the promotion of inclusive governance structures. By decentralizing decision-making processes and promoting community participation, this integrated approach can ensure that development initiatives are contextually relevant and sustainable. Furthermore, by nurturing leadership skills and civic engagement among students, NEP 2020 and UBA can cultivate a new generation of changemakers committed to advancing the common good.

The combination of NEP 2020 and UBA has huge potential to speed up positive and peaceful development in India's rural areas. By matching changes in education with direct actions in villages, can give power to rural communities, encourage new ideas, and support growth that includes everyone. As India works towards lasting progress, NEP 2020 and UBA shine as guides, showing a path where education sparks good things in every corner of the country. ❑

The New and Emerging Bharat

Prof. TS Girish Kumar

Retd.
MSU, Vadodara

In the past ten years of time, Bharat had been experiencing such changes as are indeed a dream come true phenomenon. We all had been looking at these and experiencing them as well,and knew very well how things were working. With this ten years of experience at our hand, we shall know that the Nation is constantly becoming new, evolving and emerging.

The real strength of a Nation

We see our Nation emerging as a very strong and powerful one and had been finding how different the attitude of other nations was shifting focuses in our favor. The world started not only hearing us, but also listening to us. This, precisely is because of the reason that our Nation is slowly becoming formidable and more meaningful.

Now, what shall constitute the strength of any nation? Prima facie, people shall be tending to think in the Marxist perspectives at once, that economic strength of nation becomes the sub-structure, where economic strength as the sub-structure determines all other super-structures; and Bharat is moving towards becoming the third richest Nation in the entire world. This is actually very true, once one is economically strong, one gets a position and has a right to one's say in any situations. Many people are of the opinion that once the Nation is economically strong, all other things shall automatically follow as a natural phenomenon, which also has its point. Still, one may venture to think, is economic sub-structure (given Marxist structuralism) the real strength of any nation? In such cases, with the withering away of economic sub-structure as a strong one, the real strength of the nation also shall automatically wither away, which shall be an unfortunate

Bharat does not have vested interests, our only interests are vested in our Nation as Pujaniya Guruji taught us – Rashtraya Swaha… With the natural strength of Bharat from inherent unity, the economic and other strength are only to spontaneously follow. Bharat is a Nation that never attacked anyone other than through defending,in the history of our Nation. Bharat never interferes in matters of other nations, never poses any kind of threat to anyone and in time, the world shall trust Bharat and shall start listening to Bharat, which shall indeed go a long way making Bharat Viswaguru.

situation. Nonetheless, we did witness such happening in the world in many forms also. Hence, the real strength of any nation ought not to be simple economic strength, but something else.

Strength of Bharat

Bharat the Nation has a way of being unique in many aspects. The unity of Bharat also is different from the common perceptions of unity per say. Bharat is a Nation which is united through a Sanskriti, a Sanskriti that is an outward manifestation of a knowledge tradition, which is the Vedopanishadic knowledge tradition.

For Bharat, the entire human existence is between just two points, that is, everything belongs to the Vedas and everything is aimed at Moksha. Everything is essentially rooted in the Vedas and the end desideratum of everything is Moksha. Whatever one does and one is, is finally aimed at Moksha and whatever one is, is originating from the Vedas.

It is also the same case with the strength of the Nation Bharat. The strength of Bharat comes from the unity of Bharat. We find this expression in nowhere other than the Rg Veda, where the last Sukta of the tenth Mandala which is also the last Mandala explicitly instructs this. (one can look up for the last Sukta of the last Mandala of the Rg Veda for better explanations). It simply says that once you stand united, you shall simply be strong and shall only move from strength to strength.

The real strength of any nation

Such strength as the Rg Veda envisages becomes the real strength that shall be everlasting. One may have many setbacks given changes in time and situations, but in the long run, the strength of such nation shall ever remain formidable.

Bharat herself is the best example to this. There were times when Bharat was the richest, having knowledge in every aspects of human knowing and the Viswaguru. Then there took place invasions and Bharat went to poverty with the British colonial times. After the British, the British agents ruled us for all these years and now, with such changes, Bharat again is becoming Viswaguru.

Precisely, this exactly is what the new and emerging Bharat is becoming. As a matter of fact, this is nothing new for Bharat as a phenomenon, this simply shall be natural and has to be. The real strength of Bharat is her unity and the real unity of Bharat is made possible for Bharat through the Sanskriti of Bharat which is nothing but an outward manifestation of Bharatiya knowledge tradition, which is again is the Vedopanishadic knowledge tradition.

Emerging new Bharat

Automatically, the emerging new Bharat has to be a Dharmic Bharat. There shall only be conflicts between Dharma and Adharma. This indeed, shall go on – especially by looking at the kinds of blatant lies the opposition keep creating, one is tending to feel so. There are lies spread upon castes, there are lies spread to threaten castes, and most unfortunately, there are even several lies spread regarding our armed forces. One has to keep observing these and keep fighting them.

At the same time, the Nation Bharat shall be making unprecedented progress and indeed, in time, Bharat shall also see other nations trusting Bharat. Bharat does not have vested interests, our only interests are vested in our Nation as Pujaniya Guruji taught us – Rashtraya Swaha… With the natural strength of Bharat from inherent unity, the economic and other strength are only to spontaneously follow.

Bharat is a Nation that never attacked anyone other than through defending,in the history of our Nation. Bharat never interferes in matters of other nations, never poses any kind of threat to anyone and in time, the world shall trust Bharat and shall start listening to Bharat, which shall indeed go a long way making Bharat Viswaguru. ❑

तुम फिर से दिल पर राज करो...

विनीत चौहान
प्रख्यात कवि,
अलवर (राजस्थान)

बस कुछ दिन धीरज और धरो छंट जायेगा कोहरा सारा।
सूरज की रक्तिम किरणें ही फिर से चीरेंगी अंधियारा।।

उठ चलो प्रतिज्ञा बद्ध भीष्म, ले गंगा का आशीर्वाद।
धरती से लेकर अम्बर तक धुल जायेगा सारा विषाद।।

तुम फिर से दीप जला डालो बुझती सारी आशाओं के।
तुम शीश कुचल डालो फिर से बाधाओं की भाषाओं के।।

दुश्मन को पछतावे के क्षण देने में मान तुम्हारा है।
तुम फिर से दिल पर राज करो ये हिंदुस्तान तुम्हारा है।।

इस भारत माँ ने डाल दिये सब कष्ट तुम्हारी झोली में।
इस जनता ने भी सजा दिए अक्षत माथे की रोली में ।।

अब तुम पर निर्भर है, उसके माथे की कैसे पीर हरो।
जो वादे किये देश भर से उन सबको कैसे पूर्ण करो।।

यह साठ बरस की पीड़ा है, पल भर में दूर नहीं होगी।
इसमें अपनों के छलबल हैं, यह यों काफूर नहीं होगी।।

सामने समस्या है कठोर, निर्भर जिसका हल तुम पर है।
भारत की लाज बचाने का, जिम्मा अब केवल तुम पर है।।

याद रखो तुम भारत माँ की एक मात्र अभिलाषा हो।
टूट चुके इस जन गण मन की, तुम ही अन्तिम आशा हो।।

तुम भी अगर नहीं गरजे तो कौन घाव सहलायेगा।
अश्रु बहाती भारत माँ को धीरज कौन बँधायेगा।।

लंक दहन की आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम्हीं तो हो
हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम्हीं तो हो।।

ये बजरंगी जोश तुम्हारा अभी न्यून ना हो पाये।
उम्मीदों का ज्वार जगा जो कहीं शान्त ना हो जाये।।

उठो नये हनुमान तुम्हें ही नव सागर को लँघना है।
लंका में जो सिया कैद, उसके कष्टों को हरना है।।

ज्यों घनी प्रतीक्षा बाद कोई बदली पानी बरसाती है।
बरसों धरती जब तप करती तुम जैसा बेटा पाती है।।

जो खड़ी समस्याएँ समक्ष, उन सब को सीधे हल देदो।
वरदानों के बदले जनता को, अनुदानों के फल देदो।।

उठ कर के बांहों में भर लो सारा आकाश तुम्हारा है।
तुम भारत को गरिमा दोगे अब भी विश्वास हमारा है।।

हमारा विद्यालय – हमारा तीर्थ

देवकृष्ण व्यास
देवास उज्जैन (म.प्र.)

मानव में देवत्व जगाएँ, आओ मिलकर जतन करें।
तीर्थ बने विद्यालय अपना, पुण्य पंथ पर गमन करें।।

मानव है इस सकल सृष्टि में,
अद्‌भुत कृति विधाता की।
मन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा,
कर दें भारत माता की।
विश्व गुरु के श्री चरणों में,
श्रद्धा से सब नमन करें।
तीर्थ बने विद्यालय अपना,
पुण्य पंथ पर गमन करें।। 1।।

विद्यालय मंदिर है अपना,
एक अनोखा धाम बने।
हर बाला सीता बन जाए,
बच्चा–बच्चा राम बने।
मातृभूमि को पूजें निशदिन,
मुट्ठी में जो गगन भरें।
तीर्थ बने विद्यालय अपना,
पुण्य पंथ पर गमन करें।। 2।।

सुन्दर–सा परिसर हो जिसका,
कक्षाएँ मन भावन हों।
खेल रहे हो कृष्ण–कन्हैया,
विद्यालय वृन्दावन हो।
गीता जैसा ज्ञान जहाँ हो,
मोह पार्थ का शमन करें।
तीर्थ बने विद्यालय अपना,
पुण्य पन्थ पर गमन करें।।3।।

खूब सजाएँ विद्यालय को,
ऐसा हम श्रृंगार करें।
जहाँ विराजे सदा शारदा,
वीणा की झंकार भरें।
ज्ञान दीप से करें आरती,
अंधकार का दमन करें।
तीर्थ बने विद्यालय अपना,
पुण्य पंथ पर गमन करें।। 4।।

शैक्षिक मंथन (मासिक)
प्रकाशन तिथि : 1 जुलाई 2024
प्रेषण दिनांक : 7 जुलाई 2024, सी.एस.ओ. गाँधीनगर, जयपुर
पंजीयन क्र. : आर.एन.आई. राजबिल/2008/26080
डाक पंजीयन क्र. : आई.आर./जयपुर सिटी/434/2024-26

कृपया अवितरित होने पर लौटायें :
प्रकाशकीय कार्यालय
शैक्षिक मंथन
82, पटेल कॉलोनी,
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर - 302 001

प्रकाशक, मुद्रक - महेन्द्र कपूर, स्वत्वाधिकारी शैक्षिक मंथन संस्थान द्वारा प्रीमियर प्रिंटिंग प्रेस, प्लॉट नं. 12, रामनगर, सोडाला, जयपुर से मुद्रित।
सम्पादक - डॉ. शिवशरण कौशिक